



01/2012



सीरिया और खाड़ी में विकसित राजनीतिक-रणनीतिक

गतिशीलता

जाकिर हुसैन

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़,

नई दिल्ली-110001

सीरिया और खाड़ी में विकसित राजनीतिक-रणनीतिक
गतिशीलता

जाकिर हुसैन

सीरिया और खाड़ी में विकसित राजनीतिक-रणनीतिक गतिशीलता

प्रथम प्रकाशित, 20123

काँपीराइट © अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय

परिषद ISBN : 978-81-926825-3-2

सभी अधिकार संरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी भाग को काँपीराइट मालिक से अनुमति के बगैर पुनरुत्पादित, पुनःप्राप्ति प्रणाली में भंडारित, अथवा किसी भी प्ररूप में चाहे इलैक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोकाँपी से रिकार्डिंग अथवा अन्यथा, रूपांतरित नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकाशन में व्यक्त किये गये तथ्य एवं मतों की जिम्मेदारी पूर्णतया लेखक के पास सुरक्षित है तथा उसका विवेचन आवश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के

विचारों को व्यक्त नहीं करती है।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय

परिषद्

समूह हाउस, बाराखंभा रोड, नई

दिल्ली- 110 001, भारत

Tel. : +91-11-23317242, Fax: +91-11-23322710

www.icwa.in

के द्वारा प्रकाशित

अल्फा ग्राफिक्स

6A/1, गंगा चैम्बर्स, डब्ल्यू. ई.

ए., करोल बाग, नई दिल्ली-

110005 Tel. :

9312430311

ई-मेल : tarunberi2000@gmail.com

विषयवस्तु

1. ऐतिहासिक अनुरूपताएं 6
2. जीसीसी ब्लॉक का सैन्यीकरण - अविश्वास का निर्माण 7
3. खाड़ी युद्ध और नए क्षेत्रीय सामरिक समीकरण 25
4. खाड़ी में नए भू-आकृतिक समीकरण 32
5. ईरान: मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अनुचित संबंधों से लाभ प्राप्त करना 33
6. सीरिया: खाड़ी क्षेत्र की राजनीति शक्ति का केंद्र 36
7. सीरिया का नुकसान ईरान को कैसे प्रभावित करेगा 37
8. क्रिस्टल बाल पर टकटकी 42
9. परिदृश्य I:

मुख्य-परिधि परिकल्पना:	43
खाड़ी सुरक्षा मंच का विकास (जीएसएफ)	
10. परिदृश्य II:	
संयुक्त राज्य अमेरिका: मिडिल ईस्ट में एक जबरदस्त घुमाव	47
कूटनीति - कट्टरपंथियों को सहायता	
11. परिदृश्य III:	
सीरिया का नकाबी प्रभाव व ईरान के लिए संभावित	
परिस्थितियां	55
12. परिदृश्य IV:	
इजराइल: अन्य बातों के अधीन एक मुख्य स्रोत	57

13. परिदृश्य V:

अरब क्षेत्र में सम्प्रदाय विभाजन कितना वास्तविक और
स्थायी है

62

14. शिया-सुन्नी मतभेदों के बढ़ने पर क्षेत्र और विश्व के लिए

विवक्षा

64

15. ईरान के समक्ष विकल्प: समय हाथ से निकलता जा रहा है 66

16. विषयगत मुद्दे: ऊर्जा बाजार पर संभावित प्रभाव 70

17. निष्कर्ष 74

18. समाप्ति टिप्पणी 84

सीरिया और खाड़ी में विकसित राजनीतिक-रणनीतिक

गतिशीलता

सीरियाई अरब गणतंत्र में चल रहे वर्तमान विवाद को आमतौर पर अरब जागृति में अरब के खाड़ी क्षेत्र में विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, विशेषरूप से लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए लोकप्रिय समर्थन से प्रज्वलित तथा लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक और शासन के मुद्दों को हल करने के रूप में। हालांकि , इसकी जड़ें दो प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों यथा सऊदी अरब गणराज्य तथा ईरान इस्लामिक गणतंत्र के बीच लंबे समय तक चलने वाली भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक अस्वस्थता में अंतर्निहित हैं। शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब के बीच इस्लामी दुनिया पर हावी होने की इच्छा के बीच इराक में बैथिस्ट शासन के पतन के एक रणनीतिक प्रतिरोध ने प्राधान्य की डरावनी दौड़ को फिर से जीवित कर दिया है। अरब में चल रहे माहौल ने उनको उनके पुराने

विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस पूरी खाड़ी की गतिशीलता में, जातीय-संप्रदाय के उपकरण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुप्यायित रहे हैं। इस समय इस लेखक के दृष्टिकोण के अनुसार, ईरान लक्ष्य है ; सीरिया धनुष और बाण है ; तथा जीसीस सदस्य देश, तुर्की और लाल समुद्र के आस-पास के देश धनुर्धर हैं।

अरब गतिशीलता को विभिन्न रणनीतिक प्रिज्मों के माध्यम से देखा जाता रहा है। लेकिन क्या इसमें कुछ अन्य विवाद भी हैं अथवा क्या यह निहित पश्चिमी हितों से प्रेरित है ? क्या वर्तमान सीरियाई शासन के खिलाफ आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन है या यह इसके खिलाफ हमले शुरू करने के लिए मात्र एक बहाना है ? क्या यह मात्र मीडिया संचालित प्रज्वलन है ? अथवा यह पश्चिम द्वारा क्षेत्र के ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण की ओर एक कदम मात्र है? यह लेख इन मुद्दों को वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों तथा जातीय संघर्ष के ऐतिहासिक विवरणों के आलोक में, क्षेत्र में प्रजातांत्रित व्यवस्था में शिया गतिशीलता तक ले जाते हुए विमर्शित करता है। यह लेख भविष्य का परिदृश्य भी निर्माण करता है और यह भी बताता है कि इनका समाधान कैसे किया जा सकता है अथवा क्षेत्रीय और मुख्य शक्तियों के द्वारा इनको कैसे प्रबंधित किया जा सकता है।

ऐतिहासिक अनुरूपताएं

इराक में बैथिस्ट शासन के अंत ने जातीय-बहुमत वाले शिया समुदाय पर सदियों पुराने जातीय-अल्पसंख्यक सुन्नियों के शासन को समाप्त कर दिया। इससे पहले , सलाम-बहुल सुन्नी अरब शासन ने सद्दाम का शांतिपूर्वक समर्थन किया और शिया ईरान के साथ अपने आठ साल (सितंबर 1980 से अगस्त 1988) लंबे युद्ध का सक्रिय रूप से समर्थन किया।

ईरानी क्रांति और इराक-ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि में , मार्च 1981 में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) का गठन उप-क्षेत्रीय ब्लॉक के रूप में बाहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सउदी अरब तथा यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) को शामिल करने के लिए किया गया तथा ईराक व ईरान को इससे बाहर रखा गया। जीसीसी का गुप्त एजेंडा सामिहक रूप से अपने सदस्य देशों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना था। पश्चिमी देशों द्वारा इस ब्लाक का समर्थन किया गया था।

इससे पहले, ईरान के शाह के पतन के साथ अमेरिका ने इस

क्षेत्र में अपने एक विश्वसनीय सहयोगी को खो दिया। राष्ट्रपति निक्सन ने ईरान को सोवियत नौसैनिक शक्ति के साथ-साथ ईरान की तेल संपदा पर गर्म पानी के बंदरगाहों पर सोवियत संघ के संभावित डिजाइनों के खिलाफ एक शीत-युद्ध पोतभीत माना। बहुआयामी अमेरिका-विरोधी ताकतों तथा यूएसएसआर द्वारा अफगानिस्तान के 1979 के व्यवसाय से ईरान की क्षति के बाद खाड़ी सुरक्षा पर अमेरिका की नीति “न्यूनतम” से “महत्वपूर्ण” में परिवर्तित हो गई।

कार्टर कूटनीति ने जनवरी 1980 में घोषित किया कि “खाड़ी क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए बाहरी शक्ति के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण हितों पर हमला माना जाएगा”। तदनुसार, खाड़ी के तेल राजतंत्रों की कोई भी पहल अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए जिनके महत्वपूर्ण हित इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक स्वागत योग्य कदम है। खाड़ी राजतंत्रों की रक्षा क्षमता का निर्माण अमेरिकी विदेश नीति की सर्वोपरि अनिवार्यता बन गई।

जीसीसी ब्लॉक का सैन्यीकरण - अविश्वास का निर्माण

किसी समय अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों ने दक्षिणी खाड़ी के देशों को “अरब खाड़ी के नाटो” में बदलने की कल्पना की थी। जीसीसी देशों ने भी प्रायद्वीपीय शील्ड फोर्स (पीएसएफ) (दीरा *‘अल जज़ीरा*) के तहत अपने स्वयं के व्यापक रक्षा ढांचे का निर्माण 1982 में किया। पीएसएफ का मूल उद्देश्य “जीसीसीआई के अन्य किसी भी सदस्य देश के खिलाफ सैन्य आक्रामकता का पता लगाना और जवाब देना ” था। पीएसएफ को दो बार 1992 और 2006 में विस्तारित किया गया था और सऊदी अरब में मुख्यालय की स्थापना के साथ एक बड़े पैमाने पर रक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया था। इसके बाद एफ16, पी3सी ओरियन 30, तथा रक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों (तालिका 1, आंकड़े I और II) के साथ बड़े पैमाने पर खरीद हुई। जीसीसी की सैन्य श्रमशक्ति भी बढ़ गई। जमीनी शक्ति और समुद्री शक्ति के मुकाबले वायु शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया गया। वायु शक्ति में

जोड़ने के लिए , लंबी, मध्यम और छोटी दूरी की सामरिक मिसाइलों की एक किस्म का भी अधिग्रहण किया गया। वायु शक्ति को शसक्त बनाने के लिए , 1988-2010 के दौरान SIPRI के अनुसार, लंबी, मध्यम और छोटी दूरी की सामरिक मिसाइलों की एक किस्म का अधिग्रहण भी किया गया था। सिप्री के अनुसार, 1988-2010 के दौरान , रक्षा और रक्षा से संबंधित वस्तुओं (तालिका 2) के अधिग्रहण पर कतर को छोड़कर , जीसीसी के पाँच सदस्य देशों द्वारा लगभग 629 बिलियन डालर का खर्च किया गया था।

चित्र 1 तथा II में दिए गए विवरण के अनुसार पारंपरिक सैन्य व्यवस्था में ईरान निस्संदेह रूप से क्षेत्रीय दिग्गज है ; फिर भी इसकी उपस्थिति को नवीन अरब खाड़ी रक्षा प्रणालियों द्वारा चुनौती दी गई है। क्षेत्र के मुख्य देशों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान रक्षा के क्षेत्र में किए गए औसत व्यय के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि अरब खाड़ी क्षेत्र में रक्षा व्यय , दो क्षेत्रीय दिग्गजों, ईरान और सऊदी अरब के सापेक्ष रक्षा व्यय के अनुसार

कम है। 1990-94 तथा 1995-99 के दौरान हालांकि, ईरान के रक्षा व्यय ने बाकी क्षेत्रीय देशों को पीछे छोड़ दिया: इसमें क्रमशः 16.3 प्रतिशत व 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि दो समयावधियों के दौरान, जहां सऊदी अरब तथा जीसीसी में क्रमशः -4 प्रतिशत तथा -6.5 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत तक ईरान की तुलना में बहुत कम वृद्धि हुई थी। 2000-4 के दौरान भी यही रुझान जारी रहा। हालांकि ईरान ने रक्षा व्यय में बहुत कम वृद्धि की लेकिन इसने बढ़त बनाए रखी। सऊदी अरब के औसत वार्षिक रक्षा व्यय ने 1 प्रतिशत की बहुत कम वृद्धि दर्ज की व जीसीसी ने 1.6 प्रतिशत जबकि ईरान ने 3.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा (तालिका 3)

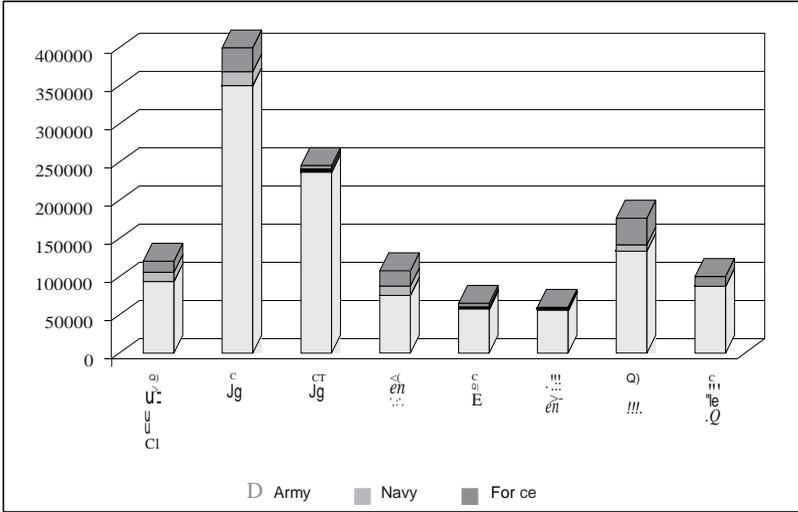
(20 11)	से	1500	2500	30,00	5167	5000	150	20,00	450	3000	1000	34,0	12,0
	ना			0			0	0	0			00	00
	कुल योग	8200	15,5 00	523,0 00a	245,7 82	42,6 00b	11,8 00	233,5 00c	51,0 00	66,5 00d	59,1 00	176,5 00	100,5 00
मुख्य युद्ध टैंक		180	293	1613	212	117	30	565	471	790	326	3501	1044
तोपें		92	218	8196	n/a	233	89	855	561	1167	492	5432	1232
टैंक रोधी हथियार		45	332	2720	n/a	200	144	2600	717	820	NA	NA	NA
टैंक रोधी		117	n/a	1882	n/a	58	58	1191	277	234	NA	NA	NA

हथियार												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

स्रोत: *सेना संतुलन, 2011*, आईआईएसएस, लंदन।

नोट: ईरान, ओमान, सऊदी अरब तथा यमन की सक्रिय सेनाओं में निम्नलिखित वर्गों में प्रशिक्षित कार्मिक शामिल हैं।

1. *ईरान*: 125,000 इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्पस।
2. *ओमान*: 2000-विदेशी बल; 6400-रॉयल हाउसहोल्ड।
3. *सऊदी अरब*: 9000-औद्योगिक सुरक्षा बल; 100000-राष्ट्रीय रक्षक; 16,000 वायु सेना।
4. *यमन*: 2000- वायु सेना।

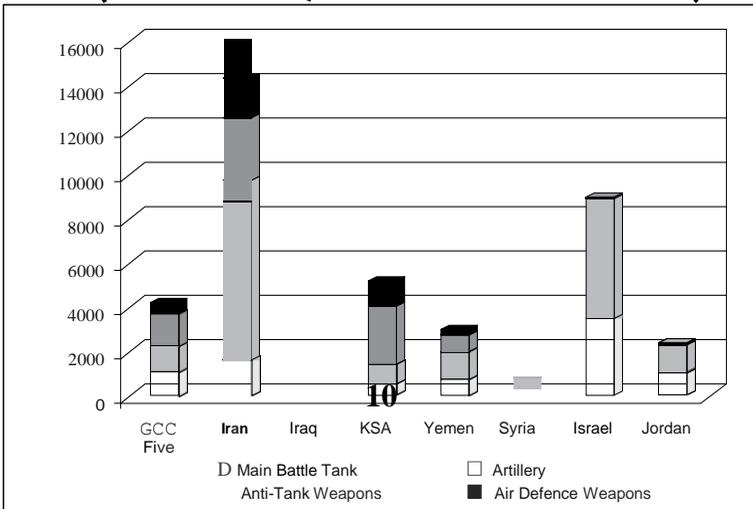


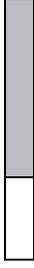
चित्र 1. ईरान की सैन्य संपत्ति के सामने शेष खाड़ी क्षेत्र

नोट: जीसीसी पाँच में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार तथा यूएई शामिल हैं।

स्रोत: तालिका 1

चित्र II ईरान की सैन्य हार्डवेयर के साथ बाकी का खाड़ी क्षेत्र





नोट: ईरानी विवरण उपलब्ध नहीं है (एन/ए)

स्रोत: तालिका 1

यह सब इस तथ्य के बावजूद था कि वे अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे थे और उन्हें अमेरिका से कोई सैन्य उपकरण प्राप्त नहीं हुए।

यह स्पष्ट है कि ईरान के रक्षा खर्च में निरंतर वृद्धि ने क्षेत्र में हथियारों की दौड़ के लिए उत्प्रेरक का काम किया। इसके परिणामस्वरूप, 2000/4-2005/10 के दौरान सऊदी अरब और जीसीसी ने अपने औसत वार्षिक रक्षा व्यय में क्रमशः 1 प्रतिशत से 28.2 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत से 18.1 प्रतिशत की वृद्धि की। यहां यह जानना रोचक है कि इस अवधि के दौरान ईरान के रक्षा खर्च में -4.9 प्रतिशत की कमी हुई। तेल की बढ़ी हुई कीमतों व साथ-ही-साथ बदलती सुरक्षा गतिविधियों ने, विशेषरूप से दो खाड़ी युद्धों के बाद, हथियारों की भारी खरीद का सहारा लेने के लिए जीसीसी देशों में हड़कंप मच गया हो, जबकि ईरानी रक्षाक्षेत्र ने तीन दशकों की हथियार मंजूरी का प्रभाव झेलना प्रारंभ कर दिया। एक तरफ पारंपरिक सैन्य क्षमता में बढ़ती कमी तथा जीसीसी देशों की सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण ने ईरान के

रणनीतिकारों को सैन्य उद्देश्यों के लिए व क्षेत्र में बढ़ते असंतुलन को संतुलित करने के लिए परमाणु क्षमताओं को विकसित करने पर विचार करने के लिए मजबूर किया होगा। इसके अलावा , इस क्षेत्र में जातीय-संप्रदायवादी भावनाओं के उदय और वृद्धि के साथ , सैन्यीकरण कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने के लिए ईरान को और अधिक सशक्त किया गया। शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संदेह के अलावा , पूर्व यूएसएसआर का पतन भी क्षेत्र में हथियारों की होड़ को तेज करने में एक कारक रहा है। यूएसएसआर ने इनमें से कुछ देशों को हथियारों की उदार आपूर्ति की थी। इस प्रकार शीत युद्ध के बाद की अवधि में उन देशों के रक्षा बजट में अचानक वृद्धि देखी गई जो पूर्व में सोविएत संघ पर निर्भर थी।

	(Mil .)	G DP	(Mil .)	G DP	(Mil .)	G DP	(Mil .)	G DP	(Mil .)	G DP	(Mil .)	GD P*	(Mil .)	GD P*
1988	21 3	5 5	254 0	8.2 8.2	17 22	18. 3	15,2 62	15 .2	365 8	8.6 8.6	23,39 5	12.4 7	167 6	2 2
1989	22 2	5. 1	315 4	8.5 8.5	18 10	16. 7	14,4 22	13 .4	370 3	7.8 7.8	23,31 1	11.2 4	210 4	2. 4
1990	24 2	4. 8	12,1 68	48. 5	21 02	16. 5	18,1 23	14 14	363 7	6.2 6.2	36,27 2	15.7 0	227 9	2 2
1991	26 3	5. 1	15,8 57	117 .3	17 41	14. 8	17,2 83	12 .5	349 9	6.3 6.3	38,64 3	17.2 3	221 5	1. 7
199	27	5.	803	31.	20	16.	16,2	11	339	6.1	30,04	12.3	197	1.

2	9	3	7	8	85	2	44	.3	5		0	7	1	4
199	27	4.	388	12.	19	15.	17,2	12	325	6.1	26,61	11.0	267	1.
3	1	8	9	4	85	4	16	.5	5		6	4	5	5
199	27	4.	412	13.	20	15.	14,8	10	309	5.9	24,44	10.0	413	2.
4	5	6	6	3	87	7	60	.6	3		1	6	6	4
199	28	4.	452	13.	20	14.	13,0	9.	301	5.5	22,94	9.2	297	1.
5	5	7	5	6	28	6	99	3	1		8	2	9	8
199	30	4.	384	10.	19	12.	13,0	8.	[298	[5.	22,12	7.0	331	1.
6	3	7	8	3	09	5	78	5	2]	1]	0	5	0	9
199	29	4.	293	8.1	19	12.	17,7	11	301	4.8	25,98	9.1	368	2.
7	7	6	3		78	5	60		6		4	9	9	1

199	30	4.	273	8.8	17	12.	20,5	14	298	5.1	28,31	11.1	389	2.
8	4	8	5		74	5	13	.3	6		2	6	1	4
199	34	4.	265	7.6	17	11.	18,2	11	295	4.3	26,00	9.0	543	3
9	0	9	8		97	4	60	.4	0		5	8	5	
200	33	4	308	7.2	21	10.	20,1	10	287	3.4	28,55	8.2	781	3.
0	7		2		39	6	25	.6	6		9	6	6	7

200	35	4.	302	7.7	24	12	21,4	11	283	3.4	30,14	8.	855	3.
1	5	2	9		88	.2	34	.5	6		2	92	2	9
200	42	4.	312	7.4	25	12	18,8	9.	286	3.3	27,79	7.	616	2.
2	4	7	6		62	.3	17	8	2		1	92	2	3

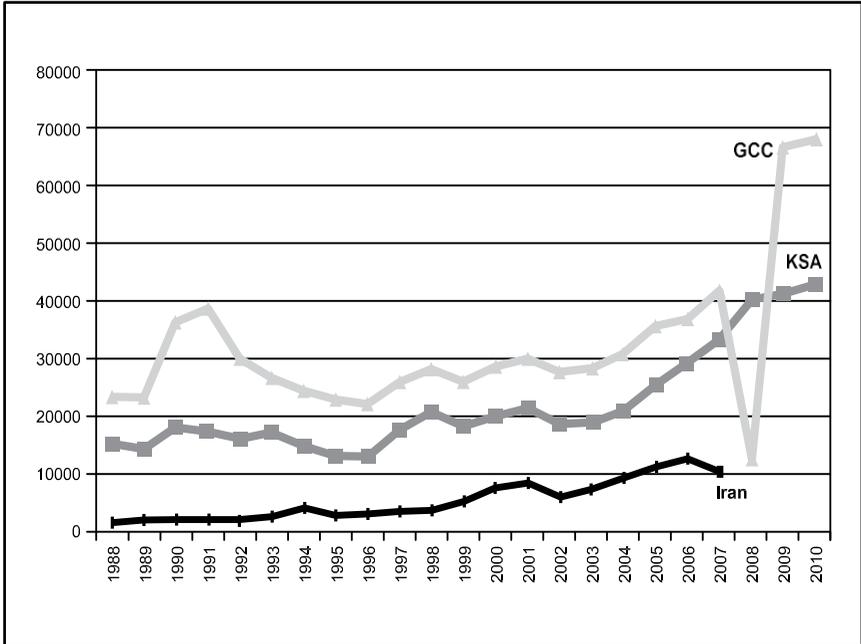
200	48	4.	336	6.5	26	12	18,9	8.	280	2.8	28,31	7.	750	2.
3	7	8	9		95	.1	56	7	7		4	04	3	7
200	49	4.	362	5.8	30	12	21,0	8.	258	2.3	30,80	6.	922	2.
4	1	3	6		30		74	4	5		6	66	8	9
200	48	3.	350	4.3	36	11	25,3	8	255	1.9	35,59	6.	11,4	3.
5	6	6	9		52	.8	93		9		9	16	44	3
200	52	3.	348	3.6	39	11	28,9	8.	n/a	n/a	36,84	n/	12,7	3.
6	8	4	6		05	.3	26	3			5	a	43	4
200	61	3.	391	3.9	39	10	33,3	9.	n/a	n/a	41,80	n/	10,4	2.
7	1	4	4		56	.7	20	3			1	a	73	5
200	67	3.	433	3.0	47	7.	40,1	8.	13,5	5.5	12,71	n/	n/a	n/

8	7	0	6		99	7	59	0	85		1.2	a		a
200	76	3.	433	3.6	44	10	41,2	11	1,57	5.0	66,64	n/	n/a	n/
9	2	2	4		89	.3	73	.2	74		3.2	a		a
201	73	3.	441	3.0	40	7.	42,9	8.	1,57	5.5	67,86	n/	n/a	n/
0	1	0	1		47	7	17	0	49		3.0	a		a

स्रोत: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई), <http://www.sipri.org/>

नोट:1. कतार को छोड़ दिया गया है। 2. एमआईएल से तात्पर्य मिलियन से है।

**चित्र III: 1988-2010 के दौरान ईरान,
सऊदी अरब तथा जीसीसी का व्यय। का
सैन्य व्यय।**



नोट: जीसीसी के आँकड़ों में दर्शाया गया डिप पिछले तीन वर्षों के ईरानी आँकड़ों के प्राप्त न होने के कारण है।

स्रोत: तालिका 2 से उद्धृत।

ईरान के रक्षा खर्च की शुरुआती वृद्धि प्रथम खाड़ी युद्ध (1990) की आशंकाओं और अपनी सीमाओं पर बढ़ते खतरों से निर्देशित थी जिसका सामना आठ वर्षों तक खींचे गए इराक-ईरान युद्ध (80-1988) के लंबे समय से दौरान हुआ था।

**तालिका 3: खाड़ी में 1990/94-2000/10 के दौरान
औसत रक्षा व्यय**

पिछले पाँच वर्षों में कुल औसतन वार्षिक व्यय (मिलियन डॉलर)							
	बहरी न	कुवै त	ओ मान	सऊदी अरब	यूएई	कुल जीसी सी	ईरान
1990-	266	8815.	2000	16,74	3375.	31,202	2655.

94		4		5	8		2
1995-99	305.8	3339.8	1897.2	16,542	14,945.0	25,074	3860.8
2000-04	418.8	3246.4	2582.8	20,081	2793.2	29,122	7852.2
2005-10	632.5	3998.333	4141.333	35,331.33	-	43,577.07	10,578.2
पाँच वर्षों में औसतन वार्षिक वृद्धि दर (%)							
1990-94	2.7	-13	-1	-4	-3	-6.5	16.3
1995-99	3.9	-41	-2	8.0	0	2.7	16.5
2000-04	9.1	4.0	8	1.0	-2	1.6	3.6
2005-	8.4	4.3	1.8	28.2	-	18.1	-4.9

स्रोत: तालिका 2 से गणना।

मात्रा और रक्षा व्यय के संदर्भ में ईरान पारंपरिक सैन्य उपकरणों (तालिका 1; आंकड़े I और II) की प्रभावशाली संख्या धारित करता है। फिर भी , यह देखते हुए, इसकी सशस्त्र सेनाएं प्रणालीगत शोष, रखरखाव संबंधी मुद्दों, साथ ही युद्ध-ग्रस्त होने के कारण, ईरान की वास्तविक युद्ध-क्षमता , शासन की बेलगाम बयानबाजी से कमतर सीमित हो गई। लंबे समय तक हथियारों के जखीरे और प्रतिबंधों ने अमेरिका और यूरोपीय सुरक्षा प्रणालियों की रक्षा क्षमता को कमजोर कर दिया है और इसकी खरीद की भी क्रमिकरूप से काफी जांच की है। ईरान अपने हथियार अधिग्रहण के लिए मुख्य रूप से रूस , चीन और कुछ हद तक उत्तर कोरिया पर निर्भर करता है जबकि अरब की खाड़ी सहित इज़राइल को अमेरिका /पश्चिमी सुरक्षा प्रणालियों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। ईरान को अब अपने अरब खाड़ी पड़ोसियों पर सैन्य बढ़त हासिल

नहीं है। ईरान के रूसी और चीनी-आपूर्ति वाले हथियारों का मिश्रण, जिन्हें अरब खाड़ी राज्यों (तालिका 5) द्वारा भारी मात्रा में खरीदा गया है, आधुनिक अमेरिकी/पश्चिमी हथियार प्रणालियों के लिए गुणात्मक रूप से कमतर है।

सके अलावा, ईरान की लड़ाकू सेना थकी हुई लगती है। बर्नार्ड कॉस्टर के अनुसार, हालांकि ईरान को कभी अपने खाड़ी अरब देश के प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में चलनशील पारंपरिक युद्ध में अधिक अनुभव प्राप्त था लेकिन इसके अनुभवी कर्मचारी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इराक-ईरान युद्ध में भाग लेने वाले लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ईरान की अधिकांश आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और उन्हें ईरानी क्रांति की कोई वैयक्तिक याद नहीं है। वे कट्टर रणनीतिकारों की दूरदर्शिता के लिए सेनाओं के खिलाफ खड़े होने और उठकर लड़ने के आह्वान की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। उनकी यह मनोवैज्ञानिकता 2009 के चुनाव में स्पष्टरूप से देखने को मिली जब भारी संख्या में युवा सुधारवादी नेताओं मीर होसेन मौसवी और मेहदी करबरबी को समर्थन देने के लिए सड़कों पर

उतर आए।

यह भी बताया गया कि ईरान की सेना कुछ जमीनी और हवाई सेना उपकरणों को अंगोपयांग करते हुए दूसरे भागों को क्रियाशील रखने के लिए इन्हें स्पेयर पार्ट्स में रूपांतरित कर रही है।

ईरानियों के विषय में भी बताया गया है कि “वे अपनी सेना को क्रियाशील रखने हेतु स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए एक गुप्त काला बाजार में तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिका से एफ-4, एफ-5 तथा एफ-14 विमानों के अनेक स्पेयर पार्ट्स की ईरान को तश्करी किए जाने के अनेक मामलों को भी उजागर किया गया”।

जीसीसी देशों के रक्षा निर्माण में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका से आया , इसके बाद फ्रांस , यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी का स्थान रहा, जबकि ईरान ने बाद में रूस , चीन और उत्तर कोरिया पर आश्रित रहना जारी रखा। तालिका संख्या 5

तालिका 4: 2009 में मिडिल ईस्ट के रक्षा सेनाओं का
विवरण

मिडिल ईस्ट में कुल	कुल रक्षा व्यय (\$)	जीडीपी का भाग (%) (2009)	देश	जनसंख्या
	742 मिलियन	3	बहरीन	807,000
	115 मिलियन	3.8	मौरीतानि या	
	781 मिलियन	1.2 2	ट्यूनीशि या	
	3.91 बिलियन	4.2 6	कुवैत	3.050 मिलियन

मिडिल ईस्ट \$139.90 7 बिलियन (5.09% GDP)	13-14 बिलियन	1.8	ईरान	75.077 मिलियन
	4.9 बिलियन	6.3 1	ईराक	31.466 मिलियन
	15.6 बिलियन	6.9 1	इजराइल	7.285 मिलियन
	4.02 बिलियन	8.7 1	ओमान	2.905 मिलियन
	9.1 बिलियन	2.5 4	कतार	1.508 मिलियन
	10.98	सऊदी अरब		
	41.3 बिलियन			27.0 मिलियन

29.2 बिलियन	3.5 5	यूएई	4.707 मिलियन
2.23 बिलियन	4.1 5	सीरिया	23.0 मिलियन
1.43 बिलियन	4.1 3	लेबनान	4.2 मिलियन
2.02 बिलियन	3.5 1	यमन	2.4 मिलियन
1.39 बिलियन	5.5 1	जार्डन	6.4 मिलियन
4.1 बिलियन	2.2	इजिप्ट	84 मिलियन
1.71 बिलियन	2.8 4	लीबिया	6.7 मिलियन
3.06	3.3	मोरक्को	32.3

	बिलियन	4		मिलियन
	5.28	3.7	अल्जीरि	35.4
	बिलियन	8	या	मिलियन

स्रोत: आईआईएसएस, रक्षा संतुलन, 2011।

1988-2010 के दौरान जीसीसी तथा ईरान को प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं को दर्शाता है। इस समयावधि के दौरान ईरान ने अमेरिका से कोई भी अथवा बहुत कम हथियार प्राप्त किए थे तथा मुख्य यूरोपीय देशों से मात्र \$400 मिलियन के ही प्राप्त किए थे। रूस ने 4800 मिलियन डॉलर के हथियार ईरान को सप्लाई किए थे; चीन ने भी लगभग बराबर 4700 मिलियन डॉलर के हथियारों सहित ईरानी हथियार बाजार में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। प्रारंभिक वर्षों के दौरान चीन ने ईरान को बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किए थे लेकिन धीरे-धीरे उसने रूस के बाजार को खो दिया। इसका कुल परिणाम यह है कि ईरान के पास आधुनिक हथियारों तक पहुँच के सीमित स्रोत ही उपलब्ध हैं।

जब से अरब क्षेत्र में प्रजातांत्रिक उन्नयन प्रारंभ हुआ है, अरब खाड़ी देशों ने अपनी दोनों, हवाई शक्ति के साथ-साथ मिसाइल रक्षा कवच प्रणालियों की रक्षा क्षमताओं को आधुनिकीकृत किया है। इन दोनों ने अपने जखीरों में उन्नत हथियारों को शामिल किया है और मौजूदा हथियारों को आधुनिकीकृत किया है।

अरब खाड़ी के प्रमुख देशों ने अमेरिका के साथ लगभग 75-80 बिलियन डॉलर के हथियारों के सौदे पूरे किए हैं जिनमें- सऊदी अरब के साथ (30 बिलियन डॉलर), इजराइल (30 बिलियन डॉलर), ईराक (11.4 बिलियन डॉलर) तथा यूएई के साथ (3.5 बिलियन डॉलर) का सौदा शामिल है। सऊदी अरब को 84 उन्नत एफ -15, तीन प्रकार के हेलीकॉप्टर - 70 अपाचे , 72 ब्लैक हॉक्स और 36 लिटिल बर्ड्स और नई युद्ध सामग्री और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होंगे। सऊदी अरब के 70 एफ15 विमानों को भी आधुनिकीकृत किया जाना है। वर्तमान सौदा सऊदी अरब के लिए एक दसवर्षीय, 60 बिलियन डॉलर हथियार पैकेज का सौदा है जिसे कांग्रेस के द्वारा 2011 में अनुमोदित किया गया था। इसी तरह के साझी रुझानों में सीरिया ने 3.5 बिलियन डॉलर का सौदा सीरिया के साथ पूरा किया है। अमेरिका ने टीएचएएडी - टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड डिफेंस- मिसाइल रक्षा प्रणाली को 3.5 बिलियन डॉलर में यूएई को बेचा है।

तालिका 5 1988-2003 के दौरान जीसीसी
देशों, सीरिया तथा ईरान को प्रमुख
आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा दिये गये
हथियार

(US\$ वर्तमान मिलियन)

		प्रमुख	अ न्य			अ न्य	
--	--	--------	----------	--	--	----------	--

आपूर्तिकर्ता	अमेरिका	पश्चिमी यूरोपीय देश	यूरोपीय देश	रूस	चीन	सभी देश	कुल
प्राप्तिकर्ता देश							
बहरीन							
2007-2010	300	0	0	0	0	0	300
2003-2006	300	0	0	100	0	0	400
2000-2003	600	0	0	0	0	0	600
1996-1999	300	0	0	0	0	0	300
1996-1995	300	0	0	0	0	0	300

1988- 1991	400	100	0	0	0	0	500
कुवैत							
2007- 2010	1,30 0	0	0	0	0	0	1,30 0
2003- 2006	1,10 0	0	0	0	200	0	1,30 0
2000- 2003	1,10 0	300	0	100	400	20 0	2,10 0
1996- 1999	2,50 0	1,4 00	100	400	0	0	4,40 0
1996- 1995	2,40 0	300	100	200	0	10 0	3,10 0
1988- 1991	500	200	200	200	0	10 0	1,20 0

ओमान							
2007- 2010	300	500	0	0	0	0	800
2003- 2006	500	300	0	0	0	0	800
2000- 2003	0	0	0	0	0	10 0	100
1996- 1999	0	400	0	0	0	0	400
1996- 1995	0	800	0	0	0	0	800
1988- 1991	100	100	0	0	0	0	200
कतार							
2007-	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.	100

2010						0	
2003- 2006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0
2000- 2003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0

1996- 1999	0.0	1,800	0.0	0.0	0.0	0.0	1,800
1996- 1995	0.0	100	0.0	0.0	0.0	0.0	100
1988- 1991	0.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	300
सऊदी अरब							
2007- 2010	5,30 0	2,200	400	0	700	100	8,70 0
2003- 2006	4,20 0	15,400	400	0	200	10	20,2 10
2000- 2003	6,30 0	16,600	1,00 0	0	0	0	23,9 00
1996- 1999	16,6 00	17,600	3,00 0	0	0	0	37,2 00

1996- 1995	12,4 00	15,000	1,70 0	0	200	100	29,4 00
1988- 1991	6,60 0	16,500	900	200	260 0	400	27,2 00
यूई							
2007- 2010	900	400	300	400	100	0	2,10 0
2003- 2006	500	5,500	300	200	0	0	6,50 0
2000- 2003	300	1900	200	100	1,90 0	100	4,500
1996- 1999	400	3,600	700	300	3,60 0	100	8,700
1996- 1995	700	300	100	300	300	100	1,800

1988- 1991	500	2100	0	0	2,10 0	400	5,100
ईरान							
2007- 2010	0	0	100	400	0	200	700
2003- 2006	0	0	100	300	200	200	800
2000- 2003	0	0	0	200	0	400	600
1996- 1999	0	100	300	900	700	0	2,000
1996- 1995	0	100	100	1,40 0	700	300	2,600
1988- 1991	0	200	1,40 0	1,60 0	3,10 0	1,500	7,800

सीरिया							
2007-	0.0	0.0	0.0	1,20	300	200	1,700
2010				0			

नोट: 0 0, US\$50 मिलियन से कम के लिए दिया गया है।

स्रोत: एंथोनी एच. कार्ड्समैन, दि मिलिटरी बैलेंस इन दि गल्फ: दि

डाइनामिक्स ऑफ फोर्स डेवलपमेंट्स, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक

स्टडीज एण्ड इंटरनेशनल स्टडीज, वाशिंगटन, 2011, पीपी.

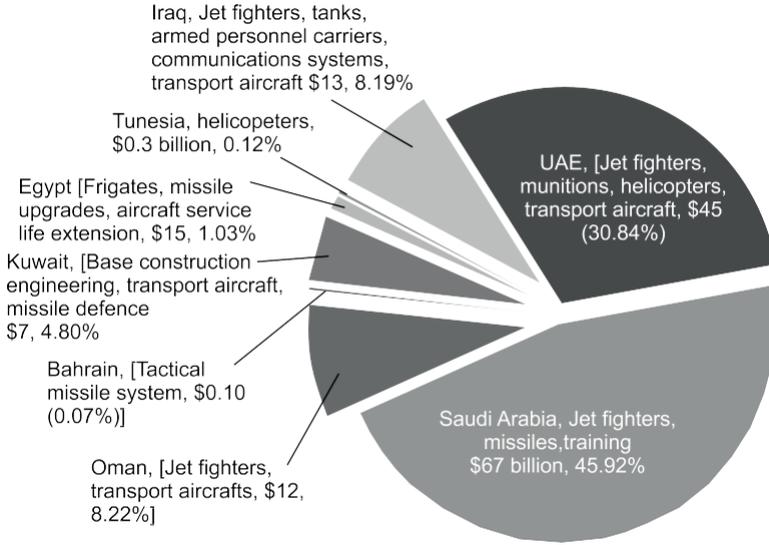
55-6। 2003-06 तथा 2007-10 के ऑकड़े रिचर्ड एफ.

ग्रीमेट, कन्वेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स टु डेवलपिंग नेशंस,

2003-2010, सीआरएस रिपोर्ट, 22 सितंबर, 2011।

चित्र IV. 2010-2011 के दौरान पश्चिम एशियाई देशों, का रक्षा

अधिग्रहण योजनाएं



स्रोत: अमेरिका-अरब व्यापार आउटलुक 2013, दि नेशनल यूएस-

अरब चैंबर ऑफ कामर्स।

ईरानी राकेटो की धमकियों को कम करने के लिए अमेरिका सऊदी पेट्रिओट मिसाइल प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए भी समर्पित है।

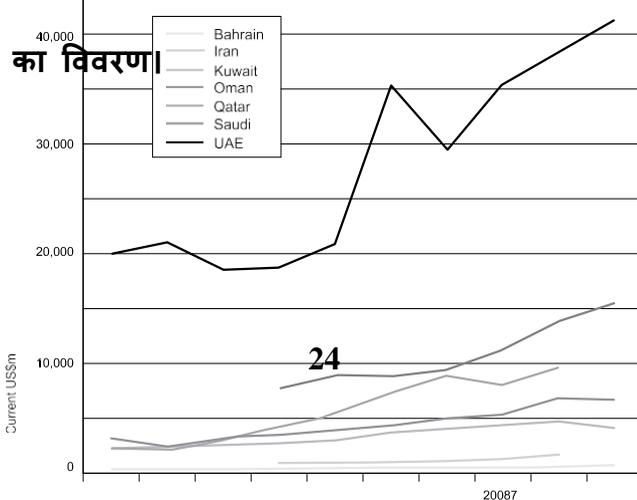
चित्र IV 2010-2011 के दौरान अनेक पश्चिम एशियाई देशों के रक्षा अधिग्रहण की योजनाओं को दर्शाता है। ये लगभग 159.4 बिलियन डॉलर की है। सऊदी अरब ने 67 बिलियन डॉलर की हथियार प्रणाली को लिया उसके बाद यूएई 4.5 बिलियन डॉलर, ईराक 13 बिलियन डॉलर और बहरीन जैसे छोटे से देश ने 12 बिलियन डॉलर को लिया। अधिकतर खाड़ी देशों ने आधुनिक जैट फाइटरो, मिसाइलों तथा प्रशिक्षण को अधिग्रहित किया और पारंपरिक हथियारों और गोलाबारूद को दरकिनार कर दिया जैसा कि अन्य पश्चिम एशियाई देशों ने नहीं किया।

चित्र V वर्तमान शताब्दी में जीसीसी देशों तथा ईरान के रक्षा व्ययों को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि सऊदी अरब ने निरंतर अपने रक्षा व्यय को बनाये रखा जबकि ईरान मात्र कतार से ऊपर दूसरा-न्यूनतम स्थान पर रहा। यहां तक कि छोटे से देश जैसे कि ओमान, कुवैत तथा बहरीन ने रक्षा व्यय के एक उच्च स्तर को बनाये रखा। बीबीसी समाचार के अनुसार, “जीसीसी (बहरीन को छोड़कर) ने 2011 में रक्षा खरीद पर 21.3 बिलियन डॉलर खर्च

किए”।

अमेरिका और अरब देशों के बीच मौजूदा हथियारों के सौदे को विशेषज्ञों के द्वारा “ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय शक्तियों को मजबूत करने के प्रयास” के रूप में देखा जाता है। देश के राजनीतिक-सैन्य मामलों के सहायक सचिव एंड्रयू जे शापिरो के अनुसार “यह बिक्री इस क्षेत्र के देशों को एक मजबूत संदेश देगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका खाड़ी और विस्तृत मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है”। उन्होंने आगे यह भी जोड़ा, कि “यह सऊदी अरब को अपनी संप्रभुता के लिए बाहरी खतरों से बचने और बचाव करने की क्षमता में वृद्धि करेगा”।

चित्र V. 2000-2009 के दौरान खाड़ी देशों के रक्षा व्यय



स्रोत: आईआईएसएस,

<http://www.iiss.org/publications/strategic-comments/past-issues/volume-15-2009/volume-15-issue-9/gulf-states-step-up-defences/>.

विदेशी मामलों की परिषद के थॉमस लिप्पमैन की टिप्पणी है कि यह सौदा “ईरानियों के लिए एक चेतावनी है, कि अगर तेहरान एक परमाणु मार्ग पर चलना जारी रखता है तो प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों और दुश्मनों के लिए यह होगी कि उनकी समग्रतः स्थिति हसित हो जाएगी”।

हाल के वर्षों में , ईरान ने संभावित समुद्री चुनौतियों का भी सामना किया है। यद्यपि इसके पास विशाल और कुशलरूप से प्रशिक्षित समुद्री सेनाएं मौजूद हैं , लेकिन बहरीन में अमेरिकी नौसेना बल की पांचवीं फ्लीट की उपस्थिति , जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगातार बनी हुई है , ने समुद्र से अरब खाड़ी देशों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इसकी नौसैनिक क्षमता का मुकाबला किया। वर्तमान में , अमेरिका, नाटो, फ्रांस, चीन, भारतीय और रूस सहित दुनिया की तीस से अधिक नौसेनाएं , समुद्री लुटेरों के साथ-साथ समुद्री डकैती से निपटने के लिए अदन की खाड़ी में मौजूद हैं और साथ ही अरब सागर के पानी से गुजर रही एसएलओसी (संचार की समुद्री रेखाओं) की सुरक्षा भी करती हैं।

बड़ी संख्या में नौसैनिक पट्टियों की मौजूदगी होर्मुज या तेल मार्ग के जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने अथवा असममित ताकतों को दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनल रास तनुरा या दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रसंस्करण सुविधा पोर्ट ऑफ अबकीक आदि जैसे किसी भी बड़े तेल टर्मिनल को ध्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले ईरानी खतरे के लिए एक बाधक होगी। आतंकवादी सऊदी तेल टर्मिनलों में भी तोड़-फोड़ करने का प्रयास कर सकते हैं: मई 2006 में आतंकवादियों ने अबकैक में स्थित प्रमुख अरामको (एआरएएमसीओ) पर आक्रमण करने का प्रयास किया था।

तेल-समृद्ध अरब राजतंत्र इराक-ईरान युद्ध के परिणाम और उप-क्षेत्रीय जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के गठन के साथ उदासीन थे। युद्ध में दो क्षेत्रीय दबंगों इराक तथा ईरान ने अपनी ऊर्जाओं को एक दूसरे पर खर्च कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका भी चुपचाप इस युद्ध में शामिल था और बड़ी मात्रा में इराक के रासायनिक और जैविक हथियारों के जखीरे को जमा करने में

शामिल था। एक अनुमान के अनुसार यह माना गया था कि ईराक द्वारा चालीस ईरानी लक्ष्यों पर लगभग 100,000 रासायनिक गोले उपयोग किए गए थे। इस बात का अनुमान लगाया था कि 1984 तक दोनों देशों में लगभग 300,000 (ईरान) तथा 250000(ईराक) लोगो हताहत हुए थे। इस युद्ध की आर्थिक लागत भी बहुत अधिक थी एक अनुमान के अनुसार ईरान के लिए यह लगभग 644 बिलियन डॉलर और इराक के लिए 452.6 बिलियन डालर का अनुमान लगाया था। युद्ध ने दोनों देशों की युवा आबादी पर भारी महसूल भी लगाया , विशेष रूप से युद्ध-विराम उत्पन्न करने के मामले में और युद्ध की तबाही के परिणामस्वरूप दुख के रूप में। सद्दाम हुसैन के रासायनिक युद्ध के जवाब में , ईरान ने 10 से 12 साल तक की युवा पास्टर्न सेना और बासिज स्वयंसेवकों का इस्तेमाल खदानों को विस्फोटों से उड़ाने के लिए कहा। इन किशोरों को अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की धार्मिक कट्टरता के साथ पक्का किया गया था , कि अगर उन्हें युद्ध के मैदान में मार भी दिया गया तो वे सीधे स्वर्ग जाएंगे। खुमैनी के अनुसार इस्लाम में

सबसे पवित्र खुशी, "अल्लाह के लिए मरना और मारना है। ईरानी रक्षा बलों के पास इराकी माइनफील्ड्स में विस्फोट करने के लिए उपकरणों की कमी थी और वे अपने छोटे युद्धक टैंकों को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं थे। युवा सैनिकों द्वारा शुरू किए गए हमलों को "मानव लहर" हमलों का नाम दिया गया था।

ईरान और इराक की राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण के अलावा, युद्ध ने 1979 में ईरानी क्रांति द्वारा फैलाए गए इस्लामीकरण की संक्रामक शक्तिशाली लहर को शांत करने में भी मदद की थी। माना जाता है कि ईरानी क्रांति से पार पाने के लिए इसके साथ-साथ तालिबान की स्थापना की गई थी। 1988 में इराक-ईरान युद्ध की समाप्ति के बाद, परिदृश्य इस स्तर तक बदला कि बजाय कि अरब-खाड़ी देश अपने मामलों को स्वतः प्रबंधित करने में सफल रहते, अमेरिका भी इस क्षेत्र में शामिल होता दिखाई दिया। इस अवधि के दौरान जीसीसी देशों ने अमेरिकी उपकरणों पर आश्रित रहना प्रारंभ कर दिया था तथा रणनीतिक और सैन्य मामलों में पश्चिमी हस्तक्षेप अधिक तैज हो गया था।

खाड़ी युद्ध एवं नये क्षेत्रीय समीकरण

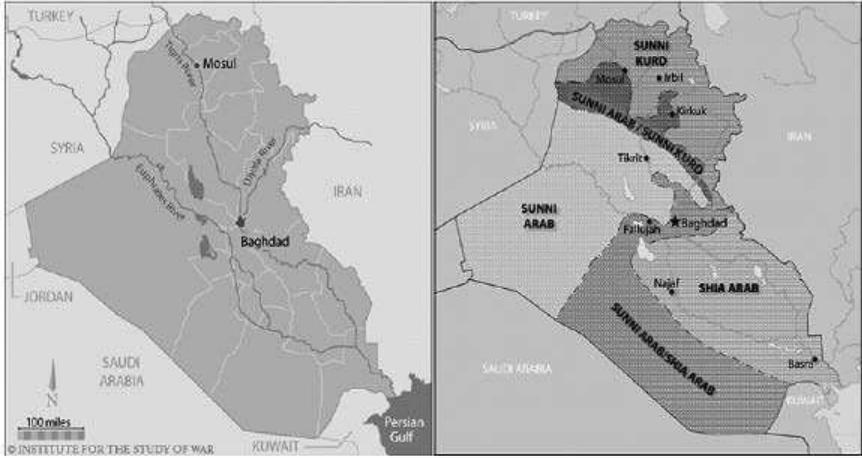
1990 तक, अरब खाड़ी क्षेत्र में स्थिति जीसीसी सदस्यों की गणना के अनुसार बदल गई। अगस्त 1990 में रणनीतिक मंटी टूट गयी जब ईराक ने स्पष्टतौर पर ईरान के साथ हुए युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए कुवैत पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने क्षेत्र के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक इतिहास को पूरी तरह से चित्रित किया, शायद हमेशा के लिए। पिछले दशकों मेहनत से बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था तथा संतुलन समीकरण एक ही झटके में ध्वस्त हो गए। तेल राजतंत्रों को अपनी नीति विकल्पों की सीमाओं और अपनी रक्षा क्षमताओं की कमजोरी का एहसास हो गया था। जीसीसी ने कुवैत द्वारा ईराक के खिलाफ की गई सेना सहायता की मांग के सापेक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई: बल्कि वे चाह रहे थे कि पश्चिमी सहयोगी हस्तक्षेप करे। डिजर्ट स्टोर्म आपरेशन के दौरान अमेरिकी गठबंधन की कमांड पर अट्ठाईस से अधिक देशों ने सीधे क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। यद्यपि

यह हस्तक्षेप वैध था फिर भी सहयोगी सेनाओं का लंबे समय तक उस क्षेत्र में जमाव, विशेषरूप से अमेरिका का उस क्षेत्र की एकता और स्थायित्व के लिए खतरनाक साबित हुआ।

इसने पूरी तरह से इस क्षेत्र के भूस्थिर परिवर्तन को हमेशा के लिए बदल दिया। इराक पर दूसरे युद्ध सहित इस क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप से उपजे कुछ विकासक्रम इस प्रकार हैं।

(क) घरेलू प्रभाव

- इराक दो खाड़ी युद्धों में बर्बाद हो चुका था। सामाजिक और आर्थिकरूप से देश बहुत नीचे पहुँच गया और अराजकता में डूब गया। लगभग 4 प्रतिशत जनसंख्या जो कि एक मिलियन से अधिक थी मात्र 4 वर्षों में 2007 तक मर चुकी थी; 2.56 मिलियन आंतरिक तौर पर विस्थापित हो चुकी थी तथा देश के 25 प्रतिशत परिवार अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य (शिया समुदाय में 34 प्रतिशत) की हत्या के गवाह बने थे।



चित्र VI. युद्ध के बाद इराक का क्षेत्रीय विभाजन, 2003

स्रोत: (i) <http://www.understandingwar.org/map/iraq-all>

(ii)

<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5052090>.

- इराक की राजनीतिक और क्षेत्रीय संरचना हमेशा के लिए बदल गई। वाम-झुकाव वाली बाथ पार्टी को कुचल दिया गया और क्षेत्रीयरूप से , जातीयता ने इराक को शिया इराक , सुन्नी इराक और कुर्द इराक (चित्र VI) में विभाजित कर दिया।
- 60-65 फीसदी आबादी वाले शिया बहुमत को सुन्नी अल्पसंख्यक के शासन से मुक्त कर दिया गया (तालिका 6 देखें)।

तालिका 6: खाड़ी जनसांख्यिकी में शिया जनसंख्या (%)

देश	ईरान	बहरीन	ईराक	लेबनान	कुवैत	कतार	सऊदी अरब	यूएई	सीरिया
शिया	90	75	65	45	30	16	10	6	1

स्रोत: वाली नास्र, *दि शिया रिवाइवल: हाउ कनफिल्कट्स विदइन इस्लाम विल शेप दि फ्यूचर,*

डब्ल्यू. डब्ल्यू. नार्टन, वाशिंगटन, 2006

- संपत्ति, मानवीय तथा प्राकृतिक स्रोतों के वृहद नुकसान के साथ ईराक खाद्य असुरक्षा से पीड़ित होने लगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित तेल खाद्य कार्यक्रम (ओएफपी) से संबंधित प्रस्तावों का एकमात्र उद्देश्य युद्ध के बाद होने वाली मानवीय क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए इराक को धन उपलब्ध कराना था। प्रारंभिक तौर पर ओएफपी के अधीन धनराशि 1 बिलियन डॉलर (यूएनएससी संकल्प 986) थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 5.2 बिलियन डॉलर (संकल्प 1153) कर दिया गया।
- इराक को वृहद पुनर्निर्माण लागत में झोंक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक तथा अनंतिम सहयोगी प्राधिकरण (सीपीए) के अनुसार 2004-2007 के दौरान इराकी

पुनर्निर्माण की लागत को लगभग 56 बिलियन डॉलर आंका गया था। इसमें से वित्त वर्ष 2006 के दौरान इराक में अमेरिकी सेना आपरेशनों को समर्थन देने के लिए दिए गये 320 बिलियन डॉलरों को अलग रखा गया है।

- इराक के तेल संसाधनों के लिए हाथापाई ने देश को विभिन्न शक्ति परिक्षेत्रों में विभाजित कर दिया। मुख्य रूप से शिया आबादी वाले तेल से समृद्ध दक्षिणी इराक में 120 बिलियन बैरल तेल आरक्षित होने का अनुमान है। क्षेत्रीय नेताओं ने तेल स्वायत्त क्षेत्र के गठन हेतु प्रश्न करना शुरू कर दिया। एक समय यह भी माना गया कि ईरान ने बसरा क्षेत्र में निविदा देने के लिए भी पैरवी की थी।
- एक अनुमान के मुताबिक , ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की 60 बिलियन डॉलर की लागत का लगभग 60 फीसदी सऊदी अरब और बाकी कुवैत ने चुकाया था। कुवैत ने जनधन खाते के लिए अपने फंड से नकदी वापस ले ली।

(ख) क्षेत्रीय तथा वैश्विक प्रभाव

अरब क्षेत्र पर अमेरिकी पकड़ मजबूत हुई। अगस्त 2000 में, अमेरिका ने कतर में अल-उदीद में एक वायु सेना अड्डे की स्थापना की।

- इराक में अमेरिका की विचलित उपस्थिति ने अरबों के बीच अमेरिका-विरोधी मजबूत भावनाओं को उत्पन्न किया। यह 11 सितंबर 2001 की घटनाओं और विश्व स्तर पर और विशेष रूप से पश्चिमी देशों के बीच , और अफगानिस्तान में अमेरिका की भागीदारी और दक्षिण एशियाई गतिशीलता पर इसके प्रभाव की व्यापक घटनाओं द्वारा प्रवर्धित किया गया था।

- इराक तथा अफगानिस्तान में युद्ध की लागतों ने इन लागतों को सीमित करने के लिए अमेरिका में घरेलू दबाव बनाया। विरोध को शांत करने के लिए , प्रशासन ने टकराव की सभ्यताओं की परिकल्पना का प्रचार किया। इसने इस्लामवादियों और पश्चिम के बीच दरार को और गहरा कर दिया।
- नौ साल के युद्ध (मार्च 2003-दिसंबर 2011) के दौरान जान-माल का भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा के अनुसार , “यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत अधिक थी - संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्त और खजाने में और इराकी लोग भी ”। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में अपने युद्धों में लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। 37,000 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और 5000 मारे गए; अकेले इराक में दस लाख से अधिक नागरिक मारे गए (चित्र VII)।

- इराक में सुन्नी-अल्पसंख्यक शासन के पतन के साथ खाड़ी में शिया प्रभुत्व पुनः स्थापित हुआ जिसने क्षेत्र में मौजूदा शक्ति के संतुलन को बिगाड़ दिया। यह अनुमान है कि बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरब तथा यूएई में कुल मिलाकर 81.3 मिलियन शिया जनसंख्या है जो खाड़ी की कुल जनसंख्या की लगभग 61 प्रतिशत जनसंख्या है।
- सऊदी अरब के विरोध के बावजूद , अमेरिका ने कतर में एक एयरबेस और बहरीन में एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना की , जिसने छोटे संसाधन संपन्न अरब देशों को अमेरिकी सुरक्षा छतरी के नीचे धकेल दिया। यह विकास GCC के भीतर बढ़ती दरार को भी केंद्र में लेकर आ गया।
- इराक में युद्ध ने तेल बाजार को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। यहां पर दो प्रगतियां हुईं। पहली, युद्ध ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। 2003 के अनुमोदन से

पहले, तेल की कीमत 25 डॉलर प्रति बैरल थी और भविष्य में बाजार में इसी के आस-पास रहने का अनुमान था।

युद्ध ने इस समीकरण को बदल दिया और तेल की कीमते 100 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गईं। दूसरा, सऊदी अरब

और बाद में कुवैत ने भी अपनी आय को अपने सुरक्षित भंडार को बेचकर बढ़ाने की कोशिश की। सऊदी अरब के पास सबसे अधिक क्षमता, विश्व की लगभग 70 प्रतिशत की भंडारण क्षमता है। सहमति के आधार पर आवटित भाग का यह उल्लंघन क्षेत्र और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के भीतर संघर्ष का कारण बन गया।

- इराक के लंबे समय तक चले युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि से अरब खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर मुद्रा का स्थानांतरण हुआ। इसने विश्व के वित्तीय संतुलन को बिगाड़ दिया। चीन , सिंगापुर और कई खाड़ी अमीरात परेशान वॉल स्ट्रीट के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता बन गए हैं। इन देशों ने अन्य अमेरिकी परिसंपत्तियों के बड़े

हिस्सों को खरीदना शुरू कर दिया। इसी अवधि के दौरान ,
 क्षेत्र में सॉवरिन वेल्थ फंड का विकास हुआ। इसी
 समयावधि के दौरान, इस क्षेत्र में संप्रभु धन उपजने लगा।

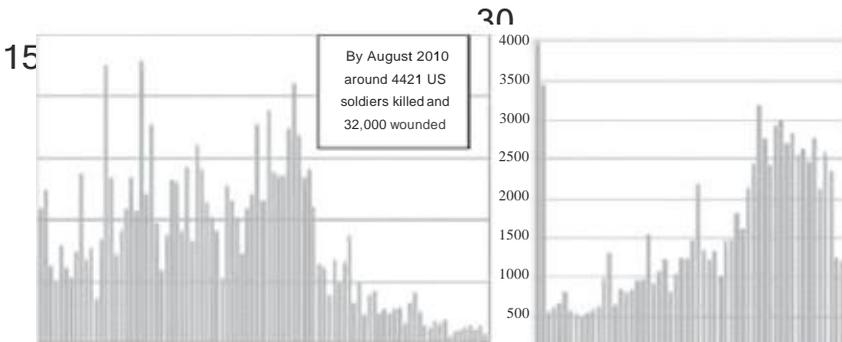
- पश्चिम एशियाई-अफगान राजनीति में अमेरिका के शामिल होने ने अन्यों को खुद को मुखर करने का मौका प्रदान कर दिया। पाकिस्तान और ईरान ने चुपके से अपनी परमाणु रक्षा क्षमताओं का निर्माण शुरू कर दिया।

चित्र VII. इराक युद्ध 120

में हुई जनहानि, मार्च

2003 - जुलाई 2010 90

60



ईराकी नागरिकों की
मौतें, मार्च 2003-
जुलाई 2010
इराक में अमेरिकी
सैन्य मौतें, मार्च
2003-जुलाई 2010
स्रोत: इराक की शरीर
संख्या
स्रोत रक्षा मैनपावर डेटा
केन्द्र

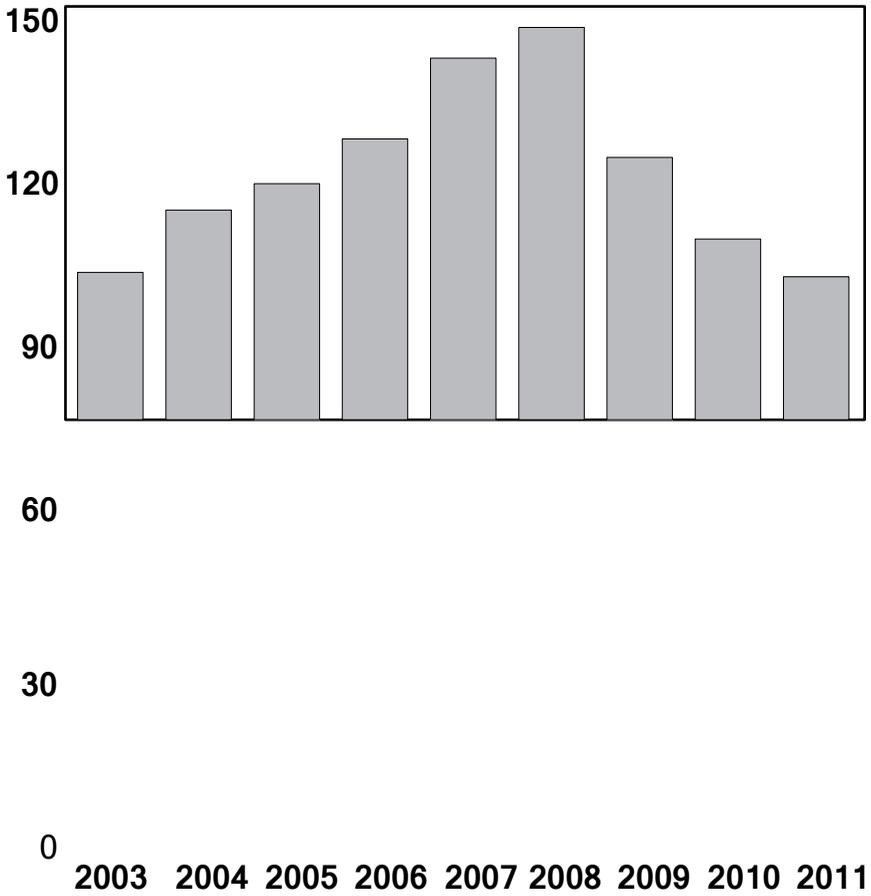
स्रोत: US flag ceremony ends Iraq operation”, BBC News,
14 December 2011.

[http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-](http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11107739)

[11107739](http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-11107739)

चित्र VIII. इराक युद्ध की कुल अमेरिकी वित्तपोषण,
2003-2011

\$bn



स्रोत: चित्र 7 के समान।

नोट: * लंबित अनुरोधों को प्रदर्शित करता है।

पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने तथा ईरान की परमाणु बोगी के नाम पर सऊदी अरब तथा अमेरिका दोनों से बड़ी धनराशि आहरित करता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर 10 बिलियन डॉलर का भुगतान किया जा चुका है जिसे कथित रूप से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने में उपयोग कर लिया है। इसकी समाप्ति अब्बोताबाद में अमेरिका के ओसामा बिन लादेन के खिलाफ आपरेशन से समाप्त हो गया। वैश्विक परिदृश्य से अमेरिका की लंबी अनुपस्थिति ने चीन को लगभग हर क्षेत्र में अमेरिका के लिए एक शक्तिशाली चुनौती के आकार को विकसित करने और ग्रहण करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया है।

अरब की खाड़ी में नए भू-आकृतिक समीकरण

खाड़ी युद्ध के बाद अरब क्षेत्र दो प्रमुख घटनाओं द्वारा

चिह्नित किया गया है: 2003 के वसंत में इराक का विघटन जो सदियों पुराने बिजली संबंधों के पतन में अग्रणी रहा; और इस क्षेत्र में ईरानी परमाणु संधि और इसका भू-रणनीतिक बुरे सपने के तौर पर सामने आना।

15 दिसंबर, 2011 को इराक युद्ध की समाप्ति की आधिकारिक अमेरिकी घोषणा के आलोक में , एक बार फिर से बेदीन अरबों पर ईरानी सभ्यता के वर्चस्व की पुरानी बोगी , जो सुन्नी देशों को अधिकारहीन करने में अग्रणी रहा, वह क्षेत्र में उठकर सामने आ गया। इसने प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों को इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक मानचित्र को अपने हितों के अनुकूल बनाने के लिए उकसाया है। अमेरिका के पीछे हटने के बाद इस क्षेत्र की शक्ति के खालीपन को कौन भरेगा ? सभी क्षेत्रों में इरान इस क्षेत्र का अग्रणी देश बनकर सामने आया। शीत युद्ध और खाड़ी युद्ध के बाद (18 मार्च 2003-15 दिसंबर 2011) के युग ने ईरान को परमाणु और जातीय दोनों मोर्चों पर रणनीतिक विशेषाधिकार का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है।

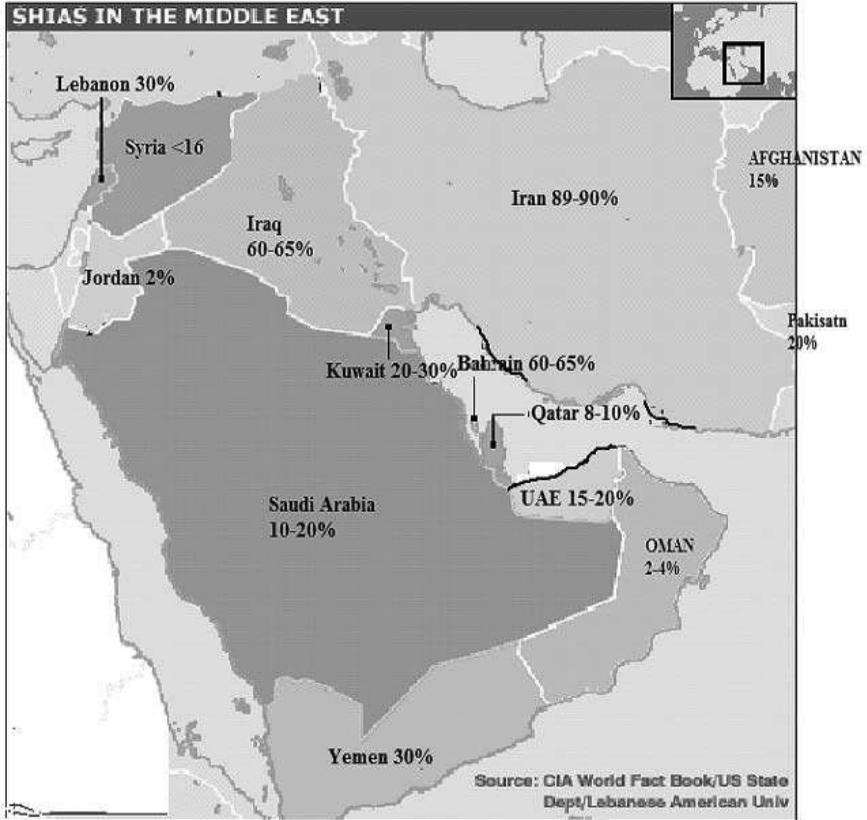
खाड़ी क्षेत्र में सांप्रदायिक विशेषाधिकार के अलावा ईरान मध्य एशियाई गणराज्यों (सीएआर) में से कुछ में भी समान जातीय-रणनीतिक विलासिता का आनंद उठाता है। कुछ सीएआर राज्यों में सांप्रदायिक जनसांख्यिकी जैसे कि अज़रबैजान ईरान (चित्र IX) का पक्षधर है। उत्तर और पश्चिम दोनों ईरान में अब शिया नृजातियों द्वारा बचाव किया जाता है। इसके आगे यूएसएसआर विघटन और इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने से ईरान दोनों मोर्चों के लिए सुरक्षित हो गया है , जबकि पहले यह शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों के बीच दुश्मनी के कारण भौगोलिक रूप से दबकर सैंडविच के जैसा हो चुका था। 1979 की ईरानी क्रांति के पश्चात अमेरिका ने अपने तथा-कथित द्विपदीय (ईरान और सऊदी अरब) मिडिल ईस्ट नीति के साथ ईरान में अपने पैठ खो दी। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने सऊदी अरब और इजराइल पर अधिक गंभीरता से ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया। ईरानी क्रांति के चरम पर खाड़ी के राजा इस विचारधारा के प्रचार से भयभीत हो गये और चुपके से

इजराइल के नजदीक आ गए। इस दिशा में कतार की चाल कुछ समय के लिए अधिक स्पष्ट थी।

ईरान: मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नाजुक हालातों से लाभ प्राप्त

दो खाड़ी युद्धों तथा चारों ओर आतंकवाद के विरुद्ध तथा कथित तथा-कथित युद्ध प्रारंभ करने की दो दशक लंबी अमेरिकी संलिप्तता ने ईरान को अपनी परमाणु क्षमता को प्रारंभ व विकसित करने का पर्याप्त समय दे दिया। चूंकि ईरान परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है तो इसने संभवतः अपने सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी परमाणु सुविधाओं का विस्तार किया और दुनिया को अपने नागरिक परमाणु कार्यसूची के विषय में सफलतापूर्वक गुमराह किया।

चित्र IX. अरब खाड़ी की जनसांख्यिकी की सांप्रदायिक संरचना



स्रोत: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5223210.stm

नोट: लेखक द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं।

उसी समय, ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम, विशेष रूप से लंबी दूरी की कवरेज पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा था। ईरान का पी 1 तथा पी2 कार्यक्रम, जो साइमन हैंडरसन के अनुसार शुरू में पाकिस्तान -1 और -2 को दर्शाता था बाद में फारसी -1 और -2 में बदल गया। इन्हें उत्तरी कोरिया की नोडोंग मिसाइल जो 1000 किमी तक परमाणु विस्फोटक का भार ले जाने में सक्षम है पर आधारित लंबी दूरी की शहाब मिसाइल विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया था। धीरे-धीरे, ईरान ने शाहब श्रृंखला की बैलिस्टिक क्षमता को 150 मील से बढ़ाकर 1200 मील तक कर दिया है।

तालिका 7: ईरानी राकेट और मिसाइलें

मिसाइलें	रूपांतर	ईंधन प्रकार	अनुमानित रेंज (किमी)	विस्फोटक वहन क्षमता

				(kg)
फाजर-3	डॉन	ठोस	45	45
फाजर-5		ठोस	75	90
फतेह-110	विक्टोरियस	ठोस	20	500
घाडर-1	पावरफुल	तरल	1600	750
ईरान- 130/नाजीट	रिमूवल	ठोस	90-120	150
ख-55	-	तरल	2500- 3000	400-450
नाजीट-6		ठोस	100	150
नाजीट-10		ठोस	140- 150	250
ओघब	ईगल	ठोस	40	70
सज्जील-2	बेक्ड कले	ठोस	2200- 2400	750

शाहाब-1	मेटेओर	तरल	300	1000
शाहाब-2		तरल	500	730
शाहाब-3		तरल	800- 1000	760-100
शाहीन-1	हाँक	ठोस	13	-
शाहीन-2		ठोस	20	-
जेलजल-1	अर्थक्वेक	ठोस	125	600
जेलजल-2		ठोस	200	600

स्रोत: आईआईएसएस, ईरान की मिसाइल क्षमताएं : एक स्पष्ट आकलन, 2010

तालिका 7 विभिन्न ईरानी मिसाइलों की रेंज, उनके भार वहन क्षमता तथा उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले ईंधन के प्रकार के विषय में बताती है। शाहब श्रंखला की मिसाइलें इजराइल तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से खाड़ी क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में लक्ष्य को भेद सकती हैं।

सीरिया: खाड़ी क्षेत्र की शक्तिशाली राजनीति का केंद्र

सीरिया की भू-रणनीतिक स्थिति अरब खाड़ी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसे इसके ईरान, लेबनान और दो अन्य शक्तिशाली असंममित ताकतों हमास और हिजबुल्लाह के साथ पिलिस्तीन के कारण की वजह से और अधिक दीर्घ-कालिक सहयोग के लिए परिवर्धित किया गया। सीरिया में सुन्नी बहुल आबादी (74 प्रतिशत) और 5 प्रतिशत से कम शिया हैं ; बाकी अलवीस (5-6 प्रतिशत), ईसाई और डूज़ (तालिका 8) हैं। यह राजनीतिक विचारधारा के साथ-साथ सांप्रदायिक प्रभुत्व के संदर्भ में दोनों ही मामलों में अरब राज्यों के लिए सीरिया को उनके पक्ष में जीतने

और इराक के नुकसान की भरपाई करने के लिए काफी अच्छा मामला बनाता है। सीरिया, अरब की दुनिया में बैथिस्ट विचारधारा का अंतिम गढ़ है। सुन्नी बहुमत पर अल्पसंख्यक अलावी शासन कर रहे हैं।

तालिका 8: सीरियाई अरब गणराज्य में सांप्रदायिक मोज़ेक

संप्र दाय	हिस्सेदारी का प्रतिशत
सुन्नी मुसलमान	68.7
अलावीस	11.5
ड्रूज	3.0
इस्मेईलिस	1.5
क्रिस्चन	14.1

स्रोत: तारेक वाई. इस्माएल एण्ड जैकलीन

एस. इस्माएल , गवर्नमेंट एण्ड

पालिटिक्स ऑफ दि कंटेपरेरी

मिडिल ईस्ट, राटलेज, लंदन, 2011,

पी. 244

खाड़ी युद्ध के बाद के परिदृश्य में, सीरिया का भू-रणनीतिक महत्व अधिक स्पष्ट हुआ। क्षेत्रीय रूप से , इराक जातीय और सांप्रदायिक धुवीकरण और शिया इराक , सुन्नी इराक और कुर्द इराक में तीन टुकड़ों में बटने के कगार पर है। सद्दाम युग के बाद, सीरिया इस क्षेत्र में एक सांप्रदायिक लाभ को लेकर इस क्षेत्र में एक भू-राजनीतिक ताकत बन गया है। सुन्नी निवासी जॉर्डन और सीरिया सीमा के समीपवर्ती हैं जबकि कुर्द अधिकतर सीरिया और पूर्वी ईरान सीमाओं पर बस चुके हैं। शिया-बहुल इराकी क्षेत्र पूर्वी ईरानी सीमा पर है , जो ईरान को इस क्षेत्र (चित्र X) में एक आसान अंतरराष्ट्रीय अन्यान्यक्रिया प्रदान करता है। इराक , में इस भू-जातीय-संप्रदाय की स्थापना में सीरिया और जॉर्डन सुन्नी अरब की खाड़ी क्षेत्र की वर्तमान भू-सामरिक डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जॉर्डन को पहले ही जीसीसी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा चुका है , जबकि सीरिया के बाहर अल-असद पर अरब स्प्रिंग के नाम पर इसे त्यागने का दबाव है। खाड़ी के नये समीकरण दो उद्देश्यो: *पहला*, इरान को और उसकी

परमाणु इच्छा को शांत करना ; दूसरा, मूल सुन्नी देशों के चारों ओर एक दीर्घकालिक सुन्नी सुरक्षा दीवार स्थापित करने, की पूर्ति करना है। इन क्षेत्रीय व्यवस्थाओं से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल तेहरान-बगदाद धुरी के बीच मध्यवर्ती देशों का निर्माण होगा।

सीरिया की हानि इरान को कैसे प्रभावित करेगी

ईरान के विशेषज्ञ करीम सदजादपुर का कहना है कि “अगर सीरिया की सरकार गिरने वाली होती तो यह ईरानी साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा धक्का होता ”। ईरान प्रथम स्थान से अलग-थलग हो जाएगा; और यह संयुक्त दबाव के साथ-साथ अरबों के साथ एक संभावित सीमित युद्ध लड़ने वाला भी अकेला देश होगा। सीरिया ईरान का मुख्य मंच रहा है , जहाँ से इसने लेबनान में हिज़्बुल्लाह की स्थापना और गाजा में हमास का समर्थन करते हुए अरब-इज़राइल के युद्ध पर भारी प्रभाव डाला है।

चित्र X. सीरिया का सामरिक महत्व और
इराक में जातीय-धार्मिक बस्तियां



स्रोत:

[http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=](http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5052090)

[5052090](http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5052090); कांग्रेस के लिए सीआरएस रिपोर्ट RL: 33487,

http://assets.opencrs.com/rpts/RL33487_20110428.pdf

f.

नोट: तुलना के लिए दो आंकड़े अलग-अलग दिए गए हैं।

ईरान का असममित प्रभाव भूमध्य सागर से लेकर अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से आगे खाड़ी तक और मध्य एशिया के कुछ इलाकों तक फैल जाएगा। दरअसल, सीरिया और ईरान पिछले तीन दशकों से "हथियारों में भाई" रहे हैं। वे "एक रणनीतिक , सामर्थ्य-गुणक गठबंधन" में स्थापित हो चुके हैं।

राजनीतिक रूप से, सीरिया इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है: यह क्षेत्र में शिया और सुन्नी के सांप्रदायिक विभाजन को दागदार करता है और संभावित रूप से फिलिस्तीनी कारण को प्रभावी बैकअप प्रदान करके अखिल-अरबवाद की भावनाओं को उकसाता है।

इसके अलावा, सीरिया ईरान को अरबों को आम मुद्दों जैसे कि इराक और क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति का विरोध करने, पिलिस्तीन के मुद्दे तथा इजराइल की भूमिका और पूरे मुस्लिम समाज में नेतृत्व का चुनाव लड़ने जैसे आम मुद्दों को एक साथ करते हुए अपनी “जमीनी राजनीति” को बनाए रखने में मदद करता है। इसने सऊदी अरब को अरब गलियारे को बनाये रखने में मदद की है।

एक बड़े भू-रणनीतिक परिदृश्य पर सीरिया, इजरायल और अमेरिका की संरचना के खिलाफ खड़ा होता है , दागिस्तान में रूसी अलगाववादी आंदोलन के खिलाफ काम करता है और इस क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता का कारण बनता है।

असाद के बगैर, “अमेरिका और इजराइल सीरिया को ईरान के ग्रहपथ (हमास और हिजबुल्लाह जैसे सीरिया प्रायोजित आतंकवादी समूहों) से ” बाहर निकाल लेगा। रूसी दामास्कस में अपने व्यवसाय को बचाने के लिए तथा डागोस्तान पर सीरियाई

गृहयुद्ध के किसी भी प्रभाव को रोकने के लिए असद का बचाव कर रहे हैं। तुर्की ने क्षेत्रीय सत्ता और कूटनीतिक लिनेपिन के रूप में अपनी नई स्थिति को मजबूत करने के लिए , अपने पूर्व सहयोगी, असद को चालू कर दिया है ; और खाड़ी अरब राज्य शिया/अलावी शासन के खिलाफ सुन्नी बहुमत वापस पाना चाहते हैं। रणनीतिक रूप से, एक स्थाई तथा तुर्की-समर्थक क्षेत्र तुर्की को लाभ पहुँचाएगा। तुर्की दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में सीरिया के साथ 800 किमी लंबी सीमारेखा को साझा करता है। तुर्की की संख्या के 18 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले लाखों की संख्या में कुर्दिश आतंकियों के बहुमत सहित सीरिया के साथ एक विवादग्रस्त सीमारेखा ऐतिहासिक रूप से तुर्की को परेशान करती आ रही है ; जब भी तुर्की ने उसे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध जाते हुए पाया है तो सीरिया में एक तुर्क-विरोधी क्षेत्र ने कभी भी इस “भू-राजनीतिक घाटे” का दुरुपयोग करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है।

वाल स्ट्रीट जरनल को दिए गए अपने साक्षात्कार में पेरिस-निवासी सीरियाई राष्ट्रीय परिषद के नेता बुरहान घालिओन ने कहा कि

सीरिया और ईरान के बीच मौजूदा संबंध असामान्य..... है [इन] पर पुनः विचार किया जाएगा। ईरान के साथ कोई विशेष संबंध नहीं रहेगा। यह सेना सहयोग का मूल मुद्दा है। असाधारण रिश्ते को तोड़ने का अर्थ रणनीतिक सैन्य गठबंधन को तोड़ना है। हम आर्थिक संबंधों को बुरा नहीं मानते हैं।

असद-पश्च संभावित युग में , लेबनान, हिज़बुल्लाह और हमास के साथ सीरिया के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। बुरहान घालिओन के अनुसार, “लेबनान के साथ हमारा संबंध सहयोग का होगा तथा आपसी मान्यता और हितों के आदान-प्रदान और क्षेत्र में स्थिरता में सुधार के लिए मांग करने का होगा ”। उन्होंने कहा कि “सीरिया शासन के पतन के साथ ही हिजबुल्लाह

पहले जैसा नहीं रहेगा। लेबनान का उपयोग उस तरह का नहीं होना चाहिए जैसा इसका उपयोग असद युग में राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हुआ था ”। करीम सजदापुर के अनुसार,

सीरिया न केवल ईरान का मुख्य क्षेत्रीय सहयोगी है बल्कि सीरिया वह देश है जो ईरान को मध्य पूर्व में अपने “सिरताज का रत्न ”, लेबनान के हिज़बुल्लाह आंदोलन की आपूर्ति करने की भी अनुमति देता है। लेबनान में हिज़बुल्लाह ईरानी क्रांति का सिरताज का रत्न है और सीरिया ईरान के संरक्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। अगर असद शासन को गिरना होता तो ये तार्किक रूप से बहुत अलग होगा कि ईरान, हिजबुल्लाह का उसी तरह से समर्थन जारी रखे जिस तरह से पिछले कुछ दशकों में यह रहा है।

असद शासन का पतन हमास को भी प्रभावित करेगा। हमास

सुन्नी अरब की ओर जा सकता है, जो अंततः अरब खाड़ी में ईरान की भू-रणनीतिक और वैचारिक आधार को प्रभावित करेगा।
बुरहान घालिओन के अनुसार,

हमास एक नई नीति में बदल गया है और वे अब फिलीस्तीन के सिपाहियों को एकजुट करने के लिए पीएलओ के साथ काम कर रहे हैं। यह अब सीरियाई शासन द्वारा समर्थित हमास नहीं रह गया है। हमास के साथ हमारा संबंध राजनीतिक रूप से पीएलओ और फिलिस्तीनी नागरिक समाज के साथ हमारे संबंधों के माध्यम से होगा।

असद के बाद के दावेदारों ने अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए पर्याप्त झुकाव दिखाया है। वे आर्थिक , राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अरब दुनिया के साथ सीरिया को एकीकृत करने का इरादा रखते हैं। अपने साक्षात्कार में बुरहान ग़ालिओन ने कहा कि:

एक नया सीरिया अरब लीग का एक अभिन्न हिस्सा होगा और यह अरब लीग की भूमिका और अरब राज्यों की भूमिका को क्षेत्रीय रूप से सुधारने पर काम करेगा , विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने सीरिया के लोगों का समर्थन करने के

लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय लिया। सीरिया अरब गोलार्ध का केंद्र है। यह अरब प्रायद्वीप , खाड़ी देशों, मिस्र और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों के बाहर नहीं रह सकता है। हमें भविष्य में अपने साथी अरबों से आर्थिक और निवेश समर्थन की आवश्यकता है। हमारा भविष्य वास्तव में अरब दुनिया और विशेष रूप से खाड़ी से जुड़ा हुआ है। भविष्य में हमें सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक समर्थनों की आवश्यकता होगी

यह स्पष्ट है कि यदि अस्साद शासन का पतन होता है तो नए राजनीतिक समीकरण क्षेत्रीय परिदृश्यों को रूपांतरित करेंगे और इरान को उसी के अनुसार समायोजन करना पड़ेगा। अधिकतर लोगों का विचार है कि अस्साद शासन अगले छह से आठ महीनों में ढह जाएगा लेकिन इस समस्या के निदान के भी कारण मौजूद हैं। अलग भू-राजनीतिक तथा भू-रणनीतिक परिदृश्यों के कारण सीरिया, लीबिया से बिल्कुल अलग है। लीबिया एक वियुक्त

मामला था और इसका अरब खाड़ी राजनीति पर न्यूनतम निहितार्थ था जबकि सीरिया क्षेत्रीय राजनीति से एकीकृत है। सीरिया दो असममित शक्तियों हेजबुल्लाह और आशिक रूप से हमास का समर्थन करता है तथा ईराक और यमन को सहानुभूति प्रदान करता है। इन भू-राजनीतिक समीकरणों ने संबद्ध शक्तियों को “सैन्य विकल्प” को लंबित रखने तथा अरब लीग के माध्यम से कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करने पर मजबूर कर दिया है; लेकिन जार्डन, अल्जीरिया तथा कुछ अन्य देश इस कदम से सहमत नहीं हुए। बढ़ते आर्थिक अलगाव के बीच, ईरान तथा सीरिया ने एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हस्ताक्षरित किया है और द्विपक्षीय आर्थिक लेनदेनों को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। ईरान ने अपने व्यापारी समुदाय को सीरिया में निवास करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया है। इन दो देशों ने सहयोग के चार स्तंभों नामतः अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और आवास को निर्धारित किया है। अनुमान है कि एफटीए 400 मिलियन डॉलर के व्यापारिक विनिमय से 2 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है।

क्रिस्टल बाल पर टकटकी ।

जैसा कि पहले चर्चा की गई थी कि जातीय, संप्रदायवादी, सैन्य और रणनीतिक गतिशीलता, सीरिया को दो क्षेत्रीय शक्तियों यथा ईरान के इस्लामी गणराज्य और सऊदी अरब के साम्राज्य में परिवर्तित कर देगी। यह भी अनुमान है कि इजराइल, इराक तथा संभवतः पिलिस्तीन, तुर्की और अन्य खाड़ी राज्य जैसे कि ओमान और कतर जैसे मुख्य प्लेयर भी अपने दीर्घकालिक हित तथा धार्मिक और सांप्रदायिक प्राथमिकताओं के कारण उनका पक्ष ले सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्णरूप से मीडिया इस घटना को इस क्षेत्र में विकसित सुरक्षा अनिवार्यताओं के लिए एक प्रमुख बदलाव और इसके निहितार्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा होगा। अस्साद शासन के पतन की स्थिति में निम्न में से कुछ लघु-से-मध्य पदों की परिस्थितियों के इस क्षेत्र में उभरने के आसार हैं।

परिदृश्य /

मुख्य-परिधि परिकल्पना: खाड़ी सुरक्षा मंच का विकास (जीएसएफ)

सीरियाई अरब गणराज्य को अरब खाड़ी क्षेत्र में कथित भू-रणनीतिक असंतुलन को ठीक करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक और पहले कदम के रूप में माना गया है। यह क्षेत्र में उभरती हुई नकारात्मक गतिशीलता जैसे ईरान का परमाणु की ओर जाने , को स्थगित करने में मदद कर सकता है , लेकिन समस्याओं को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता है। सीरिया इस क्षेत्र में शक्ति के लंबे समय तक संतुलन बनाए रखने का समाधान नहीं हो सकता है। ईरान को अन्य जातीय रूप से कृपापात्र राष्ट्रों के साथ गठबंधन में भू-रणनीतिक लाभ प्राप्त हैं और अवसर मिलते ही यह आसानी से इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्मित ढांचे को नष्ट कर सकता है , जैसा कि प्रथम खाड़ी युद्ध के युग के बाद हुआ था। सुन्नी देश इस क्षेत्र में शिया समुदाय के

जनसांख्यिकीय प्रभुत्व को नष्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए वे धीरे-धीरे अरब खाड़ी सुरक्षा ढांचे में अन्य सुन्नी-बहुसंख्यक देशों के लिए रास्ता बना रहे हैं, जो कि जातीय रूप से असंतुलित खाड़ी के साथ ईरान और इसके सहयोगियों को असंतुलित करने के लिए , सुन्नी-बहुल परिधीय देशों को शामिल करते हुए जीसीसी सुरक्षा ढांचे को निर्मित किया गया प्रतीत होता है। यह मई 2011 में जीसीसी की वार्षिक बैठक की कार्यवाही से भी स्पष्ट है , जिसमें मोरक्को और जॉर्डन , दोनों सुन्नी-बहुमत वाले राज्यों को जीसीसी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

मध्यकाल में , यह उम्मीद की जाती है कि अरब खाड़ी क्षेत्र सुन्नी कोर-परिधि संबंध की अवधारणा को विकसित और मजबूत करके ईरान के संभावित भू-राजनीतिक या भू-संप्रदाय लाभ को कम करने में सफल होगा। यह स्वयंमेव रूप से अरब खाड़ी सुरक्षा ढांचे में सुन्नी-बहुसंख्यक आबादी के साथ अधिक परिधीय राष्ट्रों को शामिल करेगा। इसे खाड़ी सुरक्षा के ढांचों में अधिक सुन्नी-बहुमत वाले राष्ट्रों को शामिल करते हुए आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ)

की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है। सांख्यिकीय तौर पर हालांकि अरब खाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या का 60 प्रतिशत शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा चार देशों-ईरान, इराक, बहरीन तथा अजर्बैजान - समेकित रूप से ये विश्व के पचास के अधिक देशों में रह रही विश्व की मुस्लिम आबादी, लगभग 1.57 बिलियन के 10-15 प्रतिशत (लगभग 154-200 मिलियन) में ये बहुसंख्यक हैं। इस क्षेत्र में ईरान द्वारा उपयोग किये गए भू-संप्रदायिक लाभों को आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) की तर्ज पर खाड़ी सुरक्षा मंच या जीसीसी सुरक्षा मंच (जीएसएफ) की अवधारणा को स्थापित करने और बढ़ावा देने से हमेशा के लिए कमजोर कर दिया जाएगा।

जीएसएफ में लीबिया, ट्यूनीशिया, सूडान, मॉरीशस, सोमाली तथा लाल सागर के चारों ओर अरब संघ को शामिल किया जाना है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे कि पाकिस्तान , बांग्लादेश और अफगानिस्तान तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई को सक्रिय सलाहकार पदों, विशेष

रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बातचीत के भागीदार के रूप में समायोजित किया जा सकता है। कतर अफगानिस्तान में एक दूतावास खोलने पर विचार कर रहा है। इसका तात्पर्य क्षेत्र में ईरान के व्यापक प्रभाव को कम करने से है। जीएसएफ में पाकिस्तान और तुर्की की संभावित भूमिका होगी और उनकी रणनीतिक गहराई में और वृद्धि होगी।

अपनी संप्रदाय रचना के आधार पर तालिका 9 में जीएसएफ के सदस्य की उम्मीदवारी रखने वाले निम्नलिखित संभावित देशों का प्रस्ताव है। इन देशों को तीन समूहों- मुख्य समूह , परिधीय समूह और एक्सटेंडेड कैचमेंट समूह में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य समूह में मुख्य रूप से अरब की खाड़ी और लेवंत देश शामिल हैं। हालांकि , जनसांख्यिकीय रूप से मुख्य समूह जाहिर तौर पर इस क्षेत्र में ईरान द्वारा उपभोग किए गए सांप्रदायिक लाभों पर काबू पाने में असमर्थ है। इस मामले में परिधीय समूह से तात्पर्य में परिधीय समूह को जीएसएफ में शामिल करना प्रभावपूर्ण ढंग से ईरान के सांप्रदायिक

लाभों का प्रतिरोध करने से है चूंकि यह समूह प्रबलरूप से सुन्नी प्रभावी देशों जैसे कि मिश्र, तुर्की, नाइजीरिया, आदि को शामिल करता है। एक्सटेंडेड कैचमेंट ग्रुप (ईसीजी) के अधीन वर्गीकृत अन्य मुस्लिम बहुसंख्यक देशों का समावेश सऊदी अरब और अन्य सुन्नी खाड़ी राज्यों को इस्लाम की पूरी सुन्नी दुनिया को एकजुट करने में मदद देगा और धीरे-धीरे मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व के ईरानी दावे को कम करेगा। यदि जीएसएफ की अवधारणा प्रचलन में आती है तो यह सुन्नी अरब खाड़ी देशों को मुख्य रूप से सऊदी अरब को न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा समस्याओं का प्रबंधन करने में जिसमें संप्रदाय भी शामिल हैं, बल्कि उन्हें एक गहन और व्यापक 'रणनीतिक' नेटवर्क का पोषण करने में सक्षम करेगी जो इस क्षेत्र में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की तुलना में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

चित्र XI इस्लामी बहुलता में शिया आबादी के अनुपात को दर्शाता है। ईरान और बहरीन में, शिया आबादी का प्रतिशत 75-95 प्रतिशत के बीच है; इराक और अजरबैजान में, 50-75 प्रतिशत; और तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 25-50 प्रतिशत है।

स्पष्टतया, इन देशों में गैर-शिया देशों की तुलना में ईरान का वैचारिक प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होगा। समेकित रूप से 154-200 मिलियन की वैश्विक शिया आबादी की लगभग 37-40 प्रतिशत आबादी इन चार देशों अर्थात् ईरान , पाकिस्तान, भारत और इराक में निवास करती हैं।

तालिका 9: पश्चिमी एशिया में जातीय असंतुलन

के संतुलन की प्रमुख-परिधि परिकल्पना

देश	कुल आबादी (मिलिय न)	शिया आबादी (%)	देश	कुल आबादी (मिलिय न)	शिया आबादी (%)
मुख्य देश			परिधीय देश		
बहरीन	1.2	70-75	इजराइल	7.418	<1
इरान	73.9	90-95	अल्जीरि या	35.4	<4
ईराक	31.6	65-60	अल्बानि या	3.204	<5
कुवैत	2.7	20-25	कोमोरोस	7.35	1

लेबनान	3.0	45-55	जिबोती	0.889	1
ओमान	2.7	5-10	मिश्र	81.1	<1
कतर	1.7	10	लीबिया	6.355	1
सऊदी अरब	27.4	11-15	मर्तानिया	3.4	1
यूएई	4.0	10	मोरक्को	0.31.9	3
यमन	24.0	35-40	सोमाली	9.0	1
सीरिया*	23.0	15-20	सूडान	43.5	2
जार्डन	6.1	<1	ट्यूनीशि या	10.48 1	<1
फिलिस्ती न	4.0	<1	नाइजीरि या	78.0	5
			इथोपि या गणरा	28.0	<1

			ज्य		
			तुर्की	74.0	10-15
			नाइजर	15.0	
जीएसएफ का एक्सटेंडेड कैचमेंट ग्रुप (ईसीजी)					
अफगानिस्तान	3.3	10-15 (20)	बांग्लादेश	145	<1
पाकिस्तान	173.5	10-15 (20)	इंडोनेशिया	230	<1
मालदीव	.0316	1	मलेशिया	17.0	2
भारत	161	20	ब्रूनेई	0.039	1

स्रोत: वैश्विक मुस्लिम आबादी का प्रतिचित्रण (2009), पीव शोध

केंद्र, पृष्ठ. 39-41,

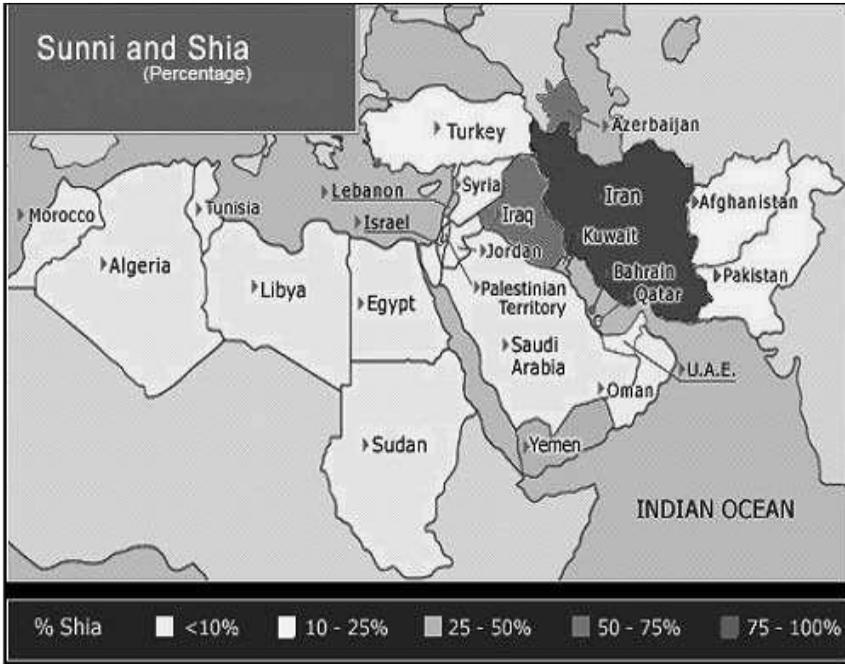
http://pewforum.org/uploadedfiles/Orphan_Migrated

[_Content/Muslimpopulation.pdf](#);

नोट: कुछ आंकड़े लेखक द्वारा स्वयं समाहित किए गए हैं।

सीरिया के आँकड़े हैं 15-19 अक्टूबर 2011 में लेखक के द्वारा की गई सीरिया की यात्रा के दौरान लेखक द्वारा लिए गए।

चित्र XI. अरब और इस्लाम बहुल देशों में शिया-



सुन्नी बटवारा

स्रोत: करबला के लिए धार्मिक यात्रा: शिया और सुन्नी इस्लाम का

संसार,

<http://www.pbs.org/>

[wnet/wideangle/episodes/pilgrimage-to-](http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/pilgrimage-to-)

[karbala/sunni-and-shia-the-worlds-of-islam/1737/.](http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/pilgrimage-to-karbala/sunni-and-shia-the-worlds-of-islam/1737/)

परिदृश्य //

**संयुक्त राज्य अमेरिका: मिडिल ईस्ट में एक जबरदस्त परिवर्तन
कूटनीति - कट्टरपंथियों की सहायता**

लीबिया, सीरिया जैसे कुछ अरब राज्यों में अरब वसंत के नाम पर अमेरिका/पश्चिम द्वारा इंजीनियरिंग शासन में हाल ही में बदलाव आया है। यह शायद निम्नलिखित कारणों में से कुछ के लिए है:

- टकराव की सभ्यताओं की परिकल्पना के आधार पर दो दशकों से चली आ रही मुस्लिम परस्त नीतियों ने मुस्लिम देशों में अमेरिका/पश्चिम की विश्वसनीयता को काफी कम किया है। नतीजतन, इन शक्तियों ने विशेष रूप से दुनिया भर के अधिकांश मुस्लिम देशों में और विशेष रूप से मुस्लिम जनता के बीच बहुत रणनीतिक पकड़ खो दी है। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अनुकूल विकास नहीं है, खासकर मध्यम गति में। अमेरिका/पश्चिम को मुस्लिम देशों के समर्थन की आवश्यकता है खासकर भविष्य में दो वस्तुओं की प्राप्ति हेतु। पहला चीन को रोकने के लिए और दूसरा वर्तमान मंदी से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को निकालन के लिए। तेल समृद्ध देश विभिन्न तरीकों से अपनी अर्थव्यवस्थाओं की सेवा कर रहे हैं। तेल राजशाहों ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में अपनी बहुत संपत्ति जमा की हुई है। अनुमान है कि गद्दाफी का 150 बिलियन डॉलर से अधिक का धन

अमेरिका और अन्य पश्चिमी बैंकों में जमा किया गया है ;
सऊदी अरब ने अमेरिकी बैंकों में 700 बिलियन डॉलर जमा
किए हुए हैं। उनकी विशाल क्रय शक्ति के आधार पर ,
परिवर्तनशील-आय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर खाड़ी बाजार
से यूएस/पश्चिम में व्यापार होने के साथ-साथ जीसीसी देशों
को भी पश्चिमी बाजार के साथ अच्छी तरह से एकीकृत
किया गया है। ये देश खाड़ी की सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा
की आपूर्ति भी प्राप्त कर रहे हैं। खाड़ी-जनित ऊर्जा स्रोतों
पर 'शून्य निर्भरता' हासिल करने के बुश प्रशासन के सभी
प्रयासों के बावजूद भी संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी
खाड़ी क्षेत्र से अपने तेल की मांग का 10 प्रतिशत प्राप्त
कर रहा है। तेल उत्पादक देशों के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में तेल
और तेल से संबंधित उपकरणों और सेवाओं का निर्यात
पश्चिमी/अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में एक और महत्वपूर्ण
योगदान है। इसके अलावा , खाड़ी क्षेत्र, विशेष रूप से
सेवानिवृत्त नागरिकों और पश्चिम से सशस्त्र कर्मियों को

बहुत अधिक पारिश्रमिक पर सलाहकार के रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

- अमेरिका और अन्यो ने इस्लामवादियों के प्रति अपने रुख में नरमी दिखाई है। यह पाकिस्तान में एबटाबाद के ऑपरेशन बाद से अधिक स्पष्ट हुआ है। अमेरिका अब “मिशन प्राप्त” का एक स्पष्ट संकेत भेजना चाहता है कि अब “आतंक पर युद्ध” ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का कोई तर्क नहीं है। अमेरिका ने अन्य देशों को अफगानिस्तान के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, विशेष रूप से प्रशिक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को अपने सुरक्षा रोजगारों को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। ट्यूनीशिया के चुनाव परिणाम स्पष्ट संकेत देते हैं कि पूर्व में प्रतिबंधित मुस्लिम भाईचारे के क्षेत्र में बेदखल तानाशाहों के उदारवादी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरने की संभावना है। अमेरिका और उसके सहयोगी बंदूक उछालने और उन्हें अवैध घोषित करने के बजाय प्रतीक्षा करो और

देखो की नीति पर काम करना चाहते हैं। मुसलमानों के उन वर्गों को जिन्हें दो दशक पहले संभावित आतंकवादियों के रूप में लक्षित किया गया था , उन्हें अब स्वयं कुछ अरब देशों से शासन परिवर्तन के लिए समर्थन मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर , सीरिया में धर्मनिरपेक्ष शासन को कट्टरपंथियों द्वारा धमकी दी जा रही है शायद सलाइस्ट्स को। इसी प्रकार , लीबिया में , एक समय सक्रिय रहे अलकायदा को अनुदान प्रदान और शायद अफगानिस्तान में प्रशिक्षित नाटो बलों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित किया जाता था। कतर ने उनका धन , हथियार, प्रशिक्षण आदि के साथ सक्रिय रूप से समर्थन किया है। हालांकि कुछ पश्चिमी मीडिया ने *अल जज़ीरा*, कतर स्थित इलेक्ट्रॉनिक चैनल की संदिग्ध भूमिका के बारे में स्वयं को व्यक्त किया है फिर भी कट्टर सुन्नी इस्लामवादियों को बढ़ावा देने के लिए, चैनल को अधिकारियों द्वारा खुले दिल से स्वीकार किया गया है।

- बाली में हाल ही में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान , अमेरिका ने पर्याप्त साक्ष्य दिए हैं कि अब उसका ध्यान मध्य पूर्व से एशिया-पैसिफिक में स्थानांतरित हो गया है , जिसमें दक्षिण चीन सागर भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि और डार्विन और केन्स में दो नौसैनिक अड्डों को प्राप्त करने के साथ साथ इसकी घोषणा कि यह म्यांमार के साथ समझौता करने की कोशिश करेगा , यह दर्शाता है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व और अफगानिस्तान से अपना ध्यान दुनिया के इस हिस्से में स्थानांतरित कर दिया है। ईरान को छोड़कर, मध्य पूर्व अब संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख चिंता नहीं है , जो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए छोड़ दिया गया है। ओबामा प्रशासन ने पहले ही 21 वीं सदी को “एशिया-पैसिफिक की सदी” घोषित कर दिया है।
- पूर्वगामी विश्लेषण से , यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि सीरिया में शासन - जो कि आगे यमन के राष्ट्रपति सालेह

के इस्तीफे से और कमजोर हो गया है, जिसने संघ की सदस्यता से सीरिया को निष्कासित करने के उद्देश्य से अरब संघ के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था - ध्वस्त होता है तो, और सुन्नी सलामी अपने पक्ष में हमास को जीतने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो , तत्काल संभावित परिणाम यह है कि ईरान को अपने संदिग्ध परमाणु सैन्यकरण को स्थगित करना पड़ सकता है। यदि इरान दृढ़ रहता है जैसा कि राष्ट्रपति अहमदीनेजाद सूचित करते हैं तो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक को शामिल करते हुए या तो कई और व्यापक चौथे चरण की मंजूरी के तौर पर इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है अथवा यह आने वाले कुछ दशकों के लिए अपनी शक्ति या संभवतः एक शासन परिवर्तन को अपंग करने की कार्यसूची के साथ युद्ध का सामना करेगा। इस बार तेल निर्यात करने वाले खाड़ी देशों ने प्रतिबंधों को प्रभावी बनाने के लिए नेतृत्व किया हो सकता है: वे तेल आयात करने

वाले गैर-पालक देशों पर दबाव बनाने के लिए तेल को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वे प्रतिबंधों के साथ सहयोग के लिए सुरक्षा की अपनी वास्तविक चिंता और क्षेत्र में परमाणु प्रसार के खतरे को सामने रख सकते हैं। सऊदी प्रिंस फैसल अलतुर्की ने आरएएफ मोल्सवर्थ में एक सभा में कहा, ब्रिटेन में अमेरिकी बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए ठिकानों में से एक ईरान में “स्टील क्लॉव” थे, जो अन्य देशों में हस्तक्षेप करने के लिए "प्रभावी उपकरण" थे। उन्होंने कहा कि “ईरान [विकासशील] एक परमाणु हथियार सऊदी अरब को मजबूर करेगा ... जो नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए अनकहे और संभवतः नाटकीय परिणाम पैदा कर सकता है”।

- इराक के प्रति अमेरिकी नीतियों में आया बदलाव खुले दिल से अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब अमेरिका इराक के शियाओं और कुर्दों को इराक में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अधिक इच्छुक है। अपने संबंधित हितों के लिए सऊदी

अरब और ईरान का बढ़ता हस्तक्षेप जाहिर तौर पर इराकियों को परेशान करेगा ; 2006-8 के दौरान , इराक में बड़े सांप्रदायिक नरसंहार हुए थे। अब इराकवासी शांति के पूर्णरूपेण आशातीत हैं। अमेरिका कूटनीति और ऊर्जा दोनों के लिहाज से इराक को मुआवजे के रूप में या ईरान खिलाफ लड़ाई की उम्मीद रखता है। सऊदी अरब के बाद दुनिया में तेल जमा करने वालों में इराक दूसरे नंबर पर है। इराकी तेल अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऊर्जा की कम आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करेगा।

- राजनीतिक रूप से अमेरिका के लिए नये इराक की कल्पना ईरान के एक विकल्प और मुआवजे के रूप में की गई है। यह अमेरिका को अपनी “जुड़वां स्तंभ मध्य पूर्व” नीति को बनाए रखने में मदद करेगा। इस खेल में , सऊदी अरब की स्थिति कम सुरक्षित है। अगर इस क्षेत्र में लोकतंत्र का पालन होता है , तो सऊदी अरब को उस देश में अपनी बहरीन नीति और उसके बड़े दांव पर पुनर्विचार करना

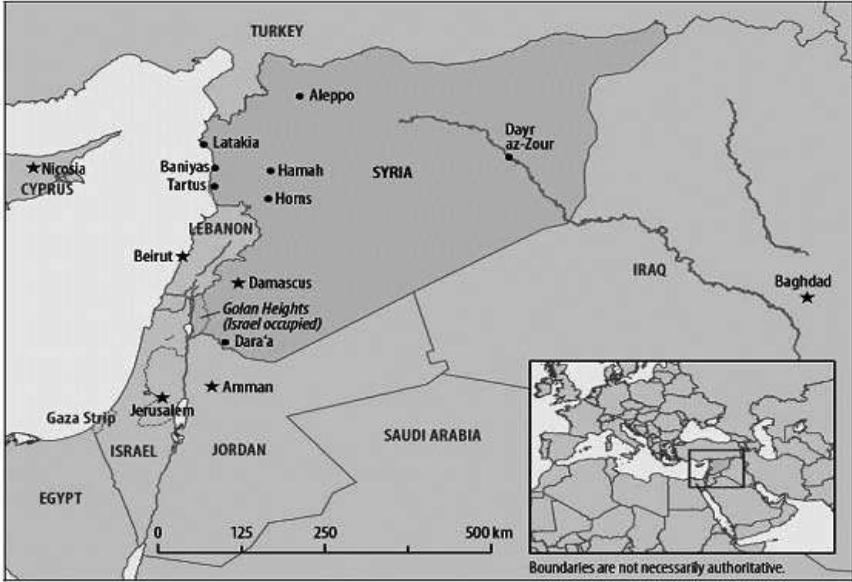
होगा।

- इस मोड़ पर अमेरिका का एक और महत्वपूर्ण नीतिगत अवसरवाद क्षेत्र में रूस की उपस्थिति को और कम करना देखा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति और सद्दाम हुसैन के निधन के बाद रूसी उपस्थिति , एक नादिर में है ; इस क्षेत्र में अमेरिका द्वारा पैदा किया गया अत्याचार , गड़बड़ी और अस्थिरता , विशेष रूप से इराक (2003) में युद्ध शुरू करने के बाद से, अमेरिका की विश्वसनीयता में कमी आई है। इन परिस्थितियों में अमेरिका व इसके सहयोगियों के पास रूस को इसके पिछले गढ़ जो कि. सीरिया, भू-रणनीतिक रूप से, हालांकि, सीरिया रूस के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है विशेषरूप से इन कारणों के लिए (i) भूमध्य सागर में सीरिया के पोर्ट टार्टस रूस को गर्म पानी प्रदान करता है, से बाहर फेंकने का एजेंडा हो सकता है। वर्तमान शासन में कोई भी हानि निश्चितरूप से सीरिया में रूसी प्रभाव को कम करेगी (तालिका XII)। (ii) भौगोलिक

तौर पर, सीरिया सीधे अरब दुनिया को रूस के अशांत क्षेत्रों जैसे दागिस्तान , चेचन्या आदि से जोड़ता है। सीरिया में कोई भी प्रतिकूल शासन परिवर्तन इस्लामवादियों को रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का रास्ता दे सकता है और वहां के अलगाववादी आंदोलन को तेज कर सकता है। अमेरिका इसे रूस के साथ “लेना और देना” कार्यक्रम के रूप में उपयोग कर सकता है और वे ईरान और इसकी बढ़ती क्षेत्रीय क्षमता पर एक राय बना सकते हैं। हालांकि , रूसी समाचार एजेंसी इज़वेस्टिया , नई दिल्ली के वरिष्ठ संवाददाता और ब्यूरो चीफ , एलेक्सी बेव , यह दृष्टिकोण रखते हैं कि इस्लामवादी भूमध्यसागरीय को पार करने और रूस के अशांत क्षेत्र में घुसपैठ करने में सक्षम होंगे। उनका विचार है कि रूस के पास किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए पर्याप्त नौसैनिक क्षमता है। फिर भी , रिकॉर्ड से पता चलता है कि 2007 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने और इन

अलगाववादियों को प्रदान की गई शरण रियाद के मुद्दे को उठाया था। बढ़ते आतंकवादी नेटवर्क के खतरे का मुकाबला करने के लिए दोनों देश एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। (iii) सीरिया रूस का एक बड़ा हथियार बाजार है। बीबीसी के विश्व संवाददाता , रिचर्ड गैल्पिन के अनुसार , “रूस की वैश्विक हथियारों की बिक्री का लगभग 10 प्रतिशत सीरिया में जाता है ”। क्षेत्र में संकट शुरू होने के बाद से , सीरिया ने रूस के साथ 3.5 अरब डॉलर के हथियारों के सौदे का निष्कर्ष निकाला है। हालांकि , एलेक्सी बेव के अनुसार , “रातोंरात हथियारों का सेटअप एक रूप से दूसरे रूप में बदलना संभव नहीं है, शासन परिवर्तन सीरिया में रूसी हित को निश्चितरूप से प्रभावित करेगा , जो रूसी हथियारों के लिए एक बड़ा बाजार प्रदान करता है ”। (iv) सीरिया कम्युनिस्ट/रूसी के पैर जमाने का अंतिम गढ़ है।

चित्र XII. सीरिया की भू-रणनीतिक महत्ता



स्रोत: जेरेमी एम. शार्प तथा क्रिस्टोफर एम. ब्लांचर्ड, अनरेस्ट इन

सीरिया एण्ड यूएस सैंक्शंस अगेन्सट दि असाद रिजीम, सीआरएस

रिपोर्ट, 16 February 2012.

इसलिए अमेरिका और सहयोगी शक्तियां सीरिया में अशांति

का उपयोग रूस को इस क्षेत्र से बाहर करने के अवसर के

रूप में कर रहे हैं शायद आने वाले कई दशकों तक।

हालांकि, 2014 के बाद के परिदृश्य को देखते हुए जो कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी के रूप में चिह्नित है, दक्षिण पश्चिम एशिया में नए सिरे से भू-राजनीतिक पुनर्निर्माण चल रहा है जो ईरान को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय बल के रूप में छोड़ देगा। यह संभवतः ईरान को “युक्त” करने के अमेरिकी प्रयास को कमजोर कर सकता है। जबकि अमेरिका ईरान के प्रति अपनी नीति में हठधर्मी बना हुआ है , चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी से यह खाई स्वतः ही पूरी हो जाएगी जो ईरान को एक मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी में परिवर्तित कर देगी।

सीरियाई प्रभुत्व प्रभाव और इरान के लिए संभावित परिस्थितियां

- सीरिया में बाशेर अल-असद की हार, ईरान के कमजोर होने और लेबनान में उसके प्रतिनिधि हिजबुल्लाह के कारण ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए ईरान में एक प्रकोष्ठ विकसित हो सकता है और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में भी सामंजस्य स्थापित कर सकता है। कुछ समय के लिए शिया बहुल इराक भी उनके प्रभाव में होगा क्योंकि यह ईरान से वैचारिक प्रेरणा लेता है। इस प्रकार, तेहरान-तेल अवीव-बगदाद-वाशिंगटन-एक्सिस के गठन की संभावना है।
- इजरायल और अमेरिका के साथ बेहतर ईरानी संबंध सुन्नी अरब राज्यों पर प्रत्यावर्ती प्रभाव डाल सकते हैं। बाद में , तेहरान-तेल अवीव-वाशिंगटन अक्ष का अगला लक्ष्य वह हो सकता है जिसने ईरान को हराने के लिए कट्टरपंथियों और

सलावादियों का उपयोग किया होगा। इस बार सऊदी अरब ,
तालिबान और दुनिया भर के अन्यों सहित जिहादी विदेश
नीति का वित्तपोषण करने के निमित्त कीमत अदा कर
सकता है। अल-रशीद और शिया-आबादी वाले पूर्वी क्षेत्र
सहित असंतुष्ट खंड, राज्य को भंग कर सकते हैं। एक बार
फिर से यह 1932 से पहले के युग के समान घट सकता
है। इस साम्राज्य से दो पवित्र शहर अलग हो सकते हैं और
विश्वभर के सदस्यों को शामिल करते हुए एक नयी प्रबंधन
समिति का गठन किया जा सकता है। यह तेहरान की एक
लंबे समय से मांग रही है।

- ईरान और सऊदी अरब में मौजूदा साम्राज्य के पतन की परिस्थिति में फिलिस्तीन का वर्तमान कारण हमेशा के लिए लुप्त हो सकता है। फिलिस्तीन खाड़ी देशों पर एक बोझ बन सकता है। इसकी स्थिति “राज्यों बिना देश” जैसी हो जाएगी जो अरबों की भाईचारे की दया पर आश्रित हो कर रह रहा हो। इस स्थिति में, वो वे सब लेंगे जो इजराइल उन्हें दे रहा होगा। वे अपनी सौदेबाजी की ताकत को खो देंगे जिसके लिए वे पिछले सत्तर वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं।
- जैसे ही अरब विश्व में स्थिति स्थायित्व में आती है तो चार क्षेत्रीय शक्तियों - मिश्र, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान के मध्य दुश्मनी उभर सकती है और बढ़ सकती है। इसके परिणामों में निम्न हो सकते हैं : (i) ईरान विश्व की मुस्लिम आबादी के 20 प्रतिशत शिया आबादी का प्रतिनिधि होगा और खाड़ी में इसकी स्थिति 60 प्रतिशत होगी।

(ii) तुर्की खाड़ी के क्षेत्रीय मामलों में दखलअंदाजी करना प्रारंभ कर सकता है जो की स्थायी सभ्रान्तों को पंसद नहीं आएगा, पहले ही ईराकी नेताओं के द्वारा तुर्की पर ईराक के तेल-समृद्ध क्षेत्र में अपना प्रभाव डालने का आरोप लगाया जा चुका है। तुर्की के द्वारा उठाया गया कोई भी गलत कदम इसकी खाड़ी विदेश नीति का प्रति प्रतिकारक हो सकता है। इस क्षेत्र में इसके औसत दर्जे के चेहरे को पहले से ही मुस्लिम भाईचारे के द्वारा शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह तुर्की को आज के हीरो से “कल के मिडिल ईस्ट के बीमार” में बदल सकता है।

(iii) अपना आधार स्थापित करने के बाद, मिश्र विदेश मामलों को गंभीरता से लेने वाला है। होस्नी मुबारक की नीतियों को पुनः विचारित किया जा सकता है। मिश्र अपनी विदेश नीति में सुधार कर सकता है तथा पहले अवसर पर यह संभवतः इजराइल और अमेरिका के साथ अपने संबंध पर पुनर्विचार कर सकता है। यह इजराइल के लिए समस्या

खड़ी कर सकता है जो क्षेत्र में नयी मुठभेड़ को तैयार कर सकता है। यदि ईरान एक परित्यक्त राष्ट्र बना रहता है तो यह एक बार फिर ईरान को मिश्र के नजदीक ला सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार, एक ईरानी जहाज के हाल ही में स्वेज नहर से गुजरना इस संभावना को दर्शाता है। मिश्र में मुस्लिम ब्रदरहुड फ्रीडम एवं जस्टिस पार्टी के नेता मुहम्मद मुर्सी के राष्ट्रपति चुने जाने की जीत की घोषणा के बाद स्थिति धीरे-धीरे सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद (एससीएएफ) के साथ दूसरी समस्या पर स्थानान्तरित हो रही है जिसने अधिकतर विधायी और विदेश मामलों से संबंधित शक्तियों को धारित कर लिया है। सेना ने युद्ध छेड़ने, 100 सदस्यीय संविधान बनाने वाली संस्था नियुक्त करने और विशेष विधायी शक्ति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने का प्रयास करने के अपने अधिकारों को बनाये रखा है।

इजराइल: *अन्य बातों के अधीन* एक मुख्य स्रोत

इजरायल ने अरब जागरण और ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव की पूरी प्रक्रिया में सांत्वना देने के साथ-साथ आशंका की प्रवृत्ति दिखाई है। इसने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है: पहले उसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरानी परमाणु सुविधाओं के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई को एक आवश्यक कदम घोषित किया, जैसा कि उसने 7 जून 1981 को इराकी परमाणु प्रतिष्ठान और 2009 में सीरियाई परमाणु परिसर के साथ किया था लेकिन बाद में शांत हो गया दूसरा, इजरायल की नीति दो क्षेत्रीय दिग्गजों, ईरान और सऊदी अरब के बीच संदेह पैदा करने और टकराव को भड़काने और संबंधित देशों में असंतुष्ट वर्गों में से कुछ को जीतकर अपने स्वयं के विदेशी अंतः क्षेत्र के लिए जगह बनाने की रही है।

अरब संघ के संबंध में, इजराइल महत्वाकांक्षी रहा है। पहले, पूरी घटना के परिणाम के बारे में इसका निराशावादी दृष्टिकोण

था। अब इसने क्षेत्र में बढ़ती सुन्नी-सैलवादी धुरी के बारे में आशंका दिखाना प्रारंभ कर दिया है। इज़राइल का मानना है कि सीरिया में धर्मनिरपेक्ष असद शासन के पतन का इज़राइल पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। यह अब दमिश्क में एक अधिक कट्टरपंथी सुन्नी-इस्लामवादी सरकार द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष शासन के प्रतिस्थापन के बारे में चिंतित है। पानी और गोलन हाइट्स , 1295 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र जिस पर इजरायल ने 1967 के युद्ध में कब्जा कर लिया था जैसे मुद्दे फिर से अपनी गति पकड़ सकते हैं और एक रैली बिंदु बन सकते हैं , फिलिस्तीन कारण के साथ मिलकर और इस खाड़ी क्षेत्र में फिर से सांप्रदायिक विभाजन को धुंधला कर सकता है।

फिर भी , उल्लेखनीय है कि 1980 के दशक में प्रस्तावित यिनन योजना की कल्पना ने फिर से इजरायल के कुछ रणनीतिकारों को मोहित किया। इस योजना के अंतर्गत वे मानते थे कि दोहरी (सूडान और इराक में) सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। सूडान को दो भागों में विभाजित किया गया है ; इराक को तीन भागों में

बांट दिया गया है ; सोमाली तीन भागों (दक्षिणी सोमाली, सोमालीलैंड, पंटलैंड) में बंटने के कगार पर है ; लीबिया योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चल रहा है ; सोमालिया ट्राइफर्सेशन के कगार पर है (दक्षिण में सोमालिया , सोमालिलैंड, पुंटलैंड); सीरिया, यमन, आदि विघटन और अराजकता के रास्ते पर अग्रसर हैं।

यिनन योजना का मूल उद्देश्य सांप्रदायिक और जातीय विभाजन के आधार पर मुस्लिम अरब दुनिया को संतुलित करके इज़राइल के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है और इस क्षेत्र में अपनी खुद के भंडार की नक्काशी करना है और बाल्कन हुए अरब संघ में एक मध्यस्थ की स्थिति का अनुमान लगाना है। यिनन योजना का मानना है कि अंग्रेजों ने क्षेत्रीय वास्तविकताओं को अनदेखा किया और अप्राकृतिक राष्ट्रीय सीमाओं को आकर्षित किया, जिसे वे सही मानते हैं। ये दो प्रमुख परिसरों में काम करता है:

इज़राइल को बने रहने के लिए निश्चितरूप से (1) एक शाही क्षेत्रीय शक्ति बनना , और (2) सभी मौजूदा अरब राज्यों के विघटन से पूरे क्षेत्र के विभाजन को छोटे राज्यों में अवश्य बांटना चाहिए। यहां छोटे राज्यों का निर्धारण प्रत्येक राज्य की जातीय या सांप्रदायिक संरचना पर निर्भर है। नतीजतन, यहूदियों को आशा है कि संप्रदाय-आधारित राज्य इज़रायल के उपग्रह बन जाते हैं, और विडंबना यह है

कि इसका स्रोत नैतिक वैधता है।

इजरायल विश्लेषकों के अनुसार , इजरायल को अरब संघ में जातीय-सांप्रदायिक विभाजन का समर्थन करना चाहिए। यह औसत एवं लंबी दौड़ में इजराइल की सुरक्षा और बचाव के हित में है। अल्पावधि में इजराइल सैन्य आधार पर अपने देश की रक्षा करने में सक्षम है। बड़े पैमाने पर यह देखा गया है कि अरब-बहुत देशों में इसकी नीति गैर-अरबों तथा गैर-मुस्लिमों को समर्थन देने की रही है। एक बड़े फलक पर इजराइल पूरे क्षेत्र में शियाओं और सुन्नियों के बीच की खाई को पाटने का काम कर रहा है। इराक में कुर्दों, सीरिया में ईसाइयों और मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों के बीच इसकी जड़ें जमाने की अपनी योजना है। देश के तौर पर इजराइल कीनिया, दक्षिणी सूडान तथा जिबोती के साथ रिश्ते विकसित कर रहा है और लीबिया में कुछ बड़ी जनजातियों पर जीत हासिल कर रहा है ; पूर्वी यूरोप में इसकी ग्रीस , साइप्रस, रोमानिया और आर्मेनिया में प्रभाव के लक्ष्यों को तराशने की योजना है। गैर-अरब मुस्लिम देशों में इंडोनेशिया और भारत के मुस्लिम इसकी सर्वोच्च

प्राथमिकता हैं।

यिनन योजना मूल रूप से प्रत्येक और हर स्तर पर मुसलमानों के बीच विभाजन करने का लक्ष्य है, हर तरह के मुद्दों - संप्रदाय, जातीय और क्षेत्रीय का लाभ उठाने की कोशिश करना है। वैश्विक स्तर पर यह मुसलमानों को अरब और गैर-अरब (आज़मी / गैर-आज़मी) और गैर-आज़मी के बीच बरेलवी और वहाबियों के बीच, भारत और इंडोनेशिया और शिया सुन्नियों के अलग-अलग हिस्सों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभाजित करने का लक्ष्य रखता है। कुल मिलाकर, अरब दुनिया की मुस्लिम आबादी के केवल 20 प्रतिशत हिस्से का निर्माण करते हैं; शेष दुनिया भर में फैले हुए हैं, अधिकांश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करते हैं।

वस्तुतः, हालांकि, संपन्न पर अनबन जो योनन योजना प्रस्तावित करती है उसका बना रहना कठिन है। आम हितों में बदलाव अनबन का समाधान करते हैं जैसा कि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ है। शिया और सुन्नी के बीच भी येनिन योजना

ध्वस्त हो जाएगी चूंकि इन दो जातियों में दो संभावनाएं उभर कर सामने आती हैं : पहली, व्यावहारिक राजनीतिक भावना दो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच एक भाव को विकसित कर सकती है: सऊदी अरब और ईरान , कैथोलिक और विरोधी उत्तरी आयरलैंड में एक तीस साल के खूनी युद्ध के बाद भी चल रहे हैं। दूसरा , कुल मिलाकर इस्लाम की विचारधारा हमेशा एक मजबूत अंतर्धारा की रही है जो क्षेत्र में अखिल अरबवाद की भावना को मजबूत करती है। इतिहास से पता चला है कि कभी-कभी आवश्यकता से अधिक बालकनिकीकरण अपने प्रायोजकों के लिए खुद ही घातक हो जाता है।

प्रस्तावित जीएसएफ (खाड़ी सुरक्षा मंच) का प्रभाव इजराइल पर भी होगा विशेषकर तब जब वह इसमें और सदस्यों को भी शामिल करना चाहेगा तब। इसके बाद इजरायल को खाड़ी सुरक्षा कार्यक्रम में किसी भी एकतरफा लाभ को भूलना पड़ेगा और वह कुछ नियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी बन जाएगा। यह शायद यूएन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक भरोसा करेगा जिससे

अमेरिका पर इसकी निर्भरता बढ़ जाएगी। नई परिस्थितियों में इजरायल को समायोजित करने के लिए अमेरिका को अक्सर अपने वीटो का उपयोग करना पड़ सकता है। यह फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए इजरायल को राजी करने के लिए अमेरिकी नीति क्षेत्र में एक भावना भी पैदा कर सकता है। अमेरिका वर्तमान में मध्य पूर्व से बाहर निकल रहा है ; यह इस क्षेत्र में शांति चाहता है और इससे पहले कि देर हो जाय यह चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ प्रशांत-पार क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही इस सदी को “अमेरिका की प्रशांत शताब्दी ” घोषित कर चुका है। अमेरिका मुस्लिम देशों , खासकर अरब की खाड़ी में अपनी रणनीतिक पैठ को और अधिक कम नहीं कर सकता। अरब देश अमेरिका के विस्तारित अंग हैं, और इज़राइल को इस वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। वास्तव में , अमेरिका मध्य पूर्व में दो दशकों को खो चुका है और दुनिया के दूसरे पक्ष इसकी महाशक्ति की स्थिति पर सवाल उठाते हुए इसकी चपेट से निकल चुके हैं।

इस भावना को दो घटनाओं द्वारा आगे बढ़ाया गया है: बजट कम करने के लिए सुपर समिति का इनकार करना और राष्ट्रपति ओबामा द्वारा रक्षा बजट में \$ 600 बिलियन से अधिक कटौती की घोषणा करना, क्या अमेरिका इजरायल के साथ दीर्घकालिक रिश्तों के लिए इतना बड़ा घाटा उठा सकता है ? इजरायल के पास दो विकल्प हैं: या तो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम से कम करे और स्वयं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे ; या परिस्थितियों का पालन करें और अपनी येनिन योजना को स्थगित करें।

परिदृश्य V

अरब क्षेत्र में सम्प्रदाय विभाजन कितना वास्तविक और स्थायी है

इस क्षेत्र में शिया और सुन्नी का विभाजन उतना गहरा नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। मूलरूप से यह क्षेत्र राजनीतिक संदेह और विदेशी हस्तक्षेप के एक उच्च दौर से गुजर रहा है। यह, समय-समय पर, संप्रदाय के अंतर्विरोधों को तीव्र कर देता है। यह विदेशी शक्तियों की उपस्थिति और हस्तक्षेप के कारण, राजनीतिक शक के कारण अधिक संभावित है और वह भी मुख्यरूप से सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के बीच है। शासन के साथ-साथ क्षेत्र के अभिजात वर्ग को अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खोने का डर है, विशेष रूप से अरब संघ की जागृति के कारण जहां लोगों की शक्ति शासन के पूर्ववर्ती या राजशाही रूपों को हटा रही है। फिलिस्तीन जैसे कुछ पुराने अनसुलझे मुद्दे, आम अरबों के द्वारा इजराइल को इसकी विस्तारवादी नीति के साथ स्वीकार न

किया जाना, आम अरबों के द्वारा अमेरिका और इसके सहयोगियों के हाथों, जिनमें कुछ क्षेत्रीय देश भी शामिल थे, इसे मजबूती प्रदान करने वाली अरब समाज की मूक शक्तियां हैं। आम लोगों के बीच ईरान, हमास और हिजबुल्लाह की व्यापक स्वीकृति इंगित करती है कि सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग और आम अरबों के हितों के बीच एक बड़ी दरार मौजूद है। राजनीतिक शासन , विशेष रूप से राजशाही, क्षेत्र में शिया प्रभुत्व की प्रेतात्मा को प्रस्तुत करने में अधिक रुचि रखते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम , जो संभावित रूप से शिया-सुन्नी विभाजन को कमजोर करता है वह अरबवाद बनाम संप्रदायवाद की पहचान से संबंधित है। सऊदी अरब को छोड़कर लगभग सभी अरब राज्यों ने फिर से दोहराया है कि वे सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ अरब हैं; उनकी मुस्लिम पहचान केवल उसके बाद आती है। दूसरी ओर , सऊदी अरब अपनी पहचान को पहले मुस्लिम राज्य के रूप में रखता है। इस सैन्य क्षेत्र में, अरबवाद एक मजबूत अंतर्धारा के रूप में क्षेत्र में किसी भी स्थायी विभाजन को रोकता है। इस्लाम खुद

भी एक मजबूत आसंजक वाला अंतर्प्रवाह है।

भू-राजनीतिक रूप से भी , ईरान शिया प्रभुत्व के आधार पर तीव्र विभाजन विकसित करने में बहुत सफल नहीं होगा। नए शासन के तहत मिस्र , तुर्की और लीबिया कभी भी सऊदी अरब के बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। सामरिक और अल्पकालिक लाभों के लिए देश शिया-सुन्नी विद्वानों की रेखा को उत्तेजित कर सकता है , लेकिन लंबे समय के माध्यम में तक इस क्षेत्र में क्षेत्रीय वर्चस्व की समरूपता कम पायी जाएगी और कम समर्थनीय होगी। फिलिस्तीन मुद्दे पर अन्याय सहित, इस्लाम, अरबवाद और विदेशी शक्तियों की उपस्थिति के प्रति विरोध की असली ताकतें जमीनी स्तर पर हमेशा अरबों को एकजुट करेंगी। इस क्षेत्र में प्रजातंत्रीकरण की बढ़ती लहर शायद ही लोकप्रिय इच्छा के खिलाफ जाने के लिए कुलीन और शासकों को अनुमति प्रदान करेगी।

शिया-सुन्नी विभाजन का एक और उदाहरण भारतीय

उपमहाद्वीप में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन के समान ही प्रतीत होता है , जिसका मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने और अपने लोगों के अहंकार और हितों को सुरक्षित करने और संतुष्ट करने के लिए उपयोग किया था। पाकिस्तान गए हुए मुसलमान अभी भी वहां पूरी तरह से समायोजित और आत्मसात होने में असमर्थ हैं। मोहजीर (प्रवासियों) और पाकिस्तान के मूल निवासियों के बीच अनबन अरब क्षेत्र में शिया-सुन्नी के बीच के मौजूदा मतभेद के समान ही स्पष्ट है।

इस प्रकार, न केवल संप्रदायवादी बल्कि लेकिन जातीय विभाजन भी अरब क्षेत्र में असल में एक वास्तविकता के बजाय एक “कुलीन आशंका” की तरह लगता है। इस मोड़ पर जब विशेष रूप से अरब संघ सभी पुराने रक्षकों को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो ये विशिष्ट वर्ग सम्भवतः क्षेत्र में शासन परिवर्तन के लिए संप्रदायवादी और जातीय कार्डों का उपयोग “बांध” के रूप में करना चाहते हैं।

यदि शिया-सुन्नी मतभेद बढ़े तो: क्षेत्र और विश्व के लिए

विवक्षा

हालांकि, यदि शिया-सुन्नी विभाजन इस क्षेत्र में गहराते हैं , तो शुद्ध परिणाम संभवतः एक नया साइक्स-पिकाॅट समझौता होगा: “जातीय और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित ”। इस क्षेत्र में “रचनात्मक अराजकता ” की बहु -परिकल्पना का सिद्धांत इसकी स्वचालित स्वीकृति का पालन करेगा। नई राष्ट्रीय सीमाएँ खींची जाएंगी; बड़े राष्ट्रों का पतन हो जाएगा ; छोटे राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की जाएगी; ईरान और सऊदी अरब स्पष्टतः हारे हुए होंगे: वे आने वाले लंबे समय के लिए अपनी शक्तियों को खो देंगे। इजरायल ने राहत की सांस ली , तीनों बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों- इराक , ईरान और सऊदी अरब को बेअसर कर दिया और निस्संदेह तुर्की को अपनी तरफ से कुछ काजोलिंग और रियायतों से जीत लिया। इसका सीधा असर तेल अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उन्हें मौजूदा समय की तुलना में बहुत सस्ती दरों पर तेल की आपूर्ति करने के लिए मजबूर करेगा। इससे कुलीन वर्ग और आम जनता दोनों के हित प्रभावित होंगे। अनुदान-प्रसार

प्रणाली का विघटन अंततः आम अरबों को इन राजाओं के खिलाफ उठने और आंदोलन करने के लिए मजबूर कर सकता है और उन्हें शक्ति त्यागने के लिए भी मजबूर कर सकता है। हालांकि , उन राजाओं को शक्तियों को छोड़ने के लिए मजबूर करना जो खाड़ी के राज्यों को अपने व्यक्तिगत सम्पदा के रूप में मानते हैं उनके लिए यह एक सरल और आसान मामला नहीं होगा। सऊद हाउस के 100,000 सदस्यों में से अधिकांश अमेरिका में बसना पसंद कर सकते हैं; वे हाल ही में हटाए गए कुछ तानाशाहों की तरह, विशाल बूटियों के साथ पलायन करेंगे जैसा कि ट्यूनीशिया के ज़ैन अल अबेदिन और यमन के अब्दुल्ला अल सालेह ने किया है। इन तानाशाहों के रिश्तेदार दुनिया भर में निवेश करते पाए जाते हैं। अंत में, मध्य पूर्व में शांति और निष्क्रियता का एक लंबा दौर होगा।

खाड़ी क्षेत्र में गहरा हुआ सांप्रदायिक विभाजन अरब देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा ; बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरे वैश्विक मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा। विभाजन पूरे 1.3 बिलियन मुसलमानों

को सांप्रदायिक आधार पर धुवीकृत कर सकता है और तथाकथित इस्लामी एकजुटता और उम्म की अवधारणा में एक और दरार डाल सकता है। एक मायने में , यह विभाजन आम प्रेम-ग्रस्त मुस्लिमों के लिए अच्छा हो सकता है; वे स्वतंत्र रूप से अपने पदों को विकसित करने के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने पारंपरिक अर्थों में अरब राजशाही को देखना बंद कर सकते हैं।

अमेरिका को सस्ता तेल और एक शांतिपूर्ण मध्य पूर्व मिलेगा ; यह इसे अन्य मुद्दों और दुनिया के अन्य हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। अपनी महाशक्ति की स्थिति को बनाए रखने के प्रयासों को मजबूत करना होगा। रूस और चीन अपने व्यवहार को नियंत्रित करेंगे और अमेरिकी सहयोगी जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शांति के साथ रहेंगे।

भारत को अपने गरीबी घटाने के कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिलेगा। और क्योंकि खाड़ी के तेल राजशाही पहले से ही खत्म हो चुके हैं इसलिए पाकिस्तान अपनी साजिश रचने की

प्रवृत्ति को त्याग देगा।

पाकिस्तान भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारेगा, ऐसा कुछ जो कि आवश्यक है तथा अंतर्मुखी मंथन करेगा विशेषरूप से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर। यह भारत के लि मजबूती से अपनी चाल चलने का उचित समय होगा।

ईरान के समक्ष विकल्प: समय निकलता जा रहा है

एक अल्पभाषी शासन ईरान के पास खोने के लिए बहुत से हित हैं। दूसरी ओर एक संचारी और आगामी दृष्टिकोण इस देश की अधिकांश समस्याओं को हल कर सकता है जो पिछले तीस वर्षों से एक पराया राष्ट्र रहा है। ईरान भौगोलिक संरचना से बच नहीं सकता है; इसे वास्तविकता और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा। सऊदी राजकुमार फैसल अलतुकी की घोषणा कि यदि ईरान अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षा में सफल होता है तो सऊदी अरब अपनी स्वयं की परमाणु क्षमता विकसित करेगा, उस प्रभाव को कम कर देगा जो इस क्षेत्र में

ईरान रखना चाहता है और फिर से पारंपरिक सैन्य संतुलन और मौजूदा भू-राजनीति खाड़ी के खेल के परिणाम को तय करेगी। भारत-पाकिस्तान परमाणु संबंध एक संकेत प्रदान करते हैं: दोनों देश अब परमाणु सक्षम हैं , लेकिन कारगिल युद्ध (1999) में पाकिस्तान को उसकी पारंपरिक सैन्य शक्ति के आधार पर आंका गया था; यह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सका।

ईरानी क्रांति के दौरान तथा ईरान-इराक युद्ध के 8 वर्षों में, ईरान को इराक का मुकाबला करने के लिए अकेले छोड़ दिया गया था जबकि इराक ने यहां तक कि अमेरिका का समर्थन तक प्राप्त कर लिया था। इन शक्तियों के समेकित प्रभावों ने अयातुल्ली कमेनी को, जैसा कि वे इसे नाम देते हैं “जाओ जहर का प्याला पी लो” के लिए मजबूर कर दिया था और सार्वजनिक तौर पर 1988 में हार स्वीकार कर ली थी। ईरान क्षेत्र में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं। ईरान-विरोधी शक्तियां ईरान को आर्थिकरूप और राजनीतिकरूप से अलग करने के लिए इसी प्रकार

की धारणा रखने वाले देशों पर आश्रित हो रही है। जिस क्षण वे सफल होंगे, ईरान की सुरक्षा पर संकट बढ़ने लगेगा। और इससे पहले कि सीरिया, लेबनान और कुछ हद तक ईरान दबाव में आ जाएं व साथ ही समृद्ध अरब तेल राजशाही और यू.एस. के दबाव में आये ईरान को अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। ईरान को अपनी स्वयं की क्षेत्रीय सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जो कि इस क्षेत्र से अमेरिका को बाहर करने, इस्लामी शासन को संरक्षित करने, अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं का बचाव करने और क्षेत्र और इस्लामी दुनिया में अपने अल्पमत का विस्तार करने पर आधारित है। ईरान इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विश्वास को खो चुका है जिसे अपने ऐतिहासिक दावों को पीछे छोड़कर तथा क्षेत्र में और इसके बाहर अपनी स्वयं की वैधता को बेहतर बनाने की आवश्यकता के द्वारा सुधारने की आवश्यकता है।

ईरान खुद घरेलू और बाहरी हस्तक्षेपों से मुक्त नहीं है ; यह अपनी अखंडता और एकता के लिए खतरा हो सकता है।

जनसांख्यिकी और जातीय संरचना के संदर्भ में, यह जातीय और

संप्रदाय के आधार पर समान रूप से अतिसंवेदनशील है। हालांकि फारसियों का बहुमत ईरान में 61 प्रतिशत है , लेकिन अन्य सजातियों का भी महत्वपूर्ण हैं , जिनमें 16 प्रतिशत एज़ेरिस, 10 प्रतिशत कुर्द, 6 प्रतिशत लूर और बलूच , अरब तुर्कमेन और तुर्क प्रत्येक 2 प्रतिशत जनजातियों के हैं।

बाह्यरूप से ईरान, अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति के साथ अपनी पूर्वी सीमा पर असुरक्षित है। बलूच समूह, विशेष रूप से जंदुल्लाह समूह और तालिबान इस क्षेत्र में ईरानी और शिया के विरुद्ध हैं। यद्यपि ईरान ने ताजिक और शिया समूहों का तालिबान के विरोध में पारंपरिक रूप से समर्थन किया है , लेकिन अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी और परमाणु कार्यक्रम पर तनाव ने उसे तालिबान को “नपा तुला” समर्थन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। ईरान को संदेह है कि अमेरिका जंदुल्लाह का समर्थन करेगा, जिसने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कई वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी है। अफगानिस्तान में आशूरा (2011)

की पूर्व संध्या पर शिया सभाओं पर हुए हालिया हमले , जो 2001 के बाद पहली बार दर्ज किए गए हैं , संकेत देते हैं कि यहां क्षेत्रीय गतिशीलता बदल रही है और यह ईरान के खिलाफ जा सकता है। कतर और जर्मनी के प्रभावी मध्यस्थता के साथ , तालिबान को कतर में एक कार्यालय खोलने के लिए मनाया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईरान के पड़ोसियों को सक्रिय रूप से पोषित किया जा रहा है। सीरिया में बहुसंख्यक ताकतों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए असद शासन पर अरब संघ का दबाव यह भी दर्शाता है कि ईरान के लिए समय हाथ से निकलता जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर ईरान को प्रभावी और सक्रिय नीतियों की आवश्यकता है ; वरना अपनी प्रादेशिक अखंडता को बचाने और सुरक्षित रखने में बहुत देर हो जाएगी।

हाल के वर्षों में ईरान ने अपना ध्यान चीन की ओर स्थानांतरित कर दिया है। यह एक ग्राह्य नीतिगत कदम है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रतिबंधों और कठोर मुद्रा (डॉलर) की

अनिश्चितताओं के दबाव से बचना चाहता है , और प्रतिबंधों के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए एक वैकल्पिक कक्षा विकसित करना चाहता है। “ईरान के सेंट्रल बैंक के साथ मना करने वाले नए प्रतिबंधों जैसे प्रस्तावित प्रतिबंध , ईरान को चीन की ओर और भी अधिक अग्रेषित करेंगे ... 2001 के बाद से , ईरान को चीनी निर्यात लगभग सोलह-गुना बढ़कर \$ 12.2 बिलियन हो गया है , जबकि ईरान क् पिछले साल [2010] \$ 16.5 बिलियन, मुख्य रूप से कच्चे तेल की राशि का चीन को निर्यात करता है ”। हालांकि, यह संबंध चीन के साथ GCC देशों के साथ अपनी विदेश नीति में सहज महसूस करने के अधीन है। जीसीसी और अरब संघ पश्चिम एशिया में एक शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक आकर्षणकर्ता के रूप में उभरे हैं। शायद ही कोई देश 22 अरब देशों के संघ को नाराज करना चाहेगा।

इसके अलावा , यदि हम पाकिस्तान को चीन-ईरानी वर्ग में शामिल करते हैं , तो दोनों राष्ट्रों की विदेश नीति के अंतर्विरोध

उतने सहज नहीं होंगे जितने कथित तौर पर माने जा रहे हैं। भू-राजनीतिक मैदान पर पाकिस्तान और चीन के अच्छे संबंध हैं ; लेकिन यह देखना होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ ईरान की अंतरंगता के साथ सहज होगा या नहीं।

ईरान को क्षेत्र के 'भू-संसाधनों' की राजनीति से भी पीछे हटना पड़ा है। इस क्षेत्र में कच्चे तेल के भंडार का लगभग दो-तिहाई और दुनिया के प्राकृतिक गैस भंडार का एक तिहाई हिस्सा है , जबकि उत्पादन की उनकी लागत बढ़ रही है , विशेष रूप से पुराने होने के साथ-साथ बड़े और भरपूर तेल क्षेत्रों की गिरावट की वजह से, रूस को छोड़कर दुनिया के अन्य ऊर्जा केंद्र घट रहे हैं। लगभग सभी बड़ी शक्तियों में ऊर्जा संसाधनों की कमी है और आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व पर उनकी निर्भरता बढ़ जाएगी। इसलिए क्षेत्र में बड़ी शक्तियों का प्रभाव कम से कम आने वाले दशक के लिए कम नहीं होगा। ईरान अपनी नीतिगत आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है , विशेष रूप से अपने स्वयं के निर्धारित क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला को विकसित करने के क्षेत्र में जो बहिष्कृत अभिनेताओं

को मुख्य रूप से अमेरिका को छोड़ देता है। परमाणु मुद्दे पर ईरान की आपत्ति का कारण अरब देशों को इज़राइल सहित अपने दुश्मनों के साथ खुले तौर पर सहयोगी बनाना हो सकता है।

विषयगत मुद्दे:

ऊर्जा बाजार पर संभावित प्रभाव

यदि युद्ध होता है तो, ऊर्जा सुरक्षा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत मंदी आ जाएगी। इसके तीन संभावित परिदृश्य इस प्रकार से हो सकते हैं:

- i. तुर्की द्वारा संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले नाटो का हस्तक्षेप इस क्षेत्र को सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक में बदलने की संभावना रखता है। यदि स्थिति बिगड़ती है और संप्रदायों के मध्य संघर्ष होता है तो सऊदी अरब का पूर्वी शिया बहुल क्षेत्र उग्रवाद या गुरिल्ला युद्ध का केंद्र बन सकता है। इसके वैश्विक स्तर पर बुरे नतीजे होंगे क्योंकि पूर्वी क्षेत्र सऊदी अरब के 9 एमबीडी तेल उत्पादन में लगभग 5 प्रति दिन मिलियन बैरल उत्पादन (एमबीबी) का योगदान देता है। ऊर्जा बाजार की एक और कण्डरा का पिछला भाग रास तनुरा है, जिसके पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल-निर्यात

बंदरगाह है और विश्व को 4.5 एमबीडी आपूर्ति करता है। इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए दुनिया के किसी अन्य देश के पास इस प्रकार की अतिरिक्त क्षमता नहीं है। नतीजतन, तेल और गैस की कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होंगी, जिसका पहले से ही विश्व की धीमी अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा। एकमात्र देश जो लाभांश का लाभ उठा सकता है, वह रूस होगा, जो सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है।

- ii. ईरान स्टॉर्म ऑफ होर्मुज पर रोक लगा सकता है। यह वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य पर गंभीर नतीजे ला सकता है , क्योंकि 88 प्रतिशत से अधिक और वैश्विक तेल का लगभग 19 प्रतिशत इस संकीर्ण जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो चौकपाँइंट पर 45 किमी चौड़ा है। हालांकि विश्लेषक ईरानी नौसेना की क्षमता पर संदेह व्यक्त करते हैं कि क्या वह होर्मुज को एक सप्ताह से अधिक समय तक परेशान कर सकती है अथवा नहीं है , ईरान के पास

स्ट्रेट खदान और तीन महीने या उससे भी लंबे समय तक शिपिंग में कटौती करने की सामरिक क्षमता है। 1985 से, ईरान ने दो नौसेनाओं - दि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी (आईआरआईएन) तथा दि वाउंटेड ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स नेवी (आईआरजीसीएन) को बढ़ावा दिया है। पहले इसे लाल सागर, ओमान की खाड़ी और एक नीली-जल नौसेना के रूप में पारंपरिक भूमिका का निर्वहन करने के का कार्य सौंपा गया है ; बाद में विशेष रूप से खाड़ी के मुद्दों विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आईआरजीसीएन के पास अब 20,000 कर्मी हैं, जिनमें लगभग 5000 मरीन शामिल हैं जिनका उपयोग खाड़ी में बड़े जहाजों के बचाव में डूबने वाली छोटी नौकाओं के झुंड के असममित संचालन को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। यह ईरान को लंबे समय तक ऊर्जा धमनी को लंबे समय तक रोकने की छूट देता है जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत हानिकर होगा।

इसके अलावा, अदान की खाड़ी और इसके आस-पास स्थिति विरोधात्मक हो सकती है, इस पर विचार करते हुए कि अरब प्रायद्वीप के यमन स्थित अलकायदा (एक्यूएपी) का पूरी तरह से यहां तक कि अनवर अल-अवलाकी की मृत्यु के बाद भी पोषण नहीं हुआ है। एक्यूएपी ईरान और सीरिया से मदद ले सकता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मज पर दबाव बना सकता है। इस स्थिति में अमेरिका के पास, शायद हवाई और समुद्री दोनों माध्यमों से संयुक्त कमांड द्वारा कठोर कदम उठाने का अवसर होगा।

- iii. अमेरिका के पीछे हटने और ईरान में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के विकसित होने से वहां कुछ आशावादी परिदृश्य बने हैं विशेषरूप से ऊर्जा बाजार के लिए तथा युद्ध-ध्वंस देश के पुनर्निर्माण के संबंध में। ईराकी तेल मंत्री ने तेल की वर्तमान मात्रा 2-2.5 एमबीडी को 2017 तक 12.5 एमबीडी तक बढ़ाने की योजना बनाई है। हालांकि, ईराक के बिगड़े हुए हालात के कारण, विशेषरूप से अमेरिका के पीछे हटने

के बाद से प्रारंभ सिया और सुन्नी समुदायों के बीच सांप्रदायिक झगड़ों के अस्तित्व में आने से अमेरिका और ईरान के रिश्ते और अधिक बिगडने से ऊर्जा बाजार ठंडा पड गया है। संभवतः, 2012 के ऊर्जा बाजार के अनुमानों को दो परिदृश्य बिगाड़ सकते हैं और तेल की कीमतों को 100-120 डॉलर बैरल तक ऊपर रख सकते हैं। पहला तो यह की सांप्रदायिक झगड़ो का उदय संभवतः हाइड्रोकार्बन के साथ ईराक के निवेश वातावरण को भी नुकसान पहुँचाएगा। दूसरा, ईरान द्वारा होर्मुज के जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया जाना और शत्रुतापूर्ण अमेरिकी कार्यों के बदले में अपने स्वयं के तेल की आपूर्ति में कटौती करना तेल बाजार के लिए विनाशकारी हो सकता है। 3.56 एमबीबी ईरानी तेल अर्थात वैश्विक तेल उत्पादन के छँठवे भाग की कटौती के बाद वैश्विक तेल बाजार कैसे स्थिर होगा। हालांकि सैन्य रूप से अमेरिकी नौसेना स्टॉर्म ऑफ होर्मुज में नाकाबंदी का सफाया करने में सक्षम है लेकिन तेल की आपूर्ति को

पूर्ववत् करने में कितना समय लगेगा ? और किस देश में ईरान के तेल के हिस्से को बढ़ाने और आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होगी ? सऊदी अरब एक उतार-चढ़ाव वाले उत्पादक के रूप में काम कर सकता है , लेकिन अगर रूस ईरान के साथ मिल गया और इसने तेल उत्पादन के अपने हिस्से को धीमा कर दिया , तो विश्व संपूर्ण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। विश्व वास्तव में, सीरिया, ईरान और इराक से तेल के कारण इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा जो कि हिजबुल्लाह को रोकने से उग्रवाद में हुई वृद्धि के कारण होगा। ईरान व्हाइट हाउस के डिजाइन के खिलाफ एक गुट बनाने के लिए सभी संभावित साधनों को काम में लगा सकता है।

- iv. यह भी संभव है कि भविष्य में संकट की स्थिति में ईरान और रूस मिलकर काम कर सकते हैं , विशेष रूप से प्राकृतिक गैस के मोर्चे पर और वे गैस कार्टेल की स्थापना पर काम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास दुनिया में

अब तक की सबसे अधिक गैस जमा है।

ईरान को झुकाने में अपने दबदबे की सीमाओं से वाकिफ , अमेरिका इन आयातों पर लगाम लगाने के लिए कुछ समय के लिए भारत सहित ईरान के तेल का भारी मात्रा में आयात करने वाले देशों को मनाने के लिए एक मजबूत अनुनय मिशन पर रहा है जिससे कि वह इस आयात को रोक सके। भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान, अमेरिकी विदेश मंत्री, हिलेरी क्लिंटन ने भारतीय अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के ईरान खतरा निवारण अधिनियम का पालन करने के लिए मनाने की कोशिश की। भारत ईरानी तेल का दूसरा बड़ा, लगभग वार्षिक आधार पर 17.5 मिलियन टन का आयातक रहा है। इस संकटकाल में हालांकि, भारत और ईरान के मध्य गैर-तेल व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिबंधों के कारण , ईरान, आर्थिक अस्थिरता के नाजुक दौर से गुजर रहा है ; इसकी अर्थव्यवस्था उच्च महँगाई दर, बेरोजगारी और मुद्रा के मूल्यहास का सामना कर रही है तथा इसके विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहे हैं। ईरान को इसके व्यापक समाज को बड़े पैमाने पर स्थायित्व प्रदान

करने के लिए खाद्य, दवाइयों और अन्य घरेलू वस्तुओं की आवश्यकता है। भारत और ईरान के बीच वस्तु विनिमय भुगतान की व्यवस्था से ईरानियों को दुर्लभ मुद्रा की कमी से बहुत अधिक राहत मिलेगी। दोनों देशों ने आपसी सहयोग के संकेत का एहसास किया है, जिसके परिणामस्वरूप वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उभरते संकट को हल करने के लिए भी काम कर रहे हैं।

भारत न केवल खाड़ी में बल्कि पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान और कुछ मध्य एशियाई देशों में ईरान के भू-सामरिक महत्व को भी समझता है। नतीजतन, मध्यम से दीर्घकालिक समझ के साथ-साथ दोनों देशों के हितों ने उन्हें आगे नजदीकी बने रहने के लिए प्रेरित किया है।

निष्कर्ष

खाड़ी में स्थिति अस्थिर और जटिल दोनों है। दिसंबर 2011 तक इराक से अमेरिकी सेनाओं की वापसी ने वातावरण को जटिल बना दिया है और पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता और आशंकाएं पैदा

कर दी हैं। संभावित सांप्रदायिक फायदे और परमाणु महत्वाकांक्षा वाले ईरान ने सुन्नी अरब की खाड़ी के राज्यों , विशेष रूप से सऊदी अरब को बेकल कर दिया है। अरब खाड़ी के देश ईरान की बढ़ती भू-रणनीतिक क्षमता को सीमित करने के लिए समर्पित है। इसके लिए वे असद पर सीरिया के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए पूरी तरह से दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। आने वाले कुछ समय में असद साम्राज्य बढ़ते दबाव को महसूस करेगा ; अरब संघ सीरिया को आर्थिकतौर पर पंगु बनाने के लिए और विद्रोही समूहों के लिए “सामाजिक स्थान” बनाने और बहुसंख्यक सुन्नियों को विद्रोह के लिए उकसाने के लिए सभी संभावित प्रतिबंध लगाएगा। फिलहाल, सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई संभावित विकल्प नहीं है, क्योंकि खाड़ी की भू-राजनीतिक स्थिति लीबिया की परिस्थितियों से बहुत अलग है। लीबिया के विपरीत , सीरिया अलग-थलग नहीं है; इराक, लेबनान और यमन ने पहले ही सीरिया को निष्कासित करने के उद्देश्य से अरब संघ के निर्णय के प्रति अपनी असहमति दिखाई है ; इसके अलावा, जॉर्डन और अल्जीरिया

जैसे अन्य देशों ने आम सीरियाई लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधों को सीरिया पर लगाने पर अपनी असहमति जताई है।

सीरिया और ईरान दो शक्तिशाली गैर-राष्ट्रीय असममित संगठनों, हमास और हिजबुल्ला के संरक्षक हैं जिनकी पहुंच पूरी खाड़ी में अफगानिस्तान तक महसूस की जाती है। लीबिया के विपरीत, सीरिया के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई एक सरल और आसान निकास अभियान साबित नहीं हो सकता है। क्षेत्र में इनकी जटिलताओं को देखते हुए कोई भी सीधी कार्रवाई क्षेत्रीय देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी विपत्ति साबित हो सकती है। युद्ध जैसी स्थिति की पूर्व संध्या पर, एक्यूएपी जैसे आतंकवादी संगठन अमेरिका और खाड़ी राजशाही का विरोध करने वाली ताकतों में शामिल हो सकते हैं और तेल और पानी के अलवणीकरण संयंत्रों को लक्षित कर क्षेत्रीय और विश्व दोनों स्तरों पर बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। जल विलवणीकरण संयंत्रों का विनाश नागरिक अराजकता पैदा कर

सकता है क्योंकि अरब खाड़ी में पीने योग्य पानी की 90 प्रतिशत आपूर्ति इन्हीं संयंत्रों से होती है। यह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रदान करने में देशों की दक्षता पर भी सवाल उठाएगा। इसका एक परिणाम विशेष रूप से अरब लहर की कगार पर बैठे असंतुष्ट युवाओं को उकसाना और शासन परिवर्तन के लिए शक्तिशाली आंदोलनों को शुरू करना हो सकता है। इन गैर-राष्ट्रीय कारकों द्वारा तेल प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ “जीवाश्म ईंधन सभ्यता” को एक ठहराव के लिए ला सकता है: दुनिया में कोई अन्य तेल उत्पादक देश सऊदी तेल के हिस्से के नुकसान जो.कि. वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 10 से 12 प्रतिशत है, की भरपाई और पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।

सीरिया, अरब और इस्लामी कारणों के लिए उदार बलिदानों के इतिहास के साथ लगभग 2 मिलियन शरणार्थी - 1.2 मिलियन इराकी और 0.5 मिलियन फिलिस्तीनी लोगों की शरणगाह वाला एक अरब राष्ट्र है। सीरिया पर हमले या गंभीर प्रतिबंधों से क्षेत्र में अखिल अरबवाद भड़क सकता है जैसा कि इराक पर हमले के

समय हुआ था। इराक में बुश प्रशासन की सभी आकलन गलत हो गए थे; शिया आबादी अमेरिका का स्वागत करने के लिए कभी भी बढ़चढ़ कर आगे नहीं आयी; बल्कि उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को कमजोर करने के लिए अमेरिका का शोषण किया और लोकतांत्रिक सेटअप में अपने संभावित महत्व को बढ़ाया।

प्रजातांत्रिक मंच के लिए खाड़ी में दूसरा लक्ष्य बहरीन था। यह ईरान को उसकी स्थिति का आकलन करने में बहुत हद तक मदद कर सकता है जिसे वह खोमेरी युग के दौरान नहीं कर पाया था ; और अमेरिका को बिना किसी स्पष्ट लाभ के इराक से वापस लौटना पड़ा था। ईरान की परीक्षण करने के लिए कटिबद्ध सुन्नी अरब साम्राज्य, संभवतः इजराइल के साथ एक घनिष्ठ साझेदारी के माध्यम से जीएसएफ के गठन पर विचार कर सकता है। यदि शिया-सुन्नी दरारें गहरी होती हैं तो इजराइल क्षेत्र में मध्यस्थ बनकर इसका लाभ उठा सकता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच इस सांप्रदायिक युद्ध में इजराइल या तो सऊदी अरब से अथवा

ईरान से एक मित्रपक्ष जरूर बनाएगा। इस क्षेत्र में तुर्की की भू-रणनीतिक उम्मीदे संभवतः बढ़ेगी ; लेकिन यह अपने स्वयं के रुबिकन अर्थात् अपनी स्वयं की भू-रणनीतिक गणनाओं के साथ-साथ “शून्य पड़ोसी समस्या नीति” के अपने स्वयं के स्पष्ट विदेश नीति सिद्धांत के खिलाफ आगे नहीं जाएगा। पूरे सीरियाई उलझन में तुर्की की भूमिका व्यवहार में इस सिद्धांत की लिटमस परीक्षा होगी। अब तक असद शासन से उबर न पाने वाले सुन्नी अरब देशों सहित सभी सेनाएँ, तुर्की के द्वारा सीरियाई उलझनों को कम करने में दिलचस्पी ले रही हैं। यदि तुर्की कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो इस क्षेत्र की स्थिति एक नागरिक आपदा में परिवर्तित हो जाएगी।

यद्यपि असद शासन की समाप्ति का स्पष्ट उद्देश्य सीरिया में “लोगों के शासन” को स्थापित करना और बढ़ावा देना प्रतीत होता है, लेकिन भू-रणनीतिक समीकरण पूरी तरह से अलग ही कहानी बताता है। अमेरिका-सुन्नी अरब की खाड़ी शक्तियों का मुख्य लक्ष्य संभवतः क्षेत्र में ईरान की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति

को सीमित और कमजोर करना है। ये ताकतें सीरिया को ईरान की परिधि से अलग करना चाहती हैं , जिसके परिणामस्वरूप ईरान को अरब क्षेत्र से अलग कर दिया जाए , जिससे लेबनान और फिलिस्तीन में दो शक्तिशाली गैर-देशीय अभिनेताओं , हमास और हिजबुल्ला को कमजोर किया जा सके। इससे क्षेत्र में रियाद-तेल-अवीव-वाशिंगटन एक्सिस का गठन हो सकता है।

इस अक्षांस के गठन से निम्नलिखित कुछ संभावनाएं उभर सकती हैं:

- i. जहाँ तक रियाद का संबंध है, उस क्षेत्र में वैधता को चुनौती देने और साथ ही शासन के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए कोई स्पष्ट सांकेतिक राजनीतिक शक्ति नहीं होगी , जिसने इस्लामिक क्रांति (1979) के बाद से सऊद परिवार को परेशान किया हो। अयातुल्ला खुमैनी ने शरिया नियमों के तहत राजशाही की वैधता पर सवाल उठाया था। ईरान

के बाद के कमजोर दौर में , रियाद भी खुद को एक क्षेत्रीय शक्ति मान सकता है और खाड़ी तथा विश्वभर के मुस्लिम समाज में निर्विवाद नेतृत्व का आनंद ले सकता है।

हालाँकि, दोनों प्रस्ताव पूरी तरह से रियाद के प्रस्तावित रणनीतिक समीकरणों का अनुपालन नहीं कर सकते हैं। ये दो संभावी परिदृश्य विकसित हो सकते हैं: *पहला*, ईरान का कमजोर होना इन असममित ताकतों को इस क्षेत्र में तबाही मचाने के लिये तैयार कर सकता है जिसका कि हाइड्रोकार्बन उद्योग के विध्वंस होने पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जो यह हाइड्रोकार्बन इन *सभी* अर्थव्यवस्थाओं के लिए रोजी-रोटी है। *दूसरा*, ईरान की भू-रणनीतिक क्षीणन , सऊदी अरब क्षेत्रीय स्वदेशी और पूरक वैचारिक (धार्मिक) रियाद बनने के अपने सपने को इस्लाम की राजनीतिक पद को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता है , और अरबों के उदय को प्रेरित करता है , जो केवल ऐतिहासिक रूप से , पैगंबर

मुहम्मद और खलीफा अवधि के दौरान ही रहा है।
 दूसरी ओर ईरान की भू-रणनीतिक कमी के बाद,
 इसके प्रोत्साहन में सक्रिय रहने, जिहादीकरण को
 प्रोत्साहित करने और जिहादीकरण का वित्तपोषण
 करने और जिहादी-आधारित विदेशी नीति को
 प्रोत्साहित करने की संभावी कीमत चुकानी होगी ;
 और सऊदी अरब में साम्राज्य परिवर्तन अवश्यम्भावी
 हो सकता है। अमेरिका का मिस्र के साथ समानांतर
 रहना , सऊद परिवार को सक्रिय सहायता प्रदान नहीं
 कर सकता है: जिस स्थिति में , हाउस ऑफ सऊद
 को या तो शिष्टाचारपूर्वक या बेइज्जती के साथ
 बाहर निकलना हो सकता है। एक वैकल्पिक
 परिदृश्य में , यूएस-इज़राइल एक्सिस सऊद परिवार
 को बाहर करने और राज्य में लोकतंत्र को बढ़ावा
 देने के लिए काम कर सकता है ; एक प्रतिशोधी
 ईरान गुप्त रूप से गेम प्लान में शामिल हो सकता

है। यूएस-इज़राइल अक्ष दो कारणों से ऐसा कर सकता है: पहला , लोकतांत्रिक और राजनीतिक रूप से उभरते अरब युवाओं के बीच अपने विश्वास को कम करने और उनकी छवि को बढ़ाने के लिए ; और दूसरा , क्षेत्र में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। कुछ संभावित उद्देश्य जो तेल अवीव-वाशिंगटन/पश्चिम के लिए प्रयास कर सकते हैं वे हैं: रणनीतिक रूप से छोटा ईरान , फिलीस्तीनी मुद्दे को अपनी शर्तों पर निपटाना , रूस को पश्चिम एशिया की रणनीतिक कक्षा से सामान्य रूप से बाहर करना और विशेष रूप से खाड़ी में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना या रोकना और अंततः एक्यूएपी और एएलक्यूआईएस (अल-कायदा इन इस्लामिक मगरिब) की क्षमता को पंगु बनाना है। अमेरिका/पश्चिमी धुरी तीन शाखाओं (सुन्नी, शिया और खुर्द इराक) वाले ईरान के संसाधनों का दोहन

करने और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश, ईरान और सऊदी अरब की वैचारिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के हस्तक्षेपों और प्रभावों को कम करते हुए करेगा। इसके पीछे कुछ और मंशाएँ भी हो सकती हैं। आतंकवाद और ईरान तथा सऊदी अरब के कमजोर पड़ने से इराक में शांति और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी और अमेरिका/पश्चिमी कंपनियों को एक दशक के इराक युद्ध (2003-2011) में हुए नुकसान की भरपाई और निवेश करने की अनुमति मिलेगी। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षित समय सीमा पांच से दस वर्ष तक हो सकती है। तब तक तेल अवीव-वाशिंगटन एक्सिस सामरिक कारणों से सऊद हाउस को बनाए रखेगा।

- ii. दूसरे और पूरी तरह से अलग-अलग भू-रणनीतिक चित्र में , इस्लामी गणतंत्र ईरान या तो अमेरिका के साथ मिल सकता है या सामंजस्य स्थापित कर

सकता है और संभवतः पूर्ववर्ती शाह की गोपनीयता और अमेरिका के साथ संबंधों का आनंद ले सकता है। इस मामले में , भू-रणनीतिक रूप से , सुन्नी अरब की खाड़ी देशों को भारी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब संभवतः अपनी राजनयिक चमक खो देगा , क्योंकि ईरान , आतंकवादी समूहों को रोकने और समर्थन करने की अपनी स्थिति पर भरोसा कर सकता है और इस क्षेत्र में और उसके आसपास अमेरिका को आतंकवाद के खतरे का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। ईरान का सहयोग अमेरिका को अफ़गानिस्तान को संभालने और नशे के खतरे को नियंत्रित करने के साथ-साथ मध्य एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार भी उपलब्ध कराएगा। अमेरिका के साथ ईरान का सामंजस्य विभिन्न रणनीतिक समीकरण भी उत्पन्न कर सकता है , विशेष रूप से सऊदी अरब के संबंध

में। धीरे-धीरे , लोकतंत्र इस क्षेत्र में अपना रास्ता बना लेगा और उनका बहुमत अपना भाग्य स्वयं तय करेगा। इस परिस्थिति में , मध्यम से दीर्घकालिक रूप में , सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत की शिया आबादी अपने आप को मुखर कर सकती है और एक अलग “स्वायत्त परिवृत्ति ” की पैरवी कर सकती है , जिस प्रकार इराक में खुर्द सफल हुए हैं। ऐसी स्थिति में , सऊदी अरब खाड़ी से बाहर देख सकता है और ईरान को संतुलित करने के लिए मिस्र और तुर्की को जीएसएफ में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। नतीजतन , सत्ता की सीट या तो मिस्र या कहीं और स्थानांतरित हो सकती है , जैसा कि इतिहास में हुआ करता था। संक्षिप्त अंतर्संबंधों के सिवाय , इस्लाम की राजनीतिक सीट हमेशा गैर-अरब खाड़ी राज्यों के हाथों में रही है। गैर-अरब मुस्लिम देशों की भूमिका

और महत्व , विशेष रूप से इंडोनेशिया और भारत जैसे आबादी वाले देशों में भी वृद्धि होगी , क्योंकि इंडोनेशिया के बाद , 160 मिलियन से भी अधिक आबादी के साथ भारत दुनिया में मुस्लिम आबादी का दूसरा सबसे बड़ा घर है। भारत और सऊदी अरब की वर्तमान बढ़ती द्विपक्षीय बातचीत संभवतः एक कूटनीतिक पाचक साबित होगी और आने वाले वर्षों में एक घनिष्ठ संबंध बनाएगी।

यदि ईरान अमेरिका के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो यह सऊदी अरब को भी कमजोर कर देगा और सुन्नी शासकों व राजघरानों के बीच शिया बोगी की एक आशंका को भी तैयार कर देगा। ऐसा करना अरब खाड़ी देशों को एक खाड़ी संघ की स्थापना करने और यूएई की क्रियाविधि के अनुरूप एक संयुक्त संघ जो 1971 में गठित किया गया था उसी प्रकार एक संघ की स्थापना करने के लिए उकसा और समझा सकते हैं।

iii. जहां तेल अवीव का संबंध है , ईरान को कमजोर करने के लिए अग्रणी सीरिया का पतन परमाणु ईरान के दलदल को हटा देगा और हमास और हिजबुल्लाह की पहुंच के साथ-साथ चुस्ती की भी निगरानी करेगा। यह विशेष रूप से लेबनान और फिलिस्तीन में उनके राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधारों पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालेगा। शिया वर्धमान के उदय का प्रस्ताव भी मात्र कुछ ही समय के लिए होगा। यह क्षेत्र में अपने डोमेन और प्रभाव को बढ़ाने के लिए इजरायल का लाभ उठा सकता है। पहले से ही , इराक के युद्ध (2003) के दौरान इराक से खुर्दों ने इजराइल के लिए महत्वपूर्ण लगाव विकसित किया है क्योंकि उन्हें उस देश से काफी समर्थन मिला था। समय के साथ , इजरायल सामान्य रूप से पश्चिम एशिया और विशेष रूप से खाड़ी में एक शक्तिशाली स्तंभ के रूप में उभरेगा।

iv. वाशिंगटन के संबंध में पूरी खाड़ी नियंत्रण में होगी। यह

इराक में शांति और स्थायित्व लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह अमेरिका तथा पश्चिमी कंपनियों को युद्ध-ग्रसित इराक के संसाधनों और बाजारों का दोहन करने में सक्षम बनाएगा। कमजोर ईरान ईराक में अपने हस्तक्षेप को कम कर देगा और इस प्रकार स्वतः ही शांति उजागर हो जाएगी। सऊदी अरब की भूमिका भी कम हो जाएगी। सऊदी अरब एक सक्रिय भाईचारे की नीति को सराहने के बजाय अधिक आत्ममंथन करेगा। सीरिया में बाधीस्टों का पतन इस क्षेत्र में रूसी प्रभाव को न्यूनतम कर देगा और अमेरिका को एशिया-पैसिफिक नीतियों के साथ सामंजस्य बिठाने और चीन को आसानी से सीमित करने के लिए स्वतंत्र सहारा प्रदान कर देगा।

भारत जैसे देश जिनका कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा दाँव है उनकी भूमिका बहुत छोटी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय निमयों का पालन करना व इनके कार्यान्वयन के लिए सुविधाएं प्रदान करना है और स्थायित्व और शांति को प्रोत्साहित व प्रदान करना है। पश्चिम

एशियाई मुद्दों पर भारत ने हमेशा ही सैद्धांतिकरूप से साथ दिया है। यद्यपि हाल के दिनों में , विशेष रूप से सीरिया के मामले में , भारत ने एक सावधानीपूर्ण रुख अपनाया है , जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने के मामले में अधिक व्यावहारिक और सहमतिपूर्ण लगता है , प्रारंभ में इसे रोक दिया गया था लेकिन बाद में यूएनएससी में असद शासन के खिलाफ अरब लीग-अमेरिकी समर्थित संकल्प के पक्ष में मतदान किया गया। संकल्प के पक्ष में वोट करते समय अनुभव के आधार पर भारत इसके दुरुपयोगों के प्रति भी सचेत था। भारत के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि, हरदीप पुरी ने उल्लिखित किया कि संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की भूमिका “सीरियाई समाज के सभी वर्गों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक शांतिपूर्ण और समावेशी प्रक्रिया ” की सुविधा प्रदान करना है ; किसी भी पार्टी द्वारा की गई हिंसा या “बाहर से सुझाये गए उपाय ” एक आसान और शुरुआती समाधान नहीं हो सकता है ; इन गतिविधियों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय नीति के ढांचे का अनुपालन नहीं किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का लगभग हमेशा ही पालन और सम्मान किया है और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में मानवाधिकारों के उल्लंघन और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया है। इसी नीति का पालन उचित होगा , विशेष रूप से पश्चिम एशिया में अस्थिरता और शासन परिवर्तन के इस दौर में। हालाँकि, पूर्वी संस्कृति के अनुकूल बहु-जातीय लोकतंत्र पर आधारित भारत की राजनीतिक प्रणाली ने कुछ अरब देशों का ध्यान लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर आकर्षित किया है। भारत को अपने अनुभवों को साझा करने में संकोच नहीं करना चाहिए , लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए कि इस तरह की किसी भी विचारधारा को उन्हें अग्रेषित करने का कोई इरादा नहीं है और न ही उसे इस क्षेत्र में इस तरह के “राजनीतिक-वैचारिक मौके” को तराशने में कोई दिलचस्पी है। लोगों को तय करने दें कि उन्हें क्या सूट करता है। भारत को उस चीज का स्वागत करना चाहिए जिसका स्वागत अरब क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जा रहा है।

सामान्य रूप से एक स्थिर और शांतिपूर्ण पश्चिम एशिया और

विशेष रूप से खाड़ी, भारत सहित सभी हितधारकों के लिए
वांछनीय है। यद्यपि वर्तमान उथल-पुथल एक निरंकुश शासन से ,
“लोगों” को सत्ता हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती प्रतीत होती है,
लेकिन इसका अंतर्निहित उद्देश्य मध्यम से दीर्घावधि में हितकर
नहीं हो सकता है। समाज निश्चित रूप से ध्रुवीकरण करेगा ; नई
सरकारें अपने जातीय और सांप्रदायिक भागों के प्रबंधन के लिए
कड़े प्रतिरोध का सामना करेंगी और लोकतंत्र का भविष्य भी जल्द
नहीं सुलझने वाला है। बेदोइन संस्कृति , मजबूत आदिवासीवाद ,
उनकी विशेष संस्कृति और परंपराओं का पालन और तत्कालीन
सत्तावादी शासकों के वामपंथी वफादार समूहों की उदासीनता,
लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विकास के रास्ते पर रुकावटों को रोक
देगी। इसके अलावा , लोकतंत्र के नाम पर “बहुमत के शासन” का
डर और भाईचारे जैसी इस्लामी ताकतों के राजनीतिक
सशक्तीकरण, जो सीरियाई शासन से निपटने के लिए मिशन में
सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं , ये कुछ अन्य लोकतांत्रिक
तरीके हैं जो विशेष रूप से और सामान्य रूप से सीरिया में इस

क्षेत्र में उदारवादी उम्मीदें हैं।

HHH

Endnotes

1. In this author's understanding, there is a difference between Arab Spring and Arab Awakening. Basically, Arab Awakening has happened in the light of how the major exogenous powers in collusion with some Arab elites behaved during the Gulf War (1990) and the Iraq War (2003), which in its last phase became the playground of the clash of civilizations. During this phase the people of the Arab region recognised the real faces and motives of their rulers, who wanted to remain in power at any cost. They also realised that despite their huge wealth they were seen as good for nothing by the advanced nations. This aroused a strong anti-US/ West feeling. The Arab Spring was the expression of the disgruntlement of the common Arabs against

the indisposition of their rulers to address their genuine problems like high unemployment, political suppression, social inequality and appropriation of national wealth leading to crony capitalism, coupled with growing negative perception of the US/West among the Arab youth.

2. A study conducted by the Abu Dhabi-based Arab Monetary Fund, an Arab League agency, estimated that joblessness among Arabs is 13.7 per cent, compared with an international average of 5.7 per cent. The report estimated that if the authorities want to reduce unemployment by half, they will have to create 40 million jobs by 2020; youths account for nearly 50 per cent of jobless Arabs, i.e. 20 million. In some countries, the situation is more pathetic; 2008 data show that in Lebanon

medium jobless rates were 8.2 per cent, Syria 8.4 per cent, Egypt 8.8 per cent, Morocco 9.6 per cent, and Saudi Arabia and Libya 10 per cent each. Djibouti had the highest jobless rate of 59 per cent. The figures for some other countries are: Somalia 25 per cent, Mauritania 22 per cent, Palestine 21.6 per cent, and Iraq and Yemen 15.9 per cent each. (Zakir Hussain, “Second Wave of Saudiisation: Is it an answer to the domestic discontent in Saudi Arabia”, in *India Migration Report 2012*, in press.)

3. Discussions with several experts on the Middle East also reveal that the Kuwaiti occupation could have been a plan between the US, Israel, Saudi Arabia and Qatar to topple the regime and increase the price of oil. Iran and others had

started seeking oil payment in currency other than dollar: this was another reason for the first Gulf War.

4. In its Charter containing 22 provisions, nowhere does the GCC mention the word "political". However, the first GCC summit declared its goal to be protection from foreign interference.

5. Richard Russell, "From the War with Iraq until Today", *The Artesh: Iran's Marginalized Regular Military*, Middle East View Point, Middle East Institute, Washington, 2011.
6. Hamid Ansari, *Travelling through Conflict: Essay on the politics of West Asia*, Pearson Longman, New Delhi, 2008.
7. Anthony H. Cordesmann, *Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: The Military and International Security Dimensions* (vol. 2), Praeger, London, 2003.
8. Alternative views also opine that the invasion of Kuwait was orchestrated by the Kuwaitis themselves and the Saudis, so that the US would get permanent military bases in the Gulf and the US would renew its petrodollar deal with Aramco.

9. PSF is a land force, comprised of infantry, armour, artillery, and combat support elements from GCC participating countries. For detailed discussion, see Glenn P. Kuffel, Jr., *The Gulf Cooperation Council's Peninsular Shield Force*, Naval War College, Newport, RI, 2000, <http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA378521>.
10. For detailed discussion, see J.E. Peterson, Chapter Six, *Defending Arabia*, Croom Helm, London; St. Martin's Press, New York, 1986.
11. Saudi Arabia approached China to acquire \$2 billion worth CSS-2 missiles after the United States refused to sell it Lance missiles and F-15s. In late 1987, Saudi Arabia received the first of the CSS-2 missiles, which are alleged to be nuclear-tipped

(Source: Timothy V. McCarthy, *A Chronology of PRC Missile Trade and Developments*, Monterey Institute of International Studies, USA, 1992).

12. For details, see Richard F. Grimmett, *Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2002-2009*, 10 September 2010, CRS Report for Congress, R41403, www.crs.gov, pp. 57-8.
13. Iran ratified NPT in 1970 and since February 1992, allowed the IAEA to inspect its nuclear facilities.
14. Bernard Kaussler, "The Iranian Army: Task and capabilities", in *The Artesh: Iran's Marginalized Regular Army*, Middle East Institute.
15. For a detailed discussion, see Kenneth Katzman, *Iran: Arms and Technology Acquisitions*, CRS Report for Congress, updated 22 June 1998,

<http://www.parstimes.com/nuclear/iranarms98.pdf>;

also see CRS Report 94-138, *Iran: Conventional Arms Acquisitions*; and CRS Report 98-299, *Russian Missile and Nuclear Reactor Transfers to Iran*.

16. The US/West arms supplied to the GCC countries are suspect on two counts: they were not the latest technology, and the GCC countries lack trained personnel to handle them effectively. Large kickbacks also happened in these arms deals. The Al Yamamah deal between Saudi Arabia and Great Britain is still ailing the Saudi royals in some quarters.
17. Kausler, "The Iranian Army ...", n. 14.
18. In the 2009 election the youth mostly supported the Green Movement of Hossein Mossavi. For details, see Colin Freeman, "Iran Protest Cancelled as Leaked Election Results Show Mahmoud Ahmadinejad came Third", *The Telegraph*, 15 June 2009, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/5540211/Iran->

protest-cancelled-as- leaked-election-results-show-
Mahmoud-Amadinejad-came-third.html; Saeed
Kamali Dehghan, “Iran’s opposition green
movement calls for renewed street protests”, *The
Guardian*, 8 February 2011, [http://www.
guardian.co.uk/world/2011/feb/08/iran-opposition-
green-movement-tehran-protest](http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/08/iran-opposition-green-movement-tehran-protest).

19. Kaussler, “The Iranian Army ...”, n. 14.
20. Ibid.
21. Anthony H. Cordesman, *The Military Balance in the Gulf: The Dynamics of Force Developments*, Center for Strategic and International Studies, Washington, 2005, p. 80.
22. Mark Landler and Steven Lee Myers, “With \$30 Billion Arms Deal, U.S. Bolsters Saudi Ties”, *New York Times*, 29

December 2011, [http://
www.nytimes.com/2011/12/30/world/middleeast/with-
30-billion-arms- deal-united-states-bolsters-ties-to-
Saudi-arabia.html](http://www.nytimes.com/2011/12/30/world/middleeast/with-30-billion-arms-deal-united-states-bolsters-ties-to-Saudi-arabia.html).

23. Caryle Murphy, "Why is Saudi Arabia stockpiling US weapons?",

23 October 2010.

[http://www.globalpost.com/dispatch/Saudi-arabia/
101022/why-Saudi-arabia-stockpiling-us-weapons](http://www.globalpost.com/dispatch/Saudi-arabia/101022/why-Saudi-arabia-stockpiling-us-weapons)

24. Landler and Lee Myers, "With \$30 Billion Arms Deal, U.S. Bolsters Saudi Ties", n. 22.

- 25 Theater High Altitude Area Defense (THAAD) is the only system designed to destroy short- and intermediate-range ballistic missiles both inside and outside the Earth's atmosphere... The United

States, will deliver two THAAD batteries, 96 missiles, two Raytheon Co (RTN.N) AN/TPY-2 radars plus 30 years of spare parts, support and training with contractor logistics support to the UAE. Jim Wolf, “ U.S. in \$3.5 billion arms sale to UAE amid Iran tensions” (source: Jim Wolf, *The Reuters*,

1 January 2012,

<http://in.reuters.com/article/2012/01/01/usa-uae-iran-idINDEE80002R20120101>).

26. Bill Law, "Analysis: Selling Arms to the Gulf", *BBC News Middle East*, 9 January 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16396777>
27. Arthur Bright, "Eyeing Iran, US details \$60 billion arms sale to Saudi Arabia", 21 October 2010, [http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2010/1021/Eyeing-Iran-US-details-60-billion-arms-sale-to- Saudi-Arabia/\(page\)/2](http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2010/1021/Eyeing-Iran-US-details-60-billion-arms-sale-to-Saudi-Arabia/(page)/2)
28. Experts are of the view that since 2007 Iran has trained the IRGC Navy (IRGCN) to manage the Strait of Hormuz and its suburbs, particularly in emergencies. The IRGCN has assumed the

nickname of “Gorilla Navy”, which is trained in swarming techniques. For details, see Gwadat Bahgat, “Iran’s Regular Army: Its History and Capacities” in *The Artesh: Iran’s Marginalized Regular Military*, Middle East Institute, Washington, View Point 2011.

29. Background Note: Saudi Arabia, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3584.htm>.
30. It is believed that Iraq made 49 chemical warfare attacks in 40 border locations. Julian Perry Robinson and Jozef Goldblat, “Chemical Warfare in the Iran-Iraq War 1980-1988”, SIPRI Fact Sheet, May 1984, http://www.iranchamber.com/history/articles/chemical_warfare_iran_iraq_war.php.
31. Tareq Y. Ismael and Jacqueline S. Ismael,

Government and Politics of the Contemporary Middle East, Routledge, London, 2011, p. 142.

32. Iran-Iraq War (1980-1988), <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/iran-iraq.htm>.
33. Kamran Moid, *The Economic Consequences of the Gulf War*, Routledge, London, 1990.
34. Sergeant Ben Wilson, "The Evolution of Iranian Warfighting during the Iran-Iraq War", *Infantry*, July-August 2007.
35. Islamisation is a belief, ideology, philosophy, movement and thought process, which calls for recasting and re-carving an entire socio-religious structure in the light of Islamic injunctions. It also calls for instrumentalisation of Islam and believes that the role of Islam cannot be confined to ritual

practices but must be taken to the whole system as a mode of governance. This definition politicised Islam. Ayatollah Khomeini further amplified the political dimension of Islam by

mooting the concept of *Velayat-e-Faqih*, which is broadly translated as “Philosopher King”. *Velayat-e-Faqih*, rule of the religious jurist, served as the central pillar of Iran’s theocratic system. Under this, the power of the state is concentrated in the hand of a single jurist appointed by the Assembly of Experts. As a supreme leader he has final say on all matters of governance - foreign relations to domestic policy - and control over all branches of authorities, including army, police and judiciary. The concept of *Velayat-e-Faqih*, which gained momentum after the Iranian Revolution, started questioning the authoritarian regimes of the Arab Gulf. The monarchs were terrified by this contagious ideology, which questioned the embodiment of Islam by the monarchs.

36. For a detailed discussion, see *The Iranian Revolution at 30*, Viewpoint Special Edition, The Middle East Institute, Washington, DC, http://www.mei.edu/Portals/0/Publications/Iran_Final.pdf.
37. Iraq historically objected to the formation of Kuwait in 1961 under the Sabah family. The eight-year-long war with Iran financially bankrupted Saddam Hussein. He thought to cover up this loss by capturing two strategic Islands of Bubiya and Warba and the Rumailia oilfield of Kuwait.
38. According to Ismael and Ismael, n. 30, the assault upon Iraqi society has had devastating consequences. The annual death rate prior to the invasion was 5.5 per thousand. This rose to 13.2 by 2003 March and to 19.8 in 2006. The American Civil War estimated around 970,000

casualties, or 3 per cent of the population. Besides, around 2,650,000 Iraqis have been internally displaced due to sectarian violence and rise of criminality.

39. For a detailed discussion, see

<http://www.un.org/depts/oip/index.html>.

40. “Cost of Reconstruction”,

<http://www.globalsecurity.org/military/ops/>

[iraq_reconstruction_costs.htm](http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_reconstruction_costs.htm). For detailed

discussion, see various CRS Reports for Congress:

Curt Tarnoff (12 May 2005), *Iraq: Recent Developments in Reconstruction Assistance*,

<http://fpc.state.gov/>

[documents/organization/48612.pdf](http://fpc.state.gov/documents/organization/48612.pdf); Curt Tarnoff,

Iraq: Reconstruction Assistance, 7 August 2009,

<http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL31833.pdf>.

41. According to JamesA. Paul, “many experts believe that Iraq has additional undiscovered oil reserves, which might raise the total well beyond 250 billion barrels when serious prospecting resumes, putting Iraq closer to Saudi Arabia and far above all other oil producing countries”. *Iraq:*

the Struggle for Oil, Global Policy Forum,
[http://dspace.cigilibrary.](http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/22209/1/Iraq,%20the%20Struggle%20for%20Oil.pdf?1)

<http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/22209/1/Iraq,%20the%20Struggle%20for%20Oil.pdf?1>.

42. For detailed discussion, see

http://www.usip.org/files/resources/iraq_oil_pw64.pdf;

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/

[iraq_key_maps/html/oil_fields.stm](http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/02/iraq_key_maps/html/oil_fields.stm).

43. “US formally ends Iraq war with little fanfare”, *The*

Dawn, 16 December 2011,

[http://www.dawn.com/2011/12/16/us-formally-ends-](http://www.dawn.com/2011/12/16/us-formally-ends-iraq-war-with-little-fanfare.html)

[iraq-war-with-little-fanfare.html](http://www.dawn.com/2011/12/16/us-formally-ends-iraq-war-with-little-fanfare.html).

44. Linda Bilmes, a budget expert from Harvard, and

Nobel laureate Joseph Stiglitz of Columbia

University conclude that the economic cost of the

war could be at least \$3 trillion. In this estimate

\$1 trillion of economic loss due to recession has not been included. Linda J. Bilmes and Joseph E. Stiglitz, "The Iraq War Will Cost Us \$3 Trillion, and Much More", *The Washington Post*, 9 March 2008, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/07/AR2008030702846.html>. Also see Steve Schifferes, "The Iraq war: Counting the cost", *BBC News*, 19 March 2011, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7304300.stm>.

45. Atul Aneja, "US Military Operation in Iraq Ends", *The Hindu*, 16 December 2011.
46. Bilmes and Stiglitz, "The Iraq War Will Cost us \$3 Trillion, and Much More", n. 36.
47. Before invading Kuwait, Saddam Hussein blamed that country for overproduction of oil, which led to decline in oil prices, straining the Iraqi economy.

For details, see Ole Gunnar Austinik, “The War over the Price of Oil: Oil and the Conflict on the Persian Gulf”, *The International Journal of Global Energy*, 5(2), 1993, Inderscience Enterprises, <http://www.kaldor.no/energy/GLOB9205-oil-in-the-pg.pdf>.

48. Iraq is planning to increase its export capacity to 12 million barrels per day in the coming years; this has the consent of OPEC. At present, according to Iraq’s Minister of Oil, the country is producing 2.6 million barrels.
49. For detailed discussion, see Zakir Hussain, “India Woos GCC’s Sovereign Wealth Fund: Policy, Scope and Precautions”, *IDSA Policy Brief*, 26 June 2009, <http://www.idsa.in/system/files/ZakirHussain26062009.pdf>.
50. According to Mohammad Khelvi, the Saudi nuclear

scientist relegated to the US, Saudi Arabia paid \$14 billion indirectly for the Pakistani nuclear projects. Saudi Arabia promoted Pakistan to develop nuclear weapons for its safety and security.

51. Under the Kerry-Lugar Bill, Pakistan received \$1.5 billion aid money annually. “US Senate passes Kerry Lugar Bill to triple aid to Pakistan”, *Times of India*, 25 September 2011, http://articles.timesoindia.indiatimes.com/2009-09-25/us/28101474_1_kerry-lugar-bill-afghanistan-and-pakistan-pakistani-people.
52. Israel will nevertheless remain a major player in the regional geo- strategic dynamics.
53. For a graphic description, see Bill Marsh and Joe Burgess, “Points of Confrontation”, *New York Times, Sunday Review*, 27 August 2011, http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/28/opinion/sunday/20110828_Confrontation.html?ref=sunday.
54. For detailed discussion, see <http://www.iaea.org/newscenter/focus/>

iaeairan/bog112011-65.pdf.

55. Simon Henderson, "Iran's Nuclear Program: 'Credible' Evidence of 'Continuing' Work on a Bomb, *Policy Alert*, 8 November <http://www.washingtoninstitute.org/templateC06.php?CID=1751>.
56. Peter Brookes even believes that by 2015 Iran with its intercontinental ballistic missile (ICBM) capability could reach the USA. Peter Brookes, *Protect America from What?*, The Heritage Foundation, 2012, <http://www.heritage.org/research/reports/2012/05/protect-america-from-what>
57. Bernard Gwertzman, "Assad Regime in Syria Crucial to Iran", 30 August 2011, <http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/08/30/>

syria-and-irans-power-calculus/.

58

<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2011/04/irans-nightmare-losing-syria.html#ixzz1eo2wYSE8>.

59. Emile Hokayam, "Syria and its neighbor", *Survival*, Vol. 52(2), April- May 2012.
60. Mehdi Hasan, "Syria's brave but divided opposition will have to take down Assad on their own", *The Guardian*, 11 December 2011, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/dec/11/syria-opposition-assad-intervention>.
61. Ibid.
62. See for the latest development in Dagestan, Lucy Ash, "Dagestan - the most dangerous place in Europe", 27 November 2011, <http://www.bbc>.

co.uk/news/magazine-15824831

63. Mehdi Hasan, “Syria’s brave but divided opposition ...”, n. 58.
64. Since the Syrian crisis started in March 2011, Turkey has given shelter to

more than 32,000 Syrian refugees. Also, the rebel Syrian National Army has established an attack base on Turkey's border with Syria to target the Syrian forces. After the shooting down of a Turkish warplane by the Syrian army, the situation has rapidly deteriorated. It is possible that the allied forces will use this opportunity to carve a no-fly zone on Turkey's border with Syria as they did in Libya, and launch NATO attacks. But such a strategy may not work out in Syria's context. Russia and Iran, coupled with the network of the two asymmetrical forces, Hamas and Hizbullah, are mostly likely to support the current regime in Syria.

65. Syria Opposition Leader Interview Transcript: "Stop the Killing Machine", <http://online.wsj.com/article/SB100014240529702038>

3310_4577071960384240668.html.

66. Gwertzman, "Assad Regime in Syria Crucial to Iran", n. 56.
67. Syria Opposition Leader Interview Transcript: "Stop the Killing Machine", n. 63.
68. Ibid.
69. "Iran, Syria sign free trade agreement", *Press TV*, 20 August 2010, <http://www.presstv.ir/detail/139463.html>.
70. *Mapping the Global Muslim Population (2009)*, Pew Research Center, USA, http://pewforum.org/uploadedfiles/Orphan_Migrated_Content/Muslimpopulation.pdf; Febe Amanois, *Islam: Sunnis and Shiites*, CRS Report for Congress, 2004.
71. *Mapping the Global Muslim Population: A*

Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population, Pew Research Center, USA.

<http://www.pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf>.

72. This author believes that the creation of GCC Federation as proposed by Saudi Arabia in May 2012 will at most work at the regional level, but it would not be effective in achieving its goal of countering Iran, which is a regional heavyweight in terms of population, conventional military force, sectarian advantages and geostrategic and geopolitical presence in the region and beyond. See Atul Aneja, "GCC cool to Riyadh's Meet- Iran Threat Plan", 15 May 2012, *The Hindu*, <http://www.thehindu.com/>

[news/international/article3422592.ece](https://www.bbc.com/news/international/article3422592.ece)

73. The Arab League was established at a meeting in Cairo in 1945 by Egypt, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Transjordan and Yemen. It is involved in political, economic, cultural and social programmes designed to promote the interests of member states. It has served as

a forum to coordinate policy positions and deliberate on matters of common concern, settling some Arab disputes and limiting conflicts. The League's current membership includes Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria and Tunisia.

74. Mapping the Global Muslim Population, October 2009, Pew Research Center, Washington, <http://www.pewforum.org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation.pdf>
75. Till the writing of this paper, the US has not announced the Iran Threat Reduction Act, December 2011. Under this Act, the Obama administration has imposed severe economic

sanction over the Iranian economic and oil businesses. It had put July 2 2012 as the last deadline to all those countries and companies dealing with Iran. In the month of July the Obama administration has once again imposed fresh sanction over Iranian oil export. The effects of these sanctions are deteriorating the economic conditions in terms of rise in inflation, unemployment, decline in foreign exchange and fall in oil export. However, the Iranian authorities have not shown any weaknesses or sign of compromise on nuclear issue with the US/West.

76. *A Saudi National Security Doctrine for the Next Decade*, 11 July, 2011, <http://www.Sau'dibrit.com/2011/07/11/a-Sau'di-national-security- doctrine-for-the-next-decade/>.

77. Jason Burke, "Saudi Arabia worries about stability, security and Iran", <http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/29/Sau'di-arabia-prince-turki-arab-spring-iran>.
78. Richard Galpin, "Russian Arms Shipments Bolster Syria's Embattled Assad", *The BBC News Middle East*, 30 January 2012. <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16797818>
79. Telephonic interview with Alexey Baev, Senior Correspondent, New Delhi Bureau Chief, Izvestia, on 16 May 2012, at 11.36 a.m.
80. Alex Vatanka, *America's Catch 22 Situation: The Iran Question in Afghanistan*, 13 June 2012, Middle East Institute, Washington, <http://www.mei.edu/content/americas-catch-22-iran-question-afghanistan>

81. All Iraqi oil fields under development are linked to the national pipelines that transfer crude oil from Basra to the Turkish port of Ceyhan. The Mediterranean port has capacity beyond this Iraq target. "Iraq Could Export 2.6 million barrels by 2012", <http://www.zawya.com/story.cfm/>

sidZAWYA20111128061504/lok061500111127/Iraq_ca
n_export_26
million_barrels_in_2012?weeklynewsletter&zawyaemail
marketing.

82. Already, Syria-Turkey relations have deteriorated seriously, particularly after the shooting down of Turkey's F-4 Phantom plane by the Syrian air force. Turkey has called a NATO meeting to consider possible punitive steps against Syria. It has started deploying missile batteries, and columns of military vehicles are moving towards the border. This author believes that Turkey's belligerence is a miscalculation, for some of the following reasons: (i) Turkey will be seen by the people of the region as an agent of the West for plunging the region into a costly devastating war.

(ii) Turkey will be fighting Israel's war. (ii) A war, once begun, will not be easy to wind up. During the four decades of its rule the House of Assad has not only built deep connections with the regional forces but also built up huge arms depots. Turkey shares a long border with Syria, and this borderland is mostly inhabited by disgruntled Kurds. From time to time Syria has been using these Kurd rebels to its own advantage. Thus, Turkey will bleed for the coming few years and this will potentially affect its growing economy. (iii) Waging a war will also be against Turkey's own "zero problem neighbourhood policy". However, several other analysts point out that Russia, which is a major ally of Syria, may like to see US involvement in a possible Turko-Syrian war, which may compel

the US to remain in the region for a few more years, bleeding itself economically and consequently enabling Russia to re-emerge as a global power.

88. "Israel's Secret Iran Attack Plan: Electronic Warfare". 16 November 2011, <http://www.thedailybeast.com/articles/2011/11/16/israel-s-secret-iran-attack-plan-electronic-warfare.html>.

On the Israeli threat to attack the Iranian nuclear facility, US Defense Secretary Leon Panetta opined earlier that such an event could "consume the Middle East in a confrontation and a conflict that we would regret". *U.S., Israel Discuss Triggers for Bombing Iran's Nuclear Infrastructure*, 28 December 2011, _

<http://www.thedailybeast.com/articles/2011/12/28/u-s->

israel-discuss- triggers-for-bombing-iran-s-nuclear-
infrastructure.html.

84. “In Israel, speculation grows about Iran strike”,
The Washington Post, 4 November 2011,
[http://www.washingtonpost.com/world/
middle_east/in-israel-speculation-grows-about-iran-
strike/2011/11/03/gIQAjy9AjM_story.html](http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-israel-speculation-grows-about-iran-strike/2011/11/03/gIQAjy9AjM_story.html); “Iranian
leader warns Israel, U.S. not to attack nuclear
sites”, *The Washington Post*, 11 November 2011,
[http://
www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-
leader-warns-israel-](http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-leader-warns-israel-)

[us/2011/11/10/gIQAno1k8M_story.html](http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/leon-panetta-warns-iran-strike); “Leon Panetta warns against Iran strike”, *The Guardian*, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/11/leon-panetta-warns-iran-strike>.

85. A CRS Report to Congress noted that Assad may instigate a war with Israel to divert the attention of the anti-regime elements. Jeremy M. Sharp and Christopher M. Blanchard, *Unrest in Syria and U.S. Sanctions Against the Asad Regime*, CRS Report for Congress, 9 November 2011, RL 33487, www.crs.gov.
86. Mahdi Darius Nazemroaya, “Sudan and the Yinon Plan: The Balkanization of Sudan”, [Global Research](http://www.globalresearch.com), 16 January 2011.
87. On the basis of the Yinon Plan, Israeli strategists have called for the division of Iraq into a Kurdish

state and two Arab states, one each for Shia and Sunni Muslims. This has been achieved through the soft balkanization of federalism in Iraq, which has allowed the Kurdistan regional government to negotiate with foreign oil corporations on its own. The first step towards establishing this was a war between Iraq and Iran, which is discussed in the Yinon Plan.

88. Ralph Peters, "Blood Borders: How a Better Middle East Would Look", *Armed Forces Journal*, <http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899>.
89. "The Zionist Plan for the Middle East", translated and edited by Israel Shahak; The Israel of Theodore Herzl (1904) and of Rabbi Fischmann (1947),

<http://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20>

[Zionist](#)

[%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.pdf.](#)

90. Among the objectives of the Yinon Plan is to divide Lebanon and Syria into several states on the basis of religious and sectarian identities for Sunni Muslims, Shia Muslims, Christians and

Druze:

[\[wordpress.com/2011/01/18/sudan-and-the-yinon-plan/.\]\(http://wordpress.com/2011/01/18/sudan-and-the-yinon-plan/\)](http://niqnaq.</u></p></div><div data-bbox=)

91. Discussion with Prof. Efrahim Enbar, BESA-IDSA Annual Bilateral Meeting, New Delhi, 7 December 2011.

92. The US has voted against the Palestinian Statehood in UNESCO; it has also announced to veto the resolution in UNSC. [96](http://www.</u></p></div><div data-bbox=)

[hufingtonpost.com/2011/09/08/palestinian-statehood-us- n_954246. html](http://hufingtonpost.com/2011/09/08/palestinian-statehood-us-n_954246.html).

93. Dean Cheng and Bruce Klinger, 2011, The Heritage.
94. Pakistan has considered giving India Most Favored Nation status. Both nations have moved towards increasing their trade relations. Right now, out of 8000 items, only 1946 items are traded between the two countries.

This has generated a trade volume of approximately \$2.46 billion. By the end of 2012, the two countries have agreed to reduce the negative list to a few hundreds; the potential of total bilateral trade is estimated around \$10 billion.

95. Russell, "From the War with Iraq until Today", n. 5.
96. Dennis C. Blair, "Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community for the Senate Select Committee on Intelligence", 2 February 2010.
97. CIA World fact Book, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html>.
98. Alireza Nader and Jaya Laha, *Iran's Balancing Act in Afghanistan*, Rand National Defense Research Institute, Pittsburg, 2011.
99. Ben Farmer, "Fears Afghanistan is on verge

of new sectarian war as 59 people killed in twin bomb attacks”, *The Telegraph*, 6 December 2011,

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8938246/Afghanistan-Kabul-shrine-suicide-attacks-kills-34.html>.

100. Barbara Salvin, “Iran Turns to China, Barter to Survive Sanctions”, *Atlantic Council*, November 2011.

101. Zakir Hussain, “Oil Price Volatility and India’s Energy Security: Policies and Options”, 9 January 2009, http://www.idsa.in/idsastrategiccomments/OilPriceVolatilityandIndiasEnergySecurity_ZHussain_090109.

102. Looking at the profound danger on oil security in

Saudi Arabia and its global implications, this author found that many believe that there should be some international security arrangements in protecting these oil terminals and processing facilities.

103. "Saudi Arabia and Oil: What If?" *The Economist*, <http://www.economist.com/node/2705562>
104. *Economic Effects of Major SLOC Closure*, <http://www.slideshare.net/auerswald/effect-ofclosureofthestrainofhormuz-6748310>
105. George Fredman, *The Straits of Hormuz Incident and US Strategy*, Stratfor Global Intelligence, 14 January 2008, http://www.stratfor.com/weekly/strait_hormuz_incident_and_u_s_strategy
106. W. Jonathan Rue, *Iran's Navy Threatens the Security of the Persian Gulf: Tehran's New Plan to*

Dominate its Region and Beyond, Institute for the
Study of War, 2011,
[http://www.understandingwar.org/otherwork/irans-
navy-threatens-security-persian-gulf](http://www.understandingwar.org/otherwork/irans-
navy-threatens-security-persian-gulf).

107. Joshua C. Himes, *Iran's Maritime Evolution*, Gulf Analysis Paper, Middle East Programme, Center for Strategic and International Studies, Washington, July 2011.
108. <http://www.understandingwar.org/print/1592> (Check it)
109. Clinton paid a three-day state visit to India in May 2012. During her interactions with the media, she said that “the United States is working to secure alternative sources of crude oil for India so it does not have to rely on Iran ...” Though not under pressure, India announced to cut approximately 11 per cent of the Iranian oil import. However, S.M. Krishna, India’s Minister for External Affairs, said, “Iran remains an important source of oil for us although its share in our imports is declining and that is well known. Ultimately it reflects the

decision that refineries make based on financial, commercial and technical considerations.”

“Hillary Clinton’s India visit focuses on Iran”,

Xinhuanet, 5 May 2012,

[http://news.xinhuanet.com/english/video/2012-](http://news.xinhuanet.com/english/video/2012-05/10/c_131579986.htm)

[05/10/c_131579986.htm](http://news.xinhuanet.com/english/video/2012-05/10/c_131579986.htm); US to try in expert to cut

Indian-Iran link, *Indian Express*, 9 May 2012,

[http://www.indianexpress.com/news/us-to-lyin-expert-](http://www.indianexpress.com/news/us-to-lyin-expert-to-cut-indiairan-link/947295/0)

[to-cut-indiairan-link/947295/0.](http://www.indianexpress.com/news/us-to-lyin-expert-to-cut-indiairan-link/947295/0)

110. For detailed discussion see Zakir Hussain, *Iran Crisis and India’s Policy Predicament*, 17 February 2012, <http://www.icwa.in/pdfs/VBIndiaIran.pdf>

111. At the time of writing, the situation on the ground was not very clear. Some of the Sunni Arab Gulf states, such as Saudi Arabia and Qatar, have openly supported financing for the rebel groups to

fight against the Assad regime. The US/West has also endorsed this plan and allocated funds to the “people of Syria” group. This author became aware of this nascent development when he was in Syria in October 2011.

112. The term “fossil fuel civilization” was used Bilahari Kausikan, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Singapore, during his talk on 27 March 2012 at the Indian Council of World Affairs, New Delhi.
113. Damascus was the seat of the Omayyad dynasty. It is also the home of legendary Islamic fighter Sala Din.
114. After the invasion of Iraq in 2003, around 2 million Iraqis have become refugees. Of them, 1.2 million are living in Syria, 450,000 in Jordan, 155,000

in Egypt, Lebanon, Iran and Turkey, and 150,000
in the Gulf states.

<http://www.brookings.edu/~media/Files/rc/>

papers/2007/0611humanrights_alkhalidi/0611humanri

ghts_alkhalidi.pdf.

115. The war, which President Barack Obama officially brought to an end on 31 December 2011, cost the US government around \$3 trillion, left 4487 US service members dead and killed more than 100,000 Iraqis. The Pentagon counts 32,226 US service members wounded, but the toll, including cumulative psychological and physiological damage, may be as high as half a million. Dan Froomkin, ‘Colin Powell’s New Book: War with Iraq Never Debated’, 5 September 2012, http://www.huffingtonpost.com/2012/05/09/colin-powell-book_n_1503592.html

116. Discussions with the Israeli delegation at Annual BESA-IDSA dialogue revealed to this author that the beginning and expansion of the Arab Spring took Israel by surprise. They had concluded “cold

peace” with the authoritarian rulers and monarchs of West Asia, under which the two sides had a tacit agreement not to bring back the situation of 1967 and Israel would help in sustaining these regimes.

117. However, others argue that Ayatollah Khomeini came to power in 1979 in Iran pledged to amend ‘history’s mistake. The assassination of Imam Hussein in the battle of Karbala in Iraq in 680 AD and usurpation of power by Umayyad Caliphs established the dynastic Sunni power in Islamic world. (source: Demographic, Sectarianism and Gulf Security, IISS Security Conference 2006, Chapter 6, Saturday December 6, 2006.)
118. Although 200 million Shia Muslims all over the world derive their ideological inspiration from Iran

and may not abide with the Saudi monarch's dictates, they have to visit the kingdom for Haj, which is a religious obligation for Muslims.

119. After the visit of King Abdullah to India in 2006, the relations between Saudi Arabia and India have grown rapidly: the frequency of high-level visits has multiplied; the existing areas of cooperation have deepened and expanded; and new areas such as defence, counterterrorism and cooperation in security against non-state actors have also come on the table. The Delhi Declaration (2006) and Riyadh Declaration (2011) give expression to the concerns of each other. The volume of trade between the two countries has grown threefold in the last five years, touching

\$25 billion.

120. Israel also provided active support to South Sudan in getting independence and also thereafter.

लेखक के बारे में



डा. जाकिर हुसैन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में एक रिसर्च फैलो है। उनकी रुचि का क्षेत्र पश्चिमी एशिया की राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। उनकी वाचस्पति 1990 के बाद के दशक के बाद की भारतीय-जीसीसी राजनीतिक आर्थिक संबंध रहे हैं। वर्तमान में, उनका फोकस सऊदी अरब पर है। आईसीडब्ल्यूए, को ज्वाइन करने से पहले वह प्रसिद्ध अनुसंधान संगठनों - अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (आईएलओ), राष्ट्रीय मजदूर संस्थान (एनएलआई), रक्षा अध्ययन और विश्लेषणों का संस्थान (आईडीएसए) तथा राष्ट्रीय समुद्र तटीय संगठन (एनएमएफ) से जुड़े हुए थे। डॉ हुसैन के पास पश्चिम एशिया के

आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा, प्रवर्जन और ऊर्जा आयाम में 7 वर्षों से अधिक का अनुभव है।

वे आईडीएसए टास्क फोर्स आंन तिब्बतन रिफ्यूजीस इन इंडिया के सदस्य भी रहे हैं और वे एक पुस्तक *तिब्बत एण्ड इंडियाज सिक्थोरिटी: हिमालयन रीजन, रिफ्यूजीस एण्ड सिनो-इंडियन रिलेशंस* के सह लेखक भी हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लगातार उनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनके विचार आमंत्रित किए हैं।

इस लेख को लिखने का विचार लेखक को सीरिया के शहरों जैसे कि दामास्कस, अलेप्पो, होम्स और लताकिया की अक्टूबर 2011 के दौरान की यात्रा में आया था। दामास्कस विश्वविद्यालयों के छात्रों और पत्रकारों से बातचीत करने के अलावा लेखक को अनेक प्रकार के अधिकारियों एवं सीरियाई लोगों, विदेश मंत्री के साथ, राष्ट्रपति के सलाहकार, सुन्नी मुफ्ती प्रमुख तथा सीरियाई चर्चों के प्रमुख से बातचीत करने का दुर्लभ अवसर मिला। उनसे :

shahabzakir@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

a

अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड़, नई दिल्ली-110001